आरआईएस
वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

विषय सूची

महानिदेशक की रिर्पोट..vii

अध्याय 1. वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना..........1

अध्याय 2. व्यापार, निवेष और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल..........27

अध्याय 3. व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग.... 43

अध्याय 4ए. नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे................. 55

अध्याय 4बी. नई प्रौद्योगिकियां और विकास
के मुद्दे–एफआईटीएम..71

अध्याय 5. समाजिक एकजुटता के परिप्रेक्ष्य में
स्त्री–पुरूष समानता..77

अध्याय 6. प्रकाशन कार्यक्रम..81

अध्याय 7. आंकड़ें एवं सूचना केन्द्र..................................... 95

अध्याय 8. मानव संसाधन.. 99

अध्याय 9. वित्तीय विवरण... 105

संचालन परिषद

अध्यक्ष

डॉ. मोहन कुमार

पदेन सदस्य

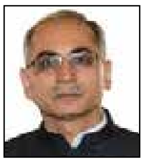

श्री विनय क्वात्रा
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(1 मई, 2022 से)

श्री हर्षवर्धन श्रिन्गला
विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
(30 अप्रैल, 2022 तक)

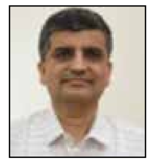

श्री अजय सेठ
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(15 अप्रैल, 2021 से)

श्री तरुण बजाज
सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
(अप्रैल, 2021 तक)

डॉ श्रीवारी चन्द्रशेखर
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(14 दिसंबर 2021 से)

डॉ रेनू स्वरुप
सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दिसंबर 2021 तक)

श्री सुनील बरतवाल
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(1 अक्टूर 2022 से)

श्री बी.वी.आर. सुब्रमनयम
वाणिज्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(30 सितंबर, 2021 तक)

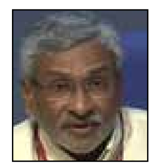

श्री दामु रवि
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय
(जुलाई, 2021 से)

अपदेन सदस्य

श्री शेषाद्री चारी
अध्यक्ष, चाईना स्टडी सेन्टर, माहे, मनीपाल

श्री जयंत दासगुप्ता
डब्ल्यूटीओ में भारत के पूर्व राजदूत

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
पूर्व उप गर्वनर, आरबीआई

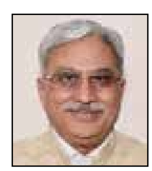

डॉ शैलेश नायक
निदेशक, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज

सदस्य सचिव (पदेन)

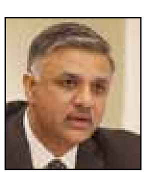

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

अनुसंधान सलाहकार परिषद

अध्यक्ष

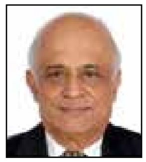

श्री एस. टी. देवरे
पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय

सदस्य

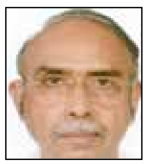

प्रोफेसर एन. एस. सिद्धार्थन
मानद प्राध्यापक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स

प्रोफेसर पुलिन बी. नायक
भूतपूर्व निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

सुश्री सिंधुश्री खुल्लर
भूतपूर्व सीईओ, नीति आयोग

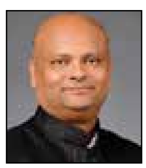

श्री अनुपम रे
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(7 फरवरी, 2021 तक)

डा. सुमित सेठ
सह सचिव (पी पी एण्ड आर)
विदेश मंत्रालय
(8 फरवरी, 2021 से)

विशेष आमंत्रित सदस्य

डॉ नागेश कुमार
प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र एस्कैंप के दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (संयुक्त राष्ट्र एस्कैप–एसएसडब्ल्यूए), नई दिल्ली

सदस्य सचिव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक, आरआईएस

çkQlj lfpu prqosZnh

महानिदेशक की रिपोर्ट

दुनिया भर की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था पर वर्ष 2021–22 के दौरान भी कोविड–19 स्वास्थ्य संकट का गंभीर प्रभाव बरकरार रहा। इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट के कारण क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के तौर–तरीके पर चर्चा करने के लिए आरआईएस ने अपनी दृढ़ प्रतिबद्धताओं के साथ विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाते हुए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना जारी रखा।

आरआईएस की वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के लिए हमने अपने संकाय सदस्यों से आरआईएस के अनुसंधान कार्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। इस संदर्भ में अध्याय–1 में डॉ. भास्कर बालाकृष्णन ने वैश्विक मुद्दों और विकास सहयोग की संरचना से संबंधित हमारे अनुसंधान के आधार के बारे में चर्चा की। यह अध्याय इस व्यापक विषय और संबंधित मामलों पर आरआईएस की ओर से की गई विविध पहलों को रेखांकित करता है। इसमें अन्य के अलावा ट्रिप्स के प्रावधानों छूट पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

विकसित राष्ट्रों की केवल अपने ही बारे में सोचने की प्रवृत्तियों के कारण विकास सहयोग में उभरती चुनौतियों ने एक अन्य संकट प्रस्तुत किया। इससे निपटने के लिए आरआईएस में फोरम फॉर इंडियन डेवलपमेंट कोऑपरेशन (एफआईडीसी) ने पहल करते हुए दक्षिण दक्षिण सहयोग के संदर्भ में कोविड–19 के बाद की विकास चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

आजादी का अमृत महोत्सव के विशेष सप्ताह के अंतर्गत आरआईएस ने भारत के विकास सहयोग पर सप्ताह भर की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया, जो बहुलता, विविधता और सामूहिक प्रगति के प्रति संकल्पबद्धता की गाथा है। इस अवसर पर इस विषय से संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी की गई। एजेंडा 2030 का प्रभावी कार्यान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल किया जाना संस्थान के वर्क प्रोग्राम का अभिन्न अंग बना हुआ है।

भारत की जी–20 की अध्यक्षता की तैयारी के लिए वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत विकास से संबंधित मसलों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आरआईएस ने अनेक बैठकों का आयोजन कर विचार–विमर्श किया। ब्रिक्स फोरम के अध्यक्ष के रूप में भारत को ध्यान में रखकर भी संस्थान ने सिलसिलेवार गतिविधियां आयोजित की।

अध्याय–2 में प्रोफेसर एस.के. मोहंती, डॉ. प्रियदर्शी दाश और डॉ. पंखुड़ी गौड़ द्वारा व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर आरआईएस की पहल के बारे में चर्चा की गई है। यह बहुपक्षवाद, डब्ल्यूटीओ, एमसी–12, मत्स्य सब्सिडी, क्षेत्रवाद से निपटने, वित्तीय तंत्र के क्षेत्र में हमारे प्रयासों से संबंधित है। आरआईएस ने अपने प्रमुख प्रकाशन, वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलेपमेंट रिपोर्ट को भी जारी किया है, जिसमें प्रौद्योगिकी और विकास संबंधों के बीच की पेचीदगियों का महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

अध्याय–3 में प्रबीर डे ने व्यापार में सुगमता, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें आसियान–भारत संबंधों और आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र का अनुसंधान कार्य, बिम्सटेक, इंडो–पेस्कि से जुड़े विषय, भारत–यूरोपीय संघ साझेदारी आदि पर कार्य के जानकारी दी गई है। इसके अलावा अध्याय–4 में डॉ रवि के श्रीनिवास, डॉ अमित कुमार और डॉ स्नेहा सिन्हा द्वारा और अध्याय–4 बी में डॉ नम्रता पाठक द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और विकास के मसलें, फोरम फॉर इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में चर्चा की गई है।

वार्षिक रिपोर्ट में डॉ बीना पांडे द्वारा "सामाजिक एकजुटता के परिप्रेक्ष्य में स्त्री–पुरुष समानता" विषय पर एक अलग अध्याय–5 भी है, जिसमें महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में वांछित सुधार लाने के लिए जी–20 सदस्य देशों से प्रभावी रूप से काम करने का आह्वान किया गया है। रिपोर्ट उन प्रकाशनों का भी विवरण देती है, जिन्हें संस्थान ने अपने नीतिगत अनुसंधान के परिण ामों का प्रसार करने के लिए प्रकाशित किया है। आरआईएस के संकाय सदस्यों ने बाहरी नीतिगत संवादों और प्रकाशनों में भी योगदान दिया है।

हम अपने अध्यक्ष राजदूत डॉ मोहन कुमार, आरआईएस की शासी परिषद और आमसभा के सभी सदस्यों; तथा राजदूत एस.टी. देवारे, अध्यक्ष और आरआईएस अनुसंधान सलाहकार परिषद के अन्य सदस्यों का हमारे अनुसंधान कार्यक्रम का निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए आभार प्रकट करते हैं; हम भारत सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, वाणि ाज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आयुष मंत्रालय और अन्य साझेदार संगठनों से प्राप्त समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

हम इस अवसर पर आरआईएस के सभी संकाय सदस्यों और प्रशासन, आईटी, प्रकाशन और पुस्तकालय प्रकोष्ठ के सहयोगियों को अनुसंधान एजेंडे और आरआईएस के संबंधित कार्यक्रम के निष्पादन में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं।

सचिन चतुर्वेदी

अध्याय 1

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

डा. भास्कर बालाकृष्णन
विज्ञान राजनेय फैलो

कोविड महामारी से निपटना

वर्ष 2021–22 में समूची दुनिया में कोविड–19 महामारी का व्यापक प्रभाव देखा गया। ज्यादा संक्रामकता वाले नए उग्र स्ट्रेन्स के उद्भव ने नैदानिक, वैक्सीन, औषधियों और चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण इनसे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा प्रयासों को परास्त कर दिया। कई देशों ने इस स्थिति से निपटने के लिए आवाजाही पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बाधित हुई। विकासशील देश, विशेष रूप से अफ्रीकी देश इनसे बुरी तरह प्रभावित हुए, जबकि विकसित देश वैक्सीन हासिल करने के लिए कहीं बेहतर स्थिति में थे। महामारी से निपटने के प्रयासों ने वैश्विक सहयोग में बड़े पैमाने पर मौजूद मतभेदों को उजागर कर किया। वैक्सीन, चिकित्सा और निदान तक किफायती पहुंच उच्च प्राथमिकता का मुद्दा बन गया। इस स्थिति में, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड–19 से मुकाबला करने के लिए आवश्यक वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के लिए ट्रिप्स प्रावधानों में अस्थायी छूट के लिए विश्व व्यापार संगठन में एक पहल शुरू की। जहां इस कदम को विकासशील देशों और कई गैर–सरकारी संगठनों का जोरदार समर्थन मिला, वहीं इसे कई विकसित देशों और बड़ी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस चुनौती से निपटने के लिए, आरआईएस ने भारत–दक्षिण अफ्रीकी पहल के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए कोविड –19 हेतु ट्रिप्स छूट के मुद्दे पर वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर सार्वजनिक वेबिनार की एक श्रृंखला शुरू की। इस प्रकार, आरआईएस ने साउथ सेंटर, जिनेवा के सहयोग से 'ट्रिप्स छूटः मुद्दे और चुनौतियां' (5 जून 2021), 'ट्रिप्स छूटः अफ्रीका के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (12 जून 2021), 'ट्रिप्स छूटः लैटिन अमेरिका के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (19 जून 2021) और 'ट्रिप्स छूटः दक्षिण पूर्व एशिया के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (26 जून 2021) विषय पर इन क्षेत्रों के विविध विशेषज्ञों के वेबिनार आयोजित किए।

कोविड –19 महामारी की चरम अवस्था के दौरान, भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद, अमेरिका सहित अनेक जरूरतमंद देशों को उदारतापूर्वक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से वैक्सीन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी। भारत ने तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों द्वारा उपयोग में लाने के लिए अपने विलक्षण को–विन पब्लिक एपीआई (अपाइंटमेंट लेने और वैक्सीन प्रमाणपत्र डाउनलोड के लिए) को निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। कई देशों ने इस तकनीक को अपनाने और उपयोग करने में दिलचस्पी दिखाई।

डिजिटल तकनीक की मदद से कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के संबंध में अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने की भारत की तत्परता ने अन्य देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के देशों की व्यापक दिलचस्पी आकर्षित की। इसे और आगे बढ़ाने के लिए जीडीसी–आरआईएस द्वारा 'कोविड से

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

निपटनाः वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स और रोलआउट में विकासशील देशों का अनुभव' (19 मई 2021) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।

कोविड के पचात आर्थिक बहाली

दुनिया भर में नियंत्रण के उपायों के बढ़ते प्रभाव और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने के परिणामस्वरूप कोविड–19 की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि यह कमी असमान रूप से आई है और नए वैरिएंट्स का खतरा हमेशा बरकरार है। पूरा ध्यान इस समय महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्थाओं की बहाली में मदद करने पर केंद्रित है। इस संबंध में भी आर्थिक प्रभाव की गंभीरता और महामारी की स्थिति के आधार पर, दुनिया भर में विविध साधन और उपाय अपनाए गए हैं। सबसे उपयुक्त साधनों और आर्थिक उपायों को तलाशने का महत्व उभरकर सामने आया है। जी–20 में, एक प्रमुख विकासशील सदस्य देश और जी–20 का वर्ष 2023 का भावी अध्यक्ष होने के नाते भारत ने आर्थिक बहाली पैकेज और व्यवस्थाओं पर विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित शर्तें लागू करने की मांग पर चिंता प्रकट की है। ऐसे समय में जब विकासशील देश कोविड–19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं और हालात से उबरने की जी–जान से कोशिश कर रहे हैं, उस समय ऐसी कड़ी शर्तों के साथ 'हरित सुधार' की वकालत करने को 'हरित उपनिवेश' का एक स्वरूप ही माना जा सकता है। इसी के मद्देनजर आरआईएस ने 9 अप्रैल 2021 को कोविड के पश्चात विश्व में विकास और स्थायित्व के लिए प्राथमिकताएं : जी–20 फ्रेमवर्क कार्यसमूह की भूमिका" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस बात पर जोर दिया गया कि भारत जी–20 का एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जिसने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। इतना ही नहीं, भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऐतिहासिक संचयी मिशन जी–20 के अनेक सदस्य देशों की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में जी–20 में पेरिस समझौते से परे नई प्रतिबद्धताओं पर बल देना पूरी तरह से अनुचित कदम है, जबकि विकासशील देशों के लिए 100 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्त (2020 तक, उच्च वार्षिक लक्ष्य के साथ 2025 तक) की प्रतिबद्धता की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।

विकास संबंधी अभूतपूर्व चुनौतियों और विकास सहयोग में उभरती नकारात्मक प्रवृत्तियों, विशेषकर उत्तर और बहुपक्षीय संगठनों की ओर से सहायता में कमी ने विकास का संकट उत्पन्न कर दिया। कोविड–19 के मद्देनजर विकास सहयोग बढ़ाने और भू–राजनीतिक तनाव के माहौल में विकास वित्त बढ़ाने, त्रिकोणीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत थी। इसके अलावा विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि जैसे ढांचागत विकास के लिए वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता थी। विकसित देशों की आत्मकेंद्रित प्रवृत्तियों के कारण हालात और खराब हो गए। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आरआईएस और उसके भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) ने 'कोविड पश्चात विश्व में विकास सहयोग के लिए नई चुनौतियां' (24 सितंबर, 2021) विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

जलवायु परिवर्तन से निपटना

'द पालग्रेव हैंडबुक ऑफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर अचीविंग द 2030 एजेंडा' के लॉन्च के अवसर पर एनईएसटी, आरआईएस द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन की अतिसंवेदनशीलता और दक्षिण–दक्षिण सहयोग पद्धतियों के संभावित उपयोग और एसआईडीएस के अस्तित्व के खतरों से निपटने के अनुभव का विश्लेषण करने के लिए 1 नवंबर, 2021 को ''एसआईडीएस और जलवायु परिवर्तन के लिए भविष्य की रणनीतियांः दक्षिण–दक्षिण सहयोग पद्धतियों के दृष्टिकोण से गौर करना'' विषय पर आभासी रूप से पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। आरआईएस और विज्ञान भारती (विभा) ने 24 अक्टूबर 2021 को संयुक्त रूप से 'सीओपी 26 से पहले की अवधि और उसके दौरान मुद्दे और चुनौतियां–भारतीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने दुनिया और भारत में हो रहे ऊर्जा संक्रमण तथा नवीकरणीय ऊर्जा और गैर–जीवाश्म बिजली उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में 28 फरवरी 2022

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

को "वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को सक्षम करनाः विश्व में भारत" विषय पर 41वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान ऑनलाइन माध्यम से दिया।

ब्रिक्स की अध्यक्षता

ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत को बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर में इस समूह का संचालन करना पड़ा। ब्रिक्स सिविल फोरम जनता के आदान–प्रदान के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच गहरी साझेदारियां स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है और मौजूदा कठिन चुनौतियों का सामना करने में सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आरआईएस के नेतृत्व में ब्रिक्स सिविल सोसायटी फोरम की इंडियन चैयर का विषय "निरंतरता, समेकन और सहमति के साथ इंट्रा–ब्रिक्स सहयोग" था। इसमें–सतत विकास लक्ष्यों के लिए संशोधित बहुपक्षवाद, तकनीकी और डिजिटल समाधान, आतंकवाद विरोधी सहयोग, और पी2पी सहयोग बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

आरआईएस ने वर्ष के दौरान कई गतिविधियां आयोजित कीं। इस दौरान आयोजित बैठकों में– ब्रिक्स में वेलनेस, स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली पर संवाद (24 मई 2021), ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं और महिलाओं की भागीदारी पर संवादः संस्थागत प्रतिक्रिया (4 जून 2021), आर्थिक विकास और समावेशन की गुणवत्ता पर संवादः क्षेत्रीय विकास परिप्रेक्ष्य (10 जून 2021), शिक्षा और कौशल के भविष्य पर संवादः ब्रिक्स में शिक्षा का नया परिप्रेक्ष्य (21 जून 2021) शामिल थीं। ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 के लिए कर्टन रेजर बैठक 16–17 अप्रैल 2021 को आयोजित की गई।

ब्रिक्स सिविल फोरम के अंतिम कार्यक्रम (28–29 जुलाई 2021) के साथ संपन्न हुई गतिविधियां "ब्रिक्स में समावेशी विकास और उद्यमिता का संवर्धनः प्रौद्योगिकी की भूमिका"; "निरंतरता पर लोगों की भागीदारीः ब्रिक्स अनुभव"; और "ब्रिक्स नागरिक प्रक्रिया को समेकित करना" जैसे विषयों पर केंद्रित थीं। इस बैठक की सिफारिशों में बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों में तेजी लाना, सतत विकास के प्रति समावेशी और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण, वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं (जीपीजी) और एसडीजी के लिए सामूहिक कार्रवाई, 'वन हैल्थ पर ब्रिक्स फ्रेमवर्क', 'वूमन ब्रिक्स' के माध्यम से गठबंधन बनाना', विकास और साझेदारियों का स्थानीयकरण, पात्रता से उद्यमिता/सामाजिक उद्यमिता में बदलाव को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका आदि शामिल हैं। ब्रिक्स सिविल प्रक्रिया को संस्थागत बनाने और ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों से प्रमुख सिविल सोसायटी संगठनों के बीच मजबूत संपर्क को सक्षम बनाने के लिए कार्य समूह बनाने की भी सिफारिश की गई। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न सीमाओं के बावजूद आईसीटी उपकरणों का पूरी तरह उपयोग करते हुए इन सभी गतिविधियों को अंजाम दिया गया।

भारत की जी–20 अध्यक्षता के लिए तैयारी

आरआईएस जी–20 के महत्वपूर्ण संपर्क समूहों में से एक थिंक–20 के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा है। उसने विकासशील देशों के थिंक–टैंक से अधिक प्रतिनिधित्व और उनकी नीतिगत सिफारिशों का संज्ञान लेने के लिए दबाव बनाया। इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा क्रमशः 2022, 2023, 2024 और 2025 में जी–20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य जी–20 और उसके संपर्क समूहों में विकास के एजेंडे पर अधिक ध्यान देना है। आरआईएस ने आभासी रूप से 'विकासशील देशों की आगामी जी–20 अध्यक्षता के लिए टी–20 सुधार' (24 नवंबर 2021) पर एक आभासी विचार–मंथन सत्र आयोजित किया। आरआईएस ने 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जी–20 के संदर्भ में महिलाओं के मुद्दों पर 'जी–20 में महिलाओं के मुद्दे और आगे की राह' विषय पर विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। जी–20 द्वारा वर्ष 2025 तक श्रम बल भागीदारी दर में जेंडर गैप कम करने के निर्धारित लक्ष्य को अभी कई जी–20

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

देशों में हासिल किया जाना बाकी है। आरआईएस ने ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव, जर्मनी के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को जी–20 फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत 'जी–20 में महामारी के बाद की अवसंरचना और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं' विषय पर आभासी सेमिनार का आयोजन किया।

भारत के विकास सहयोग के 75 साल पूरे होने का जश्न

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के विशेष सप्ताह के अंतर्गत, आरआईएस ने '75 साल की विकास साझेदारी–बहुलता, विविधता और सामूहिक प्रगति के प्रति वचनबद्धता की गाथा' पर सप्ताह भर (21–27 फरवरी 2022) की प्रदर्शनी लगाई। आरआईएस ने इस विषय पर एक रिपोर्ट जारी की। माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 21 फरवरी 2022 को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी और रिपोर्ट ने 'विकास सहयोग' और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता के साथ–साथ वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्लोबल साउथ की सहायता बिना किसी शर्त और वेदांत मंत्र 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से करने को रेखांकित किया। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 1947 से 2022 तक भारत द्वारा 127 बिलियन डॉलर के बराबर विकास सहायता प्रदान की गई है; और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) सहित कई पहलों के माध्यम से अन्य विकासशील देशों के 350,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सहायता 31 बिलियन डॉलर के लगभग है और इसका लगभग आधा भाग पड़ोसी देशों को प्रदान किया गया है। कोविड–19 महामारी फैलने के बाद भारत ने 90 से अधिक देशों को वैक्सीन और लगभग 100 देशों को 4 बिलियन डॉलर की सहायता और अनुदान प्रदान किया है। प्रदर्शनी में भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्थानों, प्रमुख सार्वजनिक और निजी इकाइयों, सिविल सोसायटी संगठनों और सामाजिक उद्यमियों को एक साथ लाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न देशों में भारत के विकास सहयोग की पहल को प्रदर्शित किया गया है।

विकास सहयोग को प्रोत्साहन

आरआईएस ने विचारों, नवाचारों और समाधानों को विकासशील देशों और उनके अतिरिक्त देशों से साझा करने का कार्य आगे बढ़ाने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ अपने विशेष प्रकोष्ठ वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जीडीसी–आरआईएस और बीएमजीएफ पोषण, स्वास्थ्य प्रणालियों, महामारी के संबंध में तैयारी, कृषि, डिजिटल वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण और विकास के अन्य प्रमुख मुद्दों जैसे क्षेत्रों में दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए नई साझेदारी बनाने और उसे सुदृढ़ बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे।

आरआईएस–जीडीसी की परियोजना, 'ग्लोबल साउथ के लिए डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं बनाना' को समाधान के भाग के रूप में चुना गया। इस परियोजना ने एशिया और अफ्रीका में उपयुक्त रूप से अपनाए जाने की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में को–विन की अग्रणी उपलब्धियों को रेखांकित किया। आरआईएस–जीडीसी ने कोविड–19 के वैश्विक प्रभाव के मद्देनजर पेरिस पीस फोरम (पीपीएफ) (नवंबर 2021) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भाग लिया। भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी–आरआईएस) ने एजेंडा 2030 की स्थिति और कोविड–19 महामारी से हालात बिगड़ने के कारणों पर प्रकाश डालने के लिए अपनी मासिक संगोष्ठी श्रृंखला के भाग के रूप में 18 अक्टूबर 2021 को 'महामारी और दक्षिण–दक्षिण सहयोग के नए क्षेत्र' विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की। आरआईएस ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए), जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए), जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) के साथ संयुक्त रूप से 24 फरवरी 2022 को इंडो–जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग, 2022 का आयोजन किया।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

एशियाई क्षेत्र के साथ सहयोग

एशियन फाउंडेशन और आरआईएस द्वारा 'एडवांसिंग साउथ–साउथ कोऑपरेशनः इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स विद् पेसेफिक आइलैंड कंट्रीज(पीआईसी)' 2021 के प्रकाशन और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामले एवं व्यापार विभाग (डीएफएटी) द्वारा समर्थन के बाद 31 मार्च 2022 को 'भारत ऑस्ट्रेलिया–प्रशांत द्वीप समूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना' विषय पर परामर्श वेबिनार आयोजित किया गया। चर्चा में भारत–पीआईसी साझेदारी के इतिहास और संभावनाओं का पता लगाया गया और पीआईसी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के हितों के बीच सामंजस्य के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

आरआईएस और त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से 22–24 मार्च 2022 को अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला में "भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोगः संभावनाएं और चुनौतियां" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर शोध अध्ययन साझा करने और सभी पड़ोसी देशों के साथ विकास साझेदारी करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत, बांग्लादेश और नेपाल के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आरआईएस, नई दिल्ली में 14–18 मार्च, 2022 के दौरान आरआईएस और नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एडवोकेसी फाउंडेशन (नेत्रा) द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर दो सप्ताह का अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के 15 शोध विद्वान शामिल हुए। माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने प्रतिभागियों से बातचीत की और क्षेत्र की मौलिकता को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय ज्ञान और पद्धतियों को आधुनिक ज्ञान के साथ एकीकृत करके एसडीजी हासिल करने पर जोर दिया।

आसियान–भारत संबंधों की तीसवीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 18 फरवरी, 2022 को 'हिंद–प्रशांत में उभरती रणनीतिक संरचनाः भारत और आसियान के परिप्रेक्ष्य से' विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में हाल के अकादमिक और नीतिगत विमर्शों और भारत की विदेश नीति के निरुपण तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सतत विकास के लिए हिंद–प्रशांत में हाल की पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। सामान्य रूप से एशिया और प्रशांत क्षेत्र और विशेषकर भारत में लचीला आर्थिक सुधार, वित्तीय चुनौतियों और जलवायु से संबद्ध संप्रभु जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर 29 जुलाई, 2021 को "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड–19 के बाद आर्थिक लचीलेपन का निर्माण" विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।

आरआईएस के वर्क प्रोग्राम

माननीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 30 दिसंबर 2021 को आरआईएस के वर्क प्रोग्राम के बारे में एक इंटरेक्टिव सत्र के लिए आरआईएस का दौरा किया। माननीय मंत्री ने सभी संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की और उपरोक्त क्षेत्रों में विकासशील देशों के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरआईएस के प्रयासों की सराहना की।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोगः संभावनाएं एवं चुनौतियां

आरआईएस और त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने 22–24 मार्च 2022 को अर्थशास्त्र विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला में संयुक्त रूप से 'भारत और पड़ोसी देशों के बीच विकास सहयोग : संभावनाएं एवं चुनौतियां' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस संगोष्ठी में विकास सहयोग और पड़ोसी देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी से संबंधित विभिन्न विषयगत मुद्दों को रेखांकित किया गया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने अपने प्रमुख भाषण में क्षेत्रीय संपर्क और पड़ोसी देशों के साथ व्यापक विकास सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने हाल के दिनों में भारत और पड़ोसी देशों द्वारा की गई प्रगति पर भी प्रकाश डाला। मोहिबुल हसन चौधरी, सांसद, शिक्षा उप मंत्री, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य ने दूसरा प्रमुख भाषण देते हुए कहा, ''बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान त्रिपुरा–भारत का योगदान आज तक उल्लेखनीय है।'' इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में युवा विद्व ानों और पीएचडी के छात्रों ने भाग लिया। ■

कोविड के बाद विकास सहयोग के लिए नई चुनौतियां

भारतीय विकास सहयोग मंच आर आई एस, ने कोविड–19 के बाद विकास के लिए नई चुनौतियां विषय पर चर्चा का 24 सितंबर 2021 को आयोजन किया। इसमें भाग लेने वाले वक्ता थेः महोदय टोनी पीपा, वरिष्ठ सहचर, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास, बरुकिंगस, वाशिंगटन; डॉक्टर एधिया मूलकाला, वरिष्ठ निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग, एशिया फाउंडेशन, कुआलालंपुर; और आचार्य गुलशन सचदेवा, सेंटर फॉर यूरोपीय अध्ययन, स्कूल एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, चर्चा का संचालन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी महानिदेशक अनुसंध ाान सूचना प्रणाली ने किया।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

कोविड का सामना करनाः वैक्सीन प्लेटफॉर्म और इन्हें पेश करने से जुड़े विकासशील देशों के अनुभव

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

राजदूत अमर सिन्हा

डॉ. संदीप भल्ला

डॉ. राम सेवक शर्मा

भारत 'को–विन' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के बारे में अपने अनुभव और विशेषज्ञता को अन्य देशों, विशेषकर अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ साझा करने को तैयार है। यह बात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा ने जीडीसी द्वारा आरआईएस में 19 मई 2021 को 'कोविड का सामना करनाः वैक्सीन प्लेटफॉर्म और इन्हें पेश करने से जुड़े विकासशील देशों के अनुभव' विषय पर आयोजित वेबिनार में कही। गौरतलब है कि डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पोर्टल को विकसित करते समय निजता के संरक्षण एवं साइबर हमलों की रोकथाम को अत्यधिक महत्व दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह जब थर्ड पार्टी एप्लिकेशंस द्वारा उपयोग के लिए को–विन पब्लिक एपीआई (अप्वाइंटमेंट और वैक्सीन प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, तब भी इन बातों को ध्यान में रखा गया था।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि 'एबीसीडी' (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिसिस) का उदय प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच को प्रभावकारी और सुविधाजनक बना रहा है। उन्होंने कहा, 'भारत के प्रयासों से एक तरह से टीकों के समान वितरण के लिए उन्हें साझा करने और इस संरचना के जरिए लोगों तक टीकों की पहुंच, इसमें समानता और समावेश को सुविधाजनक बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं।'

राजदूत अमर सिन्हा, अध्यक्ष, सलाहकार समिति–जीडीसी एवं प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस ने बताया कि चार महत्वपूर्ण अफ्रीकी देशों यथा नाइजीरिया, केन्या, युगांडा और रवांडा के प्रतिनिधियों ने अपने टीकाकरण कार्यक्रमों से संबंधित अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा करने के लिए इस वेबिनार में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जल की हर बूंद बेशकीमती होती है, ठीक उसी तरह से टीकों के संबंध में भी यही बात है कि इसकी हर खुराक/टीका महत्वपूर्ण होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी की पहुंच इस तक हो सके और वे स्वस्थ एवं सुरक्षित रह सकें।

डॉ. संदीप भल्ला, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट–प्रोजेक्ट्स, ईसीएचओ इंडिया ने इस परिचर्चा का संचालन किया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने वाले विशेषज्ञों में ये भी शामिल थेः श्री हसन सिबोमाना, निदेशक, टीकाकरण इकाई, रवांडा बायोमेडिकल सेंटर (आरबीसी); डॉ. अब्दुल्लाही बुलामा गरबा, निदेशक (नियोजन, अनुसंधान एवं सांख्यिकी), राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विकास एजेंसी (एनपीएचसीडीए), नाइजीरिया; और डॉ. रोज जलंग'ओ, रणनीतिक सूचना प्रबंधन एवं संचार अधिकारी, राष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षण कार्यक्रम (एनवीआईपी), केन्या। ■

श्री हसन सिबोमाना (रवांडा)

श्री अविरल गुप्ता

डॉ. रोज जलंग'ओ (केन्या)

डॉ. अब्दुल्लाही बुलामा गरबा (नाइजीरिया)

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

कोविड काल के बाद विकास और स्थिरता को प्राथमिकताः जी20 संरचना कार्य समूह की भूमिका

विकासशील देशों की अगुवाई करने वाले भारत ने 20 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली ब्लॉक के भीतर आम सहमति हुए बिना ही जी20 चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए विकसित देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कड़ी शर्तों के साथ 'हरित रिकवरी' पर विशेष जोर देने वाले ऐसे प्रयासों को एक ऐसा उपाय करार दिया है जो एक ऐसे समय में 'हरित औपनिवेशीकरण' का स्वरूप हासिल करेगा जब विकासशील देश कोविड–19 महामारी के कारण असुरक्षित रहे हैं और वैश्विक स्वास्थ्य संकट के बाद इससे किसी तरह उबरने के लिए प्रयासरत हैं।

कार्यक्रम का स्क्रीनशॉट

डॉ. संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, भारत ने कहा, 'हमने पेरिस समझौता कर रखा है (जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर) और हमें उसका पालन करने की आवश्यकता है। इसे जी20 में शामिल करने का बड़ा खतरा है और वह भी बिना आम सहमति के (जी20 के सदस्य देशों के बीच) ऐसा करना दरअसल पेरिस समझौते को कमजोर करना है। प्रस्तावित व्यवस्था से निर्धारित उद्देश्य को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिलेगी, उल्टे इससे सभी (पेरिस समझौते में) की आपसी सहमति अपनी दिशा से भटक जाएगी और यह एक समानांतर व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने लगेगी। डॉ. संजीव सान्याल 9 अप्रैल 2021 को आरआईएस द्वारा 'कोविड काल के बाद विकास और स्थिरता को प्राथमिकताः जी 20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की भूमिका' विषय पर आयोजित वेबिनार में बोल रहे थे।

डॉ. संजीव सान्याल ने कहा कि इसके अलावा यह भी एक मुद्दा है कि 'कौन यह तय करेगा कि क्या –क्या हरित है।' उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब एक बार रेटिंग एजेंसियों के लिए सख्त आइडिया वाली एक प्रणाली (किसे 'ग्रीन' माना जाना है) स्थापित हो जाएगी और जिसके आधार पर वे यह तय करना शुरू कर देंगी कि कौन क्रेडिट–योग्य है और कौन नहीं, तब जाकर उस सोच प्रक्रिया पर यांत्रिक तरीके से अमल करने के कारण समस्याएं होंगी, जैसा कि कर्जों के पुनर्गठन में देखा गया है। उन्होंने कहा कि रेटिंग प्रक्रिया का चक्रीयता–समर्थक रुख 'संकट में झटके लगने का कारण बनता है और इसे बढ़ा भी देता है।' उन्होंने कहा, ''यदि आप यहां (जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर) भी यही काम करते हैं, और एक सख्त व्यवस्था कर दी जाती है जिसके तहत 'ग्रीन–रेटिंग एजेंसियां' आगे चलकर क्रेडिट–रेटिंग एजेंसियों जैसा बन जाती है, तो इस पूरे सिस्टम में सभी प्रकार के अनपेक्षित नतीजे निकलने का खतरा हो जाएगा। यही नहीं, इस बात की भी प्रबल संभावना रहेगी कि इस तरह की एजेंसियां लगभग निश्चित रूप से विकसित देशों से ही उभर कर सामने आएंगी।'' डॉ. संजीव सान्याल ने कहा कि जब तक दुनिया भर में हरित रेटिंग एजेंसियों का लोकतांत्रिक प्रसार नहीं होगा और सभी देशों की सहमति से एक 'हरित' ढांचा नहीं बन जाएगा, तब तक यह वास्तविक खतरा है कि दुनिया में एक तरह का 'हरित औपनिवेशीकरण' हो सकता है।

इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (आर्थिक संबंध) राजदूत पी. हरीश ने कहा कि भारत एकमात्र जी20 देश है जिसने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। पेरिस फ्रेमवर्क से बाहर जी20 में या किसी अन्य फ्रेमवर्क में एक नई व्यवस्था करने के कदम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पेरिस फ्रेमवर्क के बाहर इस तरह की नई प्रतिबद्धताएं व्यक्त करने की विकास संबंधी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर (यह वर्ष 2020 तक के लिए है और वर्ष 2025 तक के लिए ज्यादा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना होगा) के जलवायु वित्त के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यह भी नहीं बताया गया है कि क्या हर आधिकारिक विकास सहायता को इस आंकड़े में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित प्रतिबद्धताओं के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2050 में चरम पर पहुंच जाता है, तो भी भारत का कुल शुद्ध उत्सर्जन चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में कम ही रहेगा। उन्होंने कहा, 'ऐतिहासिक केस लोड और विकासात्मक स्थिति को नजरअंदाज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी दरअसल जी7 देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी का महज 5 प्रतिशत है, और जी20 देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी का महज एक अंश है। यही नहीं, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत भी कम है।' राजदूत पी. हरीश ने कहा कि अन्य अतिरिक्त शर्तें डाल कर इस तरह के हालात में भारत के विकल्पों को सीमित कर देने से उसे इसकी भारी वित्तीय और विकासात्मक कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने सत्र की अध्यक्षता की, जबकि प्रोफेसर केविन गैलाघेर, वैश्विक विकास नीति के प्रोफेसर, फ्रेडरिक एस. पारडी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज, बोस्टन विश्वविद्यालय; श्री फेडेरिको बोनाग्लिया, उप निदेशक, ओईसीडी विकास केंद्र, पेरिस; और डॉ. प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने भी इस अवसर पर अपने–अपने विचार व्यक्त किए। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

2030 एजेंडा को प्राप्त करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका

'2030 एजेंडा हासिल करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका' के विमोचन के अवसर पर, 26 अक्टूबर, 2021 को नेस्ट, आरआईएस द्वारा एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें पुस्तिका के संपादक प्रोफेसर ली शियाओयुन, सीएयू; डॉ स्टीफ़न क्लिंगबील, डीआईई; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, आरआईएस; जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास के संघीय मंत्रालय के डॉ जर्गन कार्ल ज़ट्लर और रेडबौड विश्वविद्यालय के डॉ हेली स्वेडलंड शामिल थे। परिचर्चा का संचालन श्रीमान आर्टेम इज़मेस्टीव, यूएनओएसएससी, इस्तांबुल द्वारा किया गया था, जिसमें प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, विजिटिंग फेलो, आरआईएस द्वारा समापन टिप्पणी की गई थी।

पुस्तिका के संपादकों ने विकासशील देशों में अभ्यासियों के लिए पुस्तक के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। एजेंडा 2030 को सामूहिक रूप से हासिल करने के लिए विकास सहयोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। चर्चा करने वालों ने आपसी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में प्रतिस्पर्धा के महत्व और विकासशील देशों को एक–दूसरे से सीखने की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया। ■

'2030 एजेंडा हासिल करने के लिए विकास सहयोग की पालग्रेव पुस्तिका' के विमोचन पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस।

जी–20 में महिलाओं के मुद्दे और सफलता की राह

आरआईएस ने 8 मार्च 2022 को महिला दिवस के अवसर पर वर्चुअल मोड में 'जी–20 में महिलाओं के मुद्दे और सफलता की राह' विषय पर एक विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। डॉ नम्रता पाठक, परामर्शदाता, आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया और पैनल चर्चा का संचालन सहायक प्रोफेसर डॉ पंखुड़ी गौड़ ने किया। इस चर्चा में प्रोफेसर पैम राजपूत, डिपार्टमेंट कम सेंटर फॉर वूमेंस स्टडीज एंड़ डेवलपमेंट, पंजाब विश्वविद्यालयय प्रोफेसर लेखा एस चक्रवर्ती, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी)य और डॉ बीना पांडे, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस मुख्य पैनलिस्ट थे।

प्रोफेसर पैम राजपूत ने अपनी प्रस्तुति में जी–20 में महिलाओं के मुद्दों के बारे में जानकारी दी और इस बात पर प्रकाश डाला कि डब्ल्यू–20 ने सभी देशों से अनुरोध किया है कि वे 2025 तक श्रम बल भागीदारी दर में जैंडर गेप को कम करने के लिए जी–20 द्वारा निर्धारित '25 बाय 25' के लक्ष्य की दिशा में नीतियों को आगे बढ़ाएं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह उन प्रतिबद्ध ताओं में से एक है, जिसे अभी तक अनेक जी–20 देशों में हासिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने श्रम, वित्त, जेंडर बजटिंग और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जोर देते हुए जी–20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों की प्रतिबद्धताओं पर बल दिया। इनके अलावा, जी–20 देशों की सरकारों को महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए सार्वजनिक, निजी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की निकट साझेदारी में प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए।

पैनल चर्चा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र भी हुआ। डॉ पंखुड़ी गौड़ ने सभी पैनलिस्टों और प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

ब्रिक्स सिविल संगोष्ठी 2021

आर आई एस ने 28–29 जुलाई 2021 को ब्रिक्स सिविल फोरम का आयोजन किया। उदघाटन कार्यक्रम में माननीय विदेश राज्यमंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स नागरिक संगोष्ठी मंच गहरी साझेदारी स्थापित करने मे सहायक है, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ब्रिक्स देशों के बीच लोगों से लोगों के आदान प्रदान में नागरिक समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व किया है और स्थानीय जरूरतों पर भी आवश्यक कार्यवाही की है।

ब्रिक्स देशों से गणमान्य प्रतिभागी डॉक्टर पावलो, पूर्व निर्देशक ब्रिक्स नीति केंद्र, सुश्री झू जिगफैग, अनुसंधान सहचर चीन गैर सरकारी संगठन अंतरराष्ट्रीय प्रसार विनिमय केंद्र चीन, महोदय रेआन वैन डेर मेरवे, उप निर्देशक अंतरराष्ट्रीय संबंध, धारक संबंध, एवं दक्षिण अफ्रीकी ब्रिक्स युवा संघ, और सुश्री वैलेरिया गोरबाचेवा, जी आर निदेशक, राष्ट्रीय ब्रिक्स अनुसंधान समिति, रूस ने संगोष्ठी में भाग लिया। पूर्व पूर्ण सत्र और एक गोलमेज बैठक चर्चा में भाग लिया गया। जिसमें विषय शामिल थे: ब्रिक्स में समावेशी विकास और उधामिता को बढ़ावा देना, प्रौदयोगिकी की भूमिका;

लोगों की संधारणींयता में भागीदारी; ब्रिक्स अनुभव; तथा ब्रिक्स नागरिक प्रक्रिया को मजबूत करना। समावेशी विकास मार्ग को बढ़ावा देने में एवं ब्रिक्स में उधामिता प्रौद्योगिकी की भूमिका सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर भास्कर बालकृष्णन, कूटनीतिज्ञ अनुसंधान सहचर, आर आई एस ने की जिसमें मूल सिद्धांत संबोधन डॉ एस के वारशने, सलाहकार और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रभात मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने किया। अन्य प्रतिभागी जो सत्र में शामिल थे: डॉक्टर मोरो ऑडि नागोरिया, ब्राजील; महोदय इगोर लावरोवसकी, डॉक्टर सव्यसाची साहा सह–आचार्य, आर आई एस; और महोदय एलेक्सी वाग, चीन।

दूसरे पूर्ण सत्र, लोगों की भागीदारी ब्रिक्स दीर्घकालिक अनुभव, की अध्यक्षता श्री श्यामा परांडे, सचिव सेवा अंतरराष्ट्रीय और महासचिव, अंतर राष्ट्रीय सहयोग परिषद भारत ने की। मुख्य संबोधन श्री आर. एस. रशिम, विशिष्ट सहचर, और कार्यक्रम निर्देशक पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और संसाधन संस्थान भारत, अन्य प्रतिष्ठित प्रतिभागी थे: डॉक्टर एना टोनी, ब्राजील; श्री व्लादीमीर चुपरो, रूस; आचार्य पाम राजपूत, भारत; श्री दकियान झांग, चीन; और श्री यारेड तसगे, दक्षिण अफ्रीका।

प्रक्रिया को मजबूत करने के विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा की आचार्य सचिन चतुर्वेदी, महा निदेशक, आर आई एस ने अध्यक्षता की। राजदूत पी. हरीश,भारत के शेरपा, ब्रिक्स और अतिरिक्त सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष टिप्पणी की। सत्र में शामिल ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि थे: डॉक्टर आंद्रे डी मेलो डिसूजा, ब्राजील; आचार्य व्लादीमीर डेविडोव, रूस; डॉ राजेश टंडन, अध्यक्ष, एशिया सहभागी अनुसंधान और अध्यक्ष, भारतीय विकास सहयोग मंच, भारत; सुश्री जहूँ जिगफैग, चीन; महोदय रेऑन वैन डेर मेरवे, दक्षिण अफ्रीका; और डॉक्टर विक्टोरिया पनोवा, रूस।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

BRICS
INDIA 2021

ब्रिक्स सिविल फोरम 2021

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

राजदूत संजय भट्टाचार्य

राजदूत मोहन कुमार

भारत की वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आरआईएस को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बार फिर ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 की मेजबानी करने का काम सौंपा गया है (आरआईएस ने वर्ष 2016 में भी ब्रिक्स सिविल फोरम की मेजबानी की थी)। ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 से जुड़ी प्रक्रिया 16–17 अप्रैल, 2021 को पूर्वावलोकन के साथ शुरू हुई। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद आरआईएस के चेयरमैन डॉ. मोहन कुमार ने संबोधित किया। डॉ. विक्टोरिया पनोवा, प्रबंध निदेशक, ब्रिक्स अनुसंधान पर रूसी राष्ट्रीय समिति एवं उपाध्यक्ष (अंतरराष्ट्रीय संबंध), सुदूर पूर्व संघीय विश्वविद्यालय, रूस ने पिछले साल आयोजित ब्रिक्स सिविल फोरम की बैठक पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जो रूस में आयोजित की गई थी। राजदूत पावेल कनयाजेव, रूस के ब्रिक्स सूस–शेरपा और राजदूत बेन जौबर्ट, दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स सूस–शेरपा ने विशेष भाषण दिए; इस दौरान उन्होंने इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चयनित थीम 'निरंतरता, जुड़ाव और आम सहमति' की सराहना की और इसके साथ ही ब्रिक्स सिविल फोरम को सफल बनाने में अपना पूरा समर्थन दिया।

भारत के ब्रिक्स शेरपा राजदूत संजय भट्टाचार्य ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने सिविल सोसायटी के विशेष महत्व को यह कहते हुए सराहा कि यह हमारे लोगों के सामूहिक विवेक को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि यह सिविल फोरम दरअसल ब्रिक्स के लिए एक 'विचार बैंक' के रूप में भी कार्य करता है और इसके साथ ही संबंधित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर आवश्यक जानकारियां प्रदान करता है। राजदूत संजय भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि अपनी स्थापना के बाद से ही इस फोरम ने ब्रिक्स को ठोस नीतिगत निष्कर्षों पर पहुंचने में काफी मदद की है। उन्होंने विगत वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की।

उद्घाटन समारोह के बाद मई और जून महीनों में ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत आरआईएस द्वारा विभिन्न विषयगत संवाद आयोजित किए गए। ब्रिक्स के सभी पांचों सदस्य देशों के मुख्य सीएसओ के प्रमुख विद्वानों/विशेषज्ञों/प्रोफेशनलों, थिंक– टैंकों एवं शिक्षाविदों ने इन संवादों में भाग लिया और इस विषय पर अपने–अपने बहुमूल्य विजन साझा किए।

उपर्युक्त विषयगत संवादों के निष्कर्षों को आधार बनाकर आरआईएस 28–29 जुलाई 2021 को ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 की बैठक (वर्चुअल प्रारूप में) की मेजबानी करने जा रहा है, ताकि इन निष्कर्षों पर चर्चा की जा सके और भारत की अगुवाई में ब्रिक्स सिविल फोरम को संस्थान का रूप देने पर एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जा सके।

श्री पी. हरीश

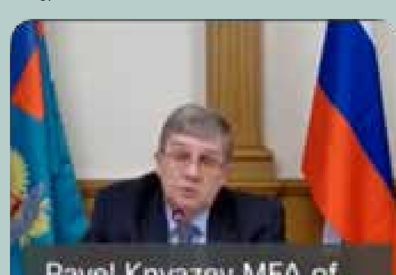

राजदूत पावेल कनयाजेव

श्री के. वी. कामथ

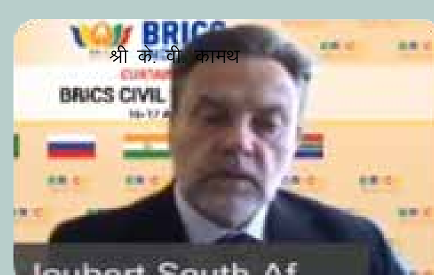

राजदूत बेन जौबर्ट

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

राजदूत लक्ष्मी पुरी

डॉ. नागेष कुमार

डॉ. मनोज नेसारी

डॉ. राजेष टंडन

डॉ. राजीव कुमार

डॉ. राजेष कोटेचा

डॉ. अरबिंद मित्रा

भारत की वर्तमान ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान आरआईएस और ओआरएफ को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बार फिर ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 की मेजबानी करने का काम सौंपा गया है (आरआईएस और ओआरएफ ने वर्ष 2016 में भी ब्रिक्स अकादमिक फोरम की मेजबानी की थी)। ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 के तहत अब तक अनगिनत संवाद आयोजित किए जा चुके हैं। आरआईएस ने अब तक निम्नलिखित विशयों पर कुछ संवाद आयोजित करने का बीड़ा उठाया है:

- पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग (12 मई 2021)
- एसडीजी और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना (20–21 मई 2021)

डॉ. राजेश कोटेचा, सचिव, आयुश मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 मई 2021 को 'पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग' विषय पर आयोजित संवाद के दौरान उद्घाटन भाषण दिया। डॉ. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार ने 20 मई 2021 को 'एसडीजी और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना' विषय पर आयोजित संवाद के दौरान उद्घाटन भाषण दिया। ब्रिक्स के सभी पांचों सदस्य देश के प्रमुख शिक्षाविदों एवं थिंक टैंकों के प्रख्यात वक्ताओं ने इनमें भाग लिया और अपने बहुमूल्य विजन साझा किए।

ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत जुलाई एवं अगस्त 2021 में कई और संवाद आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

श्री के. वी. कामथ

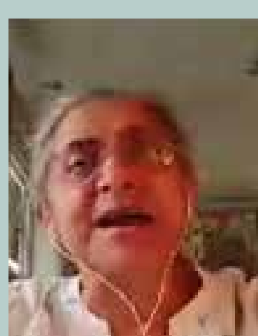

डॉ. रुक्मणी बनर्जी

डॉ. समीर सरन

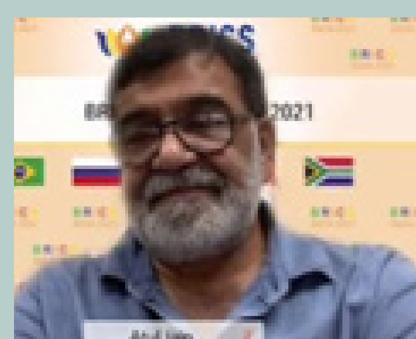

श्री अतुल जैन

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

ब्रिक्स सिविल फोरम विषयगत संवाद	तिथियां
ब्रिक्स सिविल फोरम पूर्वावलोकन संवाद निम्नलिखित विषयों पर: • बेहतर बहुपक्षवाद • विकास वित्त और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं • महामारी से निपटना, साझेदारी और सिविल सोसायटी की भूमिका	16–17 अप्रैल
'ब्रिक्स में आरोग्य, स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां' पर संवाद	24 मई
'ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाएं और महिलाओं की भागीदारी: संस्थागत उपाय' पर संवाद	4 जून
'आर्थिक विकास और समावेश की गुणवत्ता: एक क्षेत्रीय विकास परिप्रेक्ष्य' पर संवाद	10 जून
'शिक्षा और कौशल का भविष्य: ब्रिक्स में शिक्षण का नया प्रतिमान' पर संवाद	21 जून

ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021

भारत वर्ष 2021 के ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता के नाते, आरआईएस और ओआरएफ ने संयुक्त रूप से 3 से 6 अगस्त 2021 को ब्रिक्स अकादमिक फोरम का आयोजन किया। ब्रिक्स अकादमिक फोरम में शिक्षाविद विशेषज्ञ एवं शोधकर्ताओं और विश्लेशकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाल नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की और दुनिया में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया ।

फोरम का आरंभ डॉक्टर समीर शरण, अबसरवर अनुसंधान संस्थान के शुरुवाती वक्तव्य से हुआ। डॉ एस जयशंकर, माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री, ने उदघाटन भाषण दिया। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महा निदेशक आरआईएस ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और अंत में धन्यवाद प्रस्ताव व्यक्त किया।

दूसरे दिन का कार्यक्रम कॉप26 के लिए मार्ग प्रशस्त रूपरेखा पर विचार से शुरु हुआ। सुनियोजित योजना के तहत ब्रिक्स के जलवायु एजेंडा पेरिस समझौता पर हुई प्रगति को केंद्रित रखते हुए इसका जायजा लिया कि कैसे विकसित और विकासशील राष्ट्र अपने वादों में आगे बढ़ सकते हैं। सत्र में इस पर भी चर्चा हुई कि कैसे जलवायु वार्ता पर प्रस्तावित लक्ष्य भागीदारी प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करें कि कैसे इसे विकासात्मक लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है।

तीसरे दिन चर्चा का विषय था कि कैसे व्यापार और आपूर्ति के लिए कार्य सूची का प्रतिपादित करना एवं कैसे ब्रिक्स समूह इस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। तीसरे दिन का कार्यक्रम ब्रिक्स के व्यापार के एजेंडे और लोचदार पूर्ति श्रंखला पर चर्चा से शुरु हुआ। इक्कीसवीं सदी में ब्रिक्स अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार का ढांचा तैयार करे जो विकासशील देशों की अवश्यकताओं पर ध्यान दे सके और अवरोधों को घटा कर, नियमों को सुप्रवाही बनाकर सेवाओं और वस्तुओं में अधिक प्रवाह को बढ़ाया।

श्रम बल को खड़ा करना तथा नौकरी के लिए शिक्षा कार्य सूची के नए प्रतिरूप और कौशल से सुसज्जित करने पर भी चर्चा हुई। वर्तमान और भविश्य के कार्य बल को नई ढंग से शिक्षित और कुशल बनाना ताकि विकास राष्ट्रों में उत्तम पद्धतियां अपनाई जा सकें। तथा बीसवीं सदी की असमानताओं को 21वीं सदी में दोहराया ना जा सके।■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

टी–20 में विकासशील देशों से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए

दुनिया भर के शोधकर्ताओं के अनुसार, थिंक20 में, जो 20 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं वाले जी20 समूह से जुड़े महत्वपूर्ण जुड़ाव समूहों में से एक है, विकासशील देशों के विचार मंडलों से अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और उसे वैश्विक शासन से सम्बन्धित मुद्दों पर अपनी नीतिगत सिफारिशें समय पर प्रस्तुत करनी चाहिए, ताकि जी20 के नेता उनका विश्लेषण कर सकें और उन्हें अपनी अंतिम घोषणा में शामिल कर सकें। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रमुख विकासशील देश इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः 2022, 2023, 2024 और 2025 में जी20 की अध्यक्षता करने वाले हैं। अपेक्षा की जा जाती है कि विकास का एजेंडा जी20 और इसके जुड़ाव समूहों – बिजनेस 20, थिंक 20, वूमेन 20, यूथ 20, लेबर 20, अर्बन 20, सिविल 20 और साइंस 20 – द्वारा होने वाली चर्चाओं में सबसे पहले और केंद्र में रहेगा। प्रक्रियाओं को और अधिक समावेशी बनाने के लिए अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा आवाज उठाए जाने की मांग की जा रही है।

24 नवंबर, 2021 को आरआईएस द्वारा आयोजित 'आगामी जी20 की विकासशील देशों द्वारा अध्यक्षता के लिए टी20 सुधार' पर एक हुए वबीनार के सत्र में बोलते हुए, टी20 इंडोनेशिया के प्रमुख सह–अध्यक्ष और इंडोनेशिया के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर बंबांग ब्रोडजोनगोरो ने कहा कि इंडोनेशिया सभी महाद्वीपों और सभी आय समूहों के देशों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अवसंरचना वित्तपोषण, एसडीजी, डिजिटलीकरण और बहुपक्षवाद के पुनरुद्धार जैसे मुद्दों का विकासशील और विकसित देशों के लिए बहुत महत्व है। इसलिए इन मुद्दों को जी20 सदस्यों द्वारा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए टी20 प्रक्रिया में निरंतरता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया की जी20 अध्यक्षता के दौरान गरीबी और आय असमानता के साथ–साथ सतत्त विकास एजेंडा के सतत वित्तपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी।

टी20 इंडोनेशिया के प्रमुख सह–अध्यक्ष, प्रो जिस्मान सिमंदजुंतक, ने कहा कि नवीन नीतिगत विचार प्राप्त करने की दृष्टि से इंडोनेशिया अफ्रीकी विचार–मंडलों से संपर्क करेगा और अन्य शोधकर्ताओं के नीतिगत संक्षिप्त विवरण पर भी विचार करेगा, जिन्हें अब तक टी20 प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला है। दक्षिण अफ्रीकी अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संस्थान, दक्षिण अफ्रीका की मुख्य कार्यकारी सुश्री एलिजाबेथ सिदिरोपोलोस ने 'टी20 अफ्रीका स्टैंडिंग ग्रुप' को एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और अब से टी20 प्रक्रिया का हिस्सा बताया। सुश्री अनीता प्रकाश, वरिष्ठ नीति सलाहकार (अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध), इरिया, जकार्ता ने प्रतिभागियों को इरिया, आरआईएस और इंडोनेशिया के 'एलवामफब आईयू' द्वारा नए शुरू किए गए जी20 शोध मंच के बारे में जानकारी दी, ताकि वैश्विक शासन के मुद्दों पर विभिन्न थिंक–टैंक और शोधकर्ताओं के विचारों का मिलान किया जा सके। जर्मनी विकास संस्थान, जर्मनी के उप निदेशक, डॉ इममे स्कोल्ज़, ने टी –20 जर्मनी के आयोजन के तरीकों का उल्लेख किया जिसमें इंडोनेशिया और भारत के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जर्मनी 2022 में जी7 की अध्यक्षता करने जा रहा है और विभिन्न मुद्दों पर इंडोनेशिया (2022 के लिए जी20 प्रेसीडेंसी) के साथ घनिष्ठ सहयोग के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जी7–जी20 और उनसे जुड़े जुड़ाव समूहों का समन्वय तंत्र सभी जी20 आयोजनों पर लागू किया जाना चाहिए।

सत्र में अन्य प्रमुख वक्ता थेः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; प्रोफेसर नाओयुकी योशिनो, प्रोफेसर अवकाशप्राप्त (अर्थशास्त्र), कीओ विश्वविद्यालय, जापान; सुश्री गाला डियाज़ लैंगौ, कार्यकारी निदेशक, सीआईपीपीईसी, अर्जेंटीना; डॉ एंटोनियो विलाफ्रांका, अनुसंधान निदेशक, इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज, इटली; डॉ रियातु मरियातुल किबथियाह, निदेशक, एलपीईएम, इंडोनेशिया विश्वविद्यालय; डॉ योस रिज़ल दामुरी, प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जकार्ता; डॉ निकोलस बुकौड, ग्रैंड एलायंस, पेरिस; डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस और श्री ऑगस्टीन पीटर, विजिटिंग फेलो, आरआईएस। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान

आरआईएस ने ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव, जर्मनी के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को जी–20 फाइनेंस ट्रैक के भाग के रूप में 'जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान' विषय पर एक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया। इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय की वित्तीय नीति एजेंसी के अध्यक्ष श्री फेब्रियो नाथन काकारिबू ने इसमें उद्घाटन भाषण दिया। पहले पूर्ण सत्र में, राजदूत अभय ठाकुर, अपर सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय और जी–20 सोर–शेरपा द्वारा विशेष संबोधन किया गया। इसमें दो वक्ताओं : डॉ राजा अल मरजोकी, मुख्य आर्थिक सलाहकार, अर्थव्यवस्था और नियोजन मंत्रालय, सऊदी अरब और रिधा विराकुसुमा, अध्यक्ष, बी20 इंडोनेशिया, वित्त और अवसंरचना कार्यबल ने भाग लिया। इसमें चर्चा करने वालों में डॉ इरिना करापेत्यांत्स, निदेशक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस, रशियन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट तथा क्रिश्चियन वर्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस और निदेशक, पब्लिक सेक्टर सॉल्यूशंस, स्विसरे शामिल थे।

दूसरे पूर्ण सत्र का संचालन डॉ. निकोलस जे. ए. बकॉड, सह–अध्यक्ष टी20 इंडोनेशिया इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स ने किया। चर्चा करने वालों में डॉ फ्रांसेस्को प्रोफुमो, अध्यक्ष, फोंडाजियोन कॉम्पेनिया डि सैन पाओल और पूर्व प्रमुख सह–अध्यक्ष, टी20 इटली इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्सय ओईसीडी में वरिष्ठ अर्थशास्त्री और टी20 इंडोनेशिया टीएफ8 रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग के सह–अध्यक्ष डॉ रैफेले डे ला क्रोस, और डॉ सेबेस्टियन वेनजेस, ग्लोबल पब्लिक गुड्स, जीआईजेड के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के प्रोजेक्ट लीड, प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, रिसर्च फेलो, आरआईएसय डॉ.यानिक ऑट्रेट, सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, फ्रांस के पारिस्थितिकी परिवर्तन मंत्रालय शामिल थे। समापन भाषण इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय के श्री सुदार्टो ने दिया। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

आरआईएस में आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) पर विशेा सप्ताह

विकास साझेदारी के 75 वर्ष–अनेकता, विविधता और सामूहिक प्रगति के प्रति समर्पण की गाथा पर प्रदर्शनी

भारत की माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी आरआईएस द्वारा मनाए जा रहे एकेएएम में अपने उद्‌गार प्रकट कर रही हैं।

भारत 'विकास सहयोग' के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी है, क्योंकि उसके द्वारा तीसरी दुनिया के देशों (यानी ग्लोबल साउथ) को प्रौ्द्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता के साथ– साथ वित्तीय सहायता बिना किसी शर्त के और *'वसुधैव कुटुम्बकम'* (समूचा विश्व एक परिवार है) के वैदिक मंत्र की भावना के साथ उपलब्ध करायी जाती है। यह उद्‌गार माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 21 फरवरी, 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अंतर्गत आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

आरआईएस ने विदेश मंत्रालय के एकेएएम कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 75 वर्षों में भारत की ओर से की गई विकास सहयोग संबंधी पहलों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। आज़ादी के 75 वर्षों का जश्न तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव उपयुक्त रूप से मनाने के लिए आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के बाद इसी विषय पर सप्ताह भर चलने वाली एक प्रदर्शनी प्रारंभ की गई।

रिपोर्ट अनावरण करने के अवसर पर श्रीमती लेखी ने कहा, ''हम (भारत) इस आशय (विकास सहयोग में) से अग्रणी (विश्व में) है, लेकिन हम अपने महत्व को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हमारी (भारत की) अच्छाई और कोविड–19 महामारी के दौरान हमारी ओर से विश्व को टीकाकरण और चिकित्सा सहायता समेत उपलब्ध करायी गई मदद का दाम कभी चुकाया नहीं जा सकता, जिसका उत्सव इस प्रदर्शनी के माध्यम से मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर आरआईएस के अध्यक्ष डॉ. मोहन कुमार ने कहा कि भारत की ओर से दिया जाने वाला विकास सहयोग सहायता प्राप्तकर्ता देशों की प्राथमिकताओं पर आधारित और पूरी तरह मांग से प्रेरित है। आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि आरआईएस ने कड़ी मेहनत करके सभी मंत्रालयों की वार्षिक रिर्पोटों से 1947 से 2022 तक की जानकारी का संकलन किया है। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता केवल धन के संदर्भ में ही नहीं रही, बल्कि 'सदर्न कलेक्टिव', 'जलवायु न्याय', 'अवैध वित्तीय प्रवाह', 'प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र', 'शांति सेना' और 'लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) जैसी अवधारणाओं के रूप में भी रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विश्व की सहायता करने के लिए नेट–ज़ीरो स्टेटस हासिल करने की बात कही थी। प्रो. चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी संस्थाओं के गठन में भी सहायता की है। भारत ने 1952 में

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

भारत की माननीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन कर रही हैं।

नेपाल में 'भारत सहायता मिशन' की भी स्थापना की और बाद में इसका नाम बदलकर 'भारतीय सहयोग मिशन' करने का फैसला लिया गया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि सहायता का दृष्टिकोण इस्तेमाल करने की बजाए, देने का सिद्धांत विकास सहयोग पर आधारित होना चाहिए।

आरआईएस की रिपोर्ट के अनुसार गरीब देशों को भारतीय बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत का पूर्वनिश्चित शुल्क 7 बिलियन डॉलर का था। आलोच्य अवधि के दौरान कृषि उपकरणों के वितरण सहित भारत द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति संबंधी सहायता भी 7 बिलियन डॉलर रही। संयोग से, आरआईएस में विकास सहयोग के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के प्रति समर्पित एक मंच– भारतीय विकास सहयोग मंच (एफआईडीसी) है, जो अंतरराष्ट्रीय विकास सहयोग परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भारत के अपने अनुभवों का उपयोग करने की दिशा में प्रयासरत है। यह विदेश मंत्रालय, अकादमिक और नागरिक समाज संगठनों के विकास भागीदारी प्रशासन की एक त्रिपक्षीय पहल है।

शुरुआत से ही मंत्री महोदया ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य देशों के साथ भारत के आधिकारिक संपर्कों में यह रिपोर्ट उपयोगी साबित होगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की समस्त सूचनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के प्रमुख अंश

- वर्ष 1947 से 2022 तक भारत द्वारा प्रदान की गई विकास सहायता की मात्रा 127 बिलियन डॉलर रही।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) सहित कई पहलों के माध्यम से विकासशील देशों के अन्य देशों के 350,000 लोगों को प्रशिक्षित किया।
- भारत द्वारा लगभग 31 बिलियन डॉलर राशि की ऋण सहायता प्रदान की गई है, और इसका लगभग आधा भाग पड़ोसी देशों को दिया गया।
- कोविड–19 के प्रकोप के बाद, भारत ने 90 से अधिक देशों को टीके और लगभग 100 देशों को 4 बिलियन डॉलर का सहायता अनुदान प्रदान किया है।

भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राज कुमार रंजन सिंह प्रदर्शनी में प्रतिभागियों से मुलाकात कर रहे हैं।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

"भारत की विकास साझेदारी के 75 वर्षों की रूपरेखाः नई संभावनाओं की तलाश और उभरती चुनौतियों से निपटना" विषय पर पैनल परिचर्चा

आज़ादी के 75वें वर्ष का समारोह तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) को उपयुक्त रूप से मनाने के लिए आरआईएस की ओर से 21–27 फरवरी, 2022 के दौरान एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें भारत सरकार की राष्ट्रीय संस्थाओं, प्रमुख सार्वजनिक और निजी इकाइयों, नागरिक समाज संगठनों और सामाजिक उद्मियों को साथ लाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विविध देशों के साथ भारत की विकास पहलों को दर्शाया गया।

इस अवसर पर आरआईएस ने 25 फरवरी, 2022 को "भारत की विकास साझेदारी के 75 वर्षों की रूपरेखा : नई संभावनाओं की तलाश और उभरती चुनौतियों से निपटना" विषय पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया। डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने इसमें स्वागत भाषण दिया और राजदूत अमर सिन्हा, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने इसकी अध्यक्षता की। इस परिचर्चा में : श्री प्रभात कुमार, अपर सचिव (डीपीए), विदेश मंत्रालय; डॉ सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), संस्कृति मंत्रालय, श्री डेविड रसकिन्हा, पूर्व प्रबंध निदेशक, एक्जिम बैंक; डॉ रुचिता बेरी, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, द मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी–आईडीएसए); डॉ एस के वार्ष्णेय, सलाहकार/वैज्ञानिक जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग; श्री एस कुप्पुस्वामी, सलाहकार–समूह वित्त और विशेष परियोजनाएं, शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड और श्री चंद्र भूषण, अध्यक्ष और सीईओ, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (आई फॉरेस्ट) ने भाग लिया। डॉ. सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

बाएं से दाएंः डॉ. सब्यसाची साहा, श्री चंद्र भूषण, श्री डेविड रसकिन्हा, श्री प्रभात कुमार, राजदूत अमर सिन्हा, डॉ सच्चिदानंद जोशी, डॉ रुचिता बेरी और श्री एस कुप्पुस्वामी

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

दक्षिण–दक्षिण सहयोग के नए मोर्चे

दक्षिणीय सहयोग को प्रोत्साहन

आरआईएस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर समारोह।

आरआईएस ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि विकासशील देशों और उसके बाहर अपने विशेष विंग, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर (जीडीसी) के माध्यम से विचारों, नवाचारों और समाधानों को सांझा कर उन्हें आगे बढ़ा सके। जीडीसीआरआईएस और बीएमजीएफ अन्य प्रमुख विकास मुद्दों के साथ–साथ पोषण, स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी की तैयारी, कृषि, डिजिटल वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिणीय सहयोग के लिए साझेदारी को मजबूत करने और नई साझेदारियाँ बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे।

यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर प्रगति के लिए एक जीवंत, रचनात्मक और निरंतर जुड़ाव बनाने की दिशा में वैश्विक दक्षिण के बीच विकास नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस जुड़ाव में विकास समाधानों में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उनके दस्तावेजीकरण के लिए समस्तरीय और ऊर्ध्व एकीकृत साझेदारी और राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र, विचार मंडलों, नागरिक समाज और शिक्षाविदों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच बनाना शामिल होगा। इसका उद्देश्य ज्ञान आदान–प्रदान कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और कार्यान्वयन सहायता प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विचारों की साझेदारी को सुगम बनाना है। यह जुड़ाव दक्षिणीय सहयोग के व्यापक लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में स्थानीय और विश्व स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को क्यूरेट करने में व्यापक समग्र समर्थन प्रदान करके भारत और वैश्विक दक्षिण में विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच को सक्षम करेगा।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि वैश्विक विकास केंद्र का हमारा आरंभिक विचार माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए कई प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिन्होंने हमारी आर्थिक विकास

डॉ राजकुमार रंजन सिंह, माननीय विदेश राज्य मंत्री

“ इस अवसर पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा, ''भारत को संकट के समय में क्षेत्र में सर्वप्रथम क्रियाशील होने वाला देश, एक जलवायु की दिशा में पहलकदमी करने में अग्रणी, विश्व के औषधालय, प्रतिभा के भंडार और एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में देखा जाता है। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आरआईएस ने दक्षिणीय सहयोग के ढांचे के भीतर माननीय प्रधान मंत्री के विचारों को अन्य विकासशील देशों तक ले जाने के लिए अपने परिसर में एक विशेष केंद्र, ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर, (जीडीसी) की स्थापना की है। आरआईएस और बीएमजीएफ के बीच यह साझेदारी वैश्विक वस्तुओं को बढ़ावा देने की भारत की नीति के हिस्से के रूप में इच्छुक भागीदार देशों और संस्थानों के बीच ज्ञान के संस्थागत हस्तांतरण, ज्ञान के आदान–प्रदान के लिए नीति अनुसंधान और आउटरीच को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं एक बेहतर दुनिया के लिए इस रचनात्मक पहल के लिए आरआईएस में जीडीसी टीम और बीएमजीएफ के हमारे दोस्तों को बधाई देना चाहता हूं।

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

पहलों में समावेशन और स्थिरता लाने के प्रयास में बहुत योगदान दिया है। ये दो आयाम हमारे द्वारा शुरू किए गए लगभग सभी कार्यक्रमों की मुख्य ताकत रहे हैं, जैसे आधार सक्षम ई–भुगतान सेवाएं या यूपीआई या भीम या यहां तक कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, आदि। ये कार्यक्रम लीकेज को रोककर, भारत के सबसे वांछित समुदायों को लाभ लक्षित करते हुए लाभार्थियों की पहचान करके सत्तता, समावेशन और शासन में दक्षता लाने के विचार की दिशा में योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इस अवसर पर, गार्गी घोष, अध्यक्ष, ग्लोबल पॉलिसी एंड एडवोकेसी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वैश्विक मंच पर वैक्सीन निर्माण और डिजिटल स्वास्थ्य से लेकर डिजिटल वित्तीय समावेशन और उससे आगे तक भारत का नेतृत्व के महान उदाहरण हैं, जो क्रॉस–लर्निंग और सहयोग के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। हम विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के साथ इस जुड़ाव को लेकर उत्साहित हैं और आशा करते हैं कि यह मंच वैश्विक दक्षिण में विस्तारित साझेदारी के अवसर प्रदान करेगा और संधारणीय विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देगा।

सहयोग के महत्व के बारे में बात करते हुए, बीएमजीएफ के इंडिया कंट्री डायरेक्टर, श्री हरि मेनन ने कहा कि अनुसंधान में तेजी लाने, नए उपकरण विकसित करने और स्वास्थ्य और विकास में निरंतर प्रगति के लिए सहयोग और साझेदारी अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक भागीदारी के लिए भारत सरकार की गहरी प्रतिबद्धता के ध्यान में रखते हुए, वैश्विक दक्षिण में स्वास्थ्य और विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने वाली संयुक्त प्रतिबद्धता और साझा शिक्षा को सक्षम करने में सरकारों, बहुपक्षीय संस्थानों, शिक्षाविदों और स्वैच्छिक और निजी क्षेत्रों के बीच मजबूत सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बीएमजीएफ को विदेश मंत्रालय और आरआईएस के साथ काम करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। ■

माननीया विदेश राज्य मंत्री ने आरआईएस के कार्यक्रम की सराहना की और गहन नीतिगत जुड़ाव का आह्वान किया

भारत की माननीया विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आरआईएस के कार्यक्रम के संदर्भ में संकाय के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र के लिए 30 दिसंबर, 2021 को आरआईएस में पधारी। गहन संवाद सत्र के दौरान, आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने माननीया मंत्री को संस्थान के इतिहास और संगठनात्मक संरचना, महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों, अनुसंधान स्तंभों, साझेदारी मंचों, वैश्विक नेटवर्क, प्रकाशन और क्षमता निर्माण संबंधित कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। संकाय के सदस्यों ने माननीया मंत्री को अपने कार्यक्षेत्रों के बारे में अवगत किया जिनमें प्रमुख हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार; लैटिन अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक संबंध; नियम–आधारित भारत–प्रशांत, भारत–यूरोपीय संघ संयोजकता साझेदारी और विकास; हिंद महासागर में नीली अर्थव्यवस्था की संभावनायें; संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के संदर्भ में; दक्षिणीय और त्रिकोणीय सहयोग; विज्ञान नीति और विज्ञान राजनय तथा क्षेत्रीय विकास के लिए भारत और मध्य एशिया के बीच साझेदारी आदि। माननीय मंत्री ने सभी संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की और विकासशील देशों के विचार–मंडल के रूप में कार्य करने की दिशा में उपरोक्त क्षेत्रों में आरआईएस के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी संकाय सदस्यों को साक्ष्य–आधारित और नीति–प्रासंगिक अनुसंधान में संलग्न होने, कठोर विश्लेषण करने और इनमें राष्ट्रीय हित को जोड़ने के साथ–साथ सामूहिक बौद्धिक प्रयासों में भारतीय विचार और संस्कृति को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

भारत–आस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना

द एशियन फाउंडेशन और आरआईएस की ओर से ''एडवांसिंग साउथ–साउथ कोऑपरेशनः इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स विद पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज'' के 2021 के प्रकाशन और आस्ट्रेलियाई विदेश एवं व्यापार विभाग (डीएफएटी) के समर्थन के बाद, 'भारत–आस्ट्रेलिया–प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना' विषय पर चिंतन के लिए 31 मार्च 2022 को वेबिनार आयोजित किया गया। भारत, आस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपसमूह देशों के वक्ताओं ने भारत–प्रशांत द्वीपसमूह देशों के बीच साझेदारी के इतिहास और संभावनाओं पर गौर किया और पीआईसी में आस्ट्रेलिया और भारत के हितों के संयोजन के बिंदुओं पर चर्चा की। वेबिनार ने प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया। इसमें इस बात को रेखांकित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में त्रिकोणीय सहयोग की संभावनाओं का विश्लेषण करने के लिए और अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए। ■

सतत विकास लक्ष्यों पर अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारत के माननीय विदेष राज्य मंत्री डॉ राज कुमार रंजन सिंह, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के षोधार्थियों के साथ बातचीत करते हुए।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर पूर्वोत्तर के युवा शोधार्थियों के लिए दो सप्ताह के अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण आरआईएस और नॉर्थ ईस्ट ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एडवोकेसी फाउंडेशन (एनईटीआरए) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत आरआईएस, नई दिल्ली में 14–18 मार्च, 2022 के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आठ पूर्वोत्तर राज्यों के कुल 15 शोधार्थी शामिल हुए।

एफआईडीसी और प्रिया के अध्यक्ष डॉ राजेश टंडन ने अपने उद्‌घाटन भाषण में 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में एसडीजी का स्थानीयकरण' के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एसडीजी की परिकल्पना मौलिकता और प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए मूलभूत ज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़ने के लिए मूल निवासियों को साथ जोड़कर और उनके साथ काम करके ही परिपूर्ण की जा सकती है। उन्होंने प्रतिभागियों से अपना शोध कार्य अपने लोगों या अपने समुदाय को समर्पित करने का आग्रह किया।

आरआईएस में विजिटिंग फेलो प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती ने सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजी) पर संक्षिप्त भाषण तथा सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में दो सप्ताह के अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम के महत्व का वर्णन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने आरआईएस और एनईटीआरए के सहयोग के महत्व तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में समस्त 17 एसडीजी लाने या हासिल करने के लिए उनके द्वारा मिल–जुलकर किए जाने वाले कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रो. चक्रवर्ती ने अपनी प्रस्तुति में पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी के स्थानीयकरण के मुद्दों को भी उठाया।

माननीय विदेश राज्य मंत्री डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी हासिल करने के बारे में प्रतिभागियों के प्रश्नों और सुझावों को जाना। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि क्षेत्र की मौलिकता को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं को आधुनिक ज्ञान के साथ एकीकृत करके एसडीजी हासिल किए जाने चाहिए। प्रो. एस के मोहंती, वरिष्ठ प्रोफेसर, आरआईएस और डॉ. सुमित सेठ, संयुक्त सचिव, नीतिगत योजना एवं अनुसंधान, विदेश मंत्रालय भी इस बातचीत में सम्मिलित हुए।

, सडीजी–शोधार्थियों के साथ बातचीत करते हुए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने सभी प्रतिभागियों से जमीनी स्तर पर जाने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों का पता लगाने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार एसडीजी–अनुसंधान विद्वानों के साथ।

नीति निर्माताओं को स्थानीय लोगों के लिए उपयुक्त नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने 'भारत का विकास सहयोग : 17 एसडीजी के संबंध में क्रॉस बॉर्डर स्पेक्ट्रम' के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि शोधकर्ता को अपने क्षेत्र में मौजूद बुनियादी समस्याओं का पता लगाने और उनके उपयुक्त सर्वोत्तम संभावित विकल्पों को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्थानीय समुदाय से जुड़ी समस्याओं को हल करने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत तो इस बात की है कि उन समस्याओं के कारणों का पता लगाया जाए।

वक्ताओं में, आरआईएस के फेलो श्री शुभोमॉय भट्टाचार्य ने ऊर्जा सुरक्षा (एसडीजी–7) और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत से नवीकरणीय स्रोत में परिवर्तन के जोखिम और लाभ के कारक को समझने की अनिवार्यता के बारे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशिष्ट विकल्पों की पहचान करने की आवश्यकता की ओर इंगित किया।

आरआईएस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने एसडीजी के वित्त पोषण से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने घरेलू और विदेशी संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाने के महत्व पर भी बल दिया।

सबके लिए निरंतर स्वास्थ्य (एसडीजी–3) से संबंधित मुद्दों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर, आरआईएस और एनआईपीओ के अध्यक्ष टी.सी. जेम्स ने स्वास्थ्य, सबके लिए स्वास्थ्य और निरंतर स्वास्थ्य देखरेख के बारे में विस्तार से बताया। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी के लिए निरंतर स्वास्थ्य हासिल करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों की सहायता की आवश्यकता है।

एनआईयूए में वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ पूर्वा ने अपनी प्रस्तुति में इस बात की ओर संकेत किया कि सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को वैश्विक ढांचे के समानांतर लाना आसान नहीं है, इसलिए हमें शहर के स्तर (एसडीजी–11) पर जाने और इन संकेतकों को विकसित करने तथा उन संकेतकों को समझने की आवश्यकता है।

आरआईएस में प्रोफेसर अमिताभ कुंडू ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे एसडीजी–11 शहरीकरण की मौजूदा संरचना पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि मौजूदा सेटलमेंट हायरार्की (यानी आबादी या अन्य मापदंडों पर आधारित बस्तियों के पदानुक्रम) में सब कुछ बड़े शहरों में केंद्रित है, जो फ्रेमवर्क में चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने एक शहरी प्रवास रणनीति और बस्ती की रणनीति बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पास एक ऐसी बस्ती संरचना होनी चाहिए जो पूरे क्षेत्र को एकीकृत कर सके।

प्रिया के निदेशक डॉ कौस्तुभ बंद्योपाध्याय ने समुदाय या राष्ट्र में किसी नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सीएसओ की मदद से हाशिए पर मौजूद लोगों और वंचितों की पहुंच उनके लिए बनाई गई सेवाओं तक संभव हो पाती हैं। उन्होंने साझेदारियां कायम करने के कारण और अपेक्षाकृत समकक्ष सामर्थ्य वाले संगठनों, स्पष्ट रूप से परिभाषित संगठनात्मक संरचना और एक–दूसरे के साथ काम करने की सभी भागीदारों की क्षमता में वृद्धि सहित सफल साझेदारी में योगदान देने वाले कारकों को रेखांकित कियाA

त्रिपुरा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, एनईटीआरए के संस्थापक डॉ जयंत चौधरी ने इस बारे में चर्चा की कि पूर्वोत्तर भारत में एसडीजी का स्थानीयकरण किस प्रकार किया जाए। डॉ. चौधरी ने विभिन्न हितधारकों का क्षमता निर्माण करने, पूर्वोत्तर भारत में मौजूदा स्थानीय स्तर के संस्थानों को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सीएसओ के महत्व पर भी बल दिया।

सभी प्रतिभागियों ने आरआईएस द्वारा 'मूल निवासी और भारत' विषय पर आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में भी भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों ने एनईटीआरए के बोर्ड मेंबर और अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग, आरजीयू के प्रोफेसर केसांग देगी के मार्गदर्शन में पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का अगला चरण अप्रैल में क्षेत्रीय केंद्र, आईजीएनटीयू, मणिपुर में आयोजित किया जाएगा। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाना– भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना

1990 के दशक के आरंभ सें शुरू हुए वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्ष 2022 को आसियान–भारत मैत्री वर्ष नामित किया गया है। आसियान–भारत वार्ता संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आरआईएस, आसियान–भारत संबंधों की अनवरत चुनौतियों और उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्चुअल मोड में वेबिनारों का आयोजन कर रहा है। आरआईएस साल भर आसियान–भारत संबंधों के पांच विषयगत क्षेत्रों पर पांच वेबिनार आयोजित करेगा। इसका प्रारंभ 18 फरवरी, 2022 को वर्चुअल माध्यम से आसियान–भारत संबंधों के रणनीतिक स्तंभ पर आधारित पहले वेबिनार के आयोजन से हुआ। यह वेबिनार 'भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' विषय पर आयोजित किया गया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस ने स्वागत भाषण दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने उद्घाटन भाषण दिया। महामहिम राजदूत श्री अनग शॉन, कंबोडिया दूतावास, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान में भारत के राजदूत, आसियान में भारतीय मिशन, जकार्ता ने विशेष भाषण दिए। पैनल चर्चा की अध्यक्षता राजदूत राजीव भाटिया, विशिष्ट फेलो, गेटवे हाउस, मुंबई ने की। इसमें भाग लेने वाले वक्ताओं में सुश्री जोआन लिन, प्रमुख शोधकर्ता, आसियान स्टडी सेंटर, आईएसईएएस यूसुफ–इशाक इंस्टीट्यूट, सिंगापुरय प्रो. राजाराम पांडा, सीनियर फेलो, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी (एनएमएमएल), नई दिल्लीय श्री वफा खरिश्मा, शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस (सीएसआईएस), जकार्ता और डॉ लॉरेंस प्रभाकर विलियम्स, प्रोफेसर, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, चेन्नई शामिल थे। डॉ. संपा कुंडू, सलाहकार, आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस ने ध न्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

कोविड–19 के बाद एशिया एवं प्रशांत में आर्थिक लचीलापन

कोविड–19 के बाद एशिया एवं प्रशांत में आर्थिक लचीलेपन पर 29 जुलाई 2021 को परिचर्चा आयोजित की गई। आचार्य सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आर आई एस के स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। परिचर्चा में सम्मिलित थे, डॉक्टर श्वेता सक्सैना, चूएनएसोप, नई दिल्ली; आचार्य राम उपेंद्र दास, प्रमुख, क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, नई दिल्ली और श्री राजन सुदेश रत्न, आर्थिक मामले अधिकारी, एसकेप–एसएसडब्लूए। परिचर्चा का केन्द्र था कोविड–19 के बाद आर्थिक लचीलापन को बढ़ावा तथा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति। अन्य संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिसमें आर्थिक लचीलापन तथा वित की चुनौतियाँ शामिल हैं। डॉ पंकज वशिष्ठ, सहयोगी आचार्य, आर आई एसए ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ■

भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रष्शांत में रणनीतिक संरचना विकसित करने पर वेबिनार

आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 18 फरवरी, 2022 को पहला वेबिनार ' भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' विषय पर वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। महामहिम राजदूत श्री अनग शॉन, कंबोडिया दूतावास, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान में भारत के राजदूत, आसियान में भारतीय मिशन, जकार्ता ने विशेष भाषण दिए। प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, नई दिल्ली ने उद्घाटन भाषण दिया। भारत की हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल (इंडो–पेसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) और हिंद–प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोण, हिंद–प्रशांत में शांति और सुरक्षा के लिए दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हाल के अकादमिक और नीतिगत विमर्शों में हिंद–प्रशांत पर बहुत चर्चा हुई है और यह भारत की विदेश नीति के निरुपण में इसकी प्रासंगिकता को बताता है। हिंद–प्रशांत में भारत की ओर से हाल में की गई पहल विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और विकास की निरंतरता के लिए उसकी स्थिति को दर्शाती हैं। हिंद–प्रशांत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शीत युद्ध के बाद के दौर की विशेषताओं का प्रतीक है और बहुपक्षीय रचनावाद की प्रासंगिकता दर्शाता है। वेबीनार के अंत में डॉ प्रबीर डे ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

वैश्विक मुद्दे और विकास सहयोग की संरचना

वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना : विश्व में भारत

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान जारी है।

41वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान 28 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाना : विश्व में भारत' था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता टेरी की महानिदेशक डॉ. विभा धवन ने की। स्वागत भाषण डॉ. भास्कर बालकृष्णन, विज्ञान कूटनीति, आरआईएस द्वारा दिया गया। उसके बाद इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक श्री सुनीत टंडन ने संक्षिप्त भाषण दिया। डॉ अजय माथुर ने अपने संबोधन में दुनिया और भारत में हो रहे ऊर्जा परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत इस बात को रेखांकित करते हुए की कि नवीकरणीय ऊर्जा और गैर–जीवाश्म ईंधन ने बिजली उत्पादन मिश्रण का एक बड़ा भाग ले लिया है। वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 31 फीसदी है, जबकि भारत में यह 36 फीसदी है। भारत के लिए, यह इससे संबंधित पेरिस समझौते के लक्ष्य को अग्रिम तौर पर लगभग प्राप्त करने जैसा है। डॉ माथुर ने इतनी कम अवधि में इस तरह के महत्वपूर्ण बदलावों के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रेरक कारकों के बारे में विस्तार से बताया। इसका एक प्रमुख कारक नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में आई पर्याप्त गिरावट है। अन्य प्रमुख कारक बैटरी ऊर्जा भंडारण की लागत में कमी आना है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक निवेश में काफी वृद्धि हुई है और इसलिए इसकी संस्थापित क्षमताओं में भी वृद्धि हुई है।

डॉ माथुर ने दो प्रमुख सार्वजनिक नीतिगत हस्तक्षेपों अर्थात कीमत में कमी और मांग का सृजन– का उल्लेख करते हुए बताया कि ये भारत की सौर ऊर्जा स्थापना में वृद्धि करने में अब तक सहायक रहे हैं। फीड–इन टैरिफ और रिवर्स ऑक्शन वाली दो चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से कीमत में कमी हासिल की गई है, जबकि मांग का सृजन नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) की प्रणाली के माध्यम से हासिल किया गया। इन नीतिगत उपकरणों ने नवीकरणीय ऊर्जा की लागत को किफायती और प्रतिस्पर्धी बना दिया है, इस प्रकार उनके अधिक उपयोग को बढ़ावा मिला है। हालांकि, जैसा कि डॉ माथुर ने उल्लेख किया है, सोलर सेल और सौर मॉड्यूल के मामले में भारत का व्यापार संतुलन इस समय बेहद विरुपित है, जिसमें वित्त वर्ष 2021 के दौरान भारत में स्थापित केवल 36 प्रतिशत सौर पैनलों की आपूर्ति घरेलू निर्माताओं द्वारा की गई थी। डॉ. माथुर द्वारा इंगित एक अन्य चुनौती सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पूंजी की लागत के संदर्भ में है, जो कि अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे कई अन्य देशों की तुलना में भारत में काफी अधिक है। उन्होंने आशा प्रकट की कि हाल ही में शुरू की गई पीएलआई योजना निकट भविष्य में इस परिदृश्य में बदलाव लाने में सफल होगी। ■

नवीनतम प्रकाशन

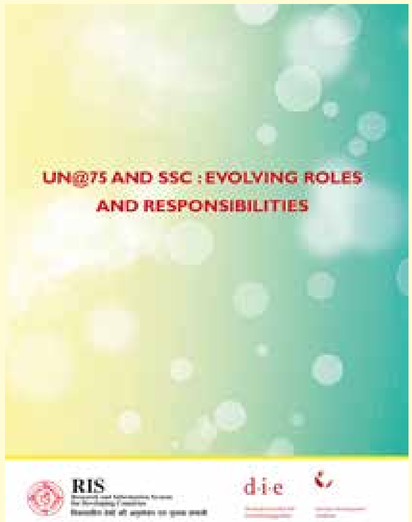

fjikVl

- **एफआईडीसी वार्षिक संगोष्ठी 2021: विकास सहयोग संवाद – संक्षेप में मुख्य बिंदु,** *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- **एफआईडीसी वार्षिक संगोष्ठी 2021: विकास सहयोग संवाद–मुख्य निष्कर्ष,** *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- यूएन@75 और एसएससी विकासशील भूमिका और जिम्मेदारियां, *आरआईएसबीआई और जर्मन विकास संस्थान 2021*

- लेवरेजिंग इंडियाज डिजिटल एक्सपीरियेंस इन पेमेंट्स एंड वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, जीडीसी, नई दिल्ली, 2022

- 75 इयर्स ऑफ डेवलॅपमेंट पार्टनरशिप –सागा ऑफ कमिटमेंट टू प्लूरेलिटी, डाइवर्सिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस आरआईएस, नई दिल्ली, 2022

- वर्चुअल ब्रेनस्ट्रोमिंग सेशन टी20 रिफॉर्म्स फॉर अपकमिंग जी 20 डेवलपिंग कंट्री प्रेजीडेंसीज, आरआईएस, नई दिल्ली, 2022

vkjvkb,l ppk i=

#272: भारत में मूल निवासी होने का आशय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ द्वारा टी सी जेम्स

#272: इंटरनेशनल डिस्कशन्स ऑन इन्डीजनस पीपुल एंड इंडिया, द्वारा टी सी जेम्स

#270: कोविड–19 एक अवसर फार्माकोविजिलेंस में सुधार सचया पाठक द्वारा प्रणाली राजेश्वरी सिंह और शुभिनी ए सराफ

th20 Mkbt LV

खंडः 1 संख्या : 2, अप्रैल, 2021

वॉल्यूम 1 नंबर 3 अक्टूबर 2021

अध्याय 2

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

प्रोफेसर एस के मोहंती

डॉ पंखुड़ी गौर

सहायक प्रोफेसर

वार्षिक रिपोर्ट : बहुपक्षवाद के संसाधन

वर्ष 2021 में राष्ट्रपति बिडेन के पद ग्रहण करने के बाद अमेरिकी प्रशासन की राजनीतिक व्यवस्था में आए में बदलाव से बहुपक्षवाद, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को नवजीवन प्राप्त हुआ है। डब्ल्यूटीओ में नए नेतृत्व की नियुक्ति के साथ ही सदस्य देशों की बढ़ती आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ में व्याप्त गतिरोध की जगह ऊर्जावान संस्था ने लेनी प्रारंभ कर दी है। बहुपक्षवाद की हाल की प्रथाओं और संयुक्त वक्तव्य पहल (जेएसआई) ने डब्ल्यूटीओ में विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचने की पुरातन प्रथाओं को अवरुद्ध किया है। डब्ल्यूटीओ में कुछ समझौतों के लगातार विरोध या खाद्य स्टॉकहोल्डिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ट्रिप्स छूट आदि जैसे कुछ समझौतों के दायरे में कमी ने विश्वसनीय, कुशल और पारदर्शी नियम बनाने वाली बहुपक्षीय संस्था के रूप में डब्ल्यूटीओ के प्रति सदस्य देशों के विश्वास को कमजोर किया है। इससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्वरूपों में क्षेत्रवाद का प्रसार हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 20वीं सदी के क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) से लेकर 21वीं सदी की क्षेत्रीय सुगमता तक क्षेत्रीय समूहों के व्यापक क्षेत्र की गवाह रही है। क्षेत्रीय समूहों का तेजी से प्रसार केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में ही नहीं, बल्कि भारत में भी देखा गया है, जो 2021 के बाद से वर्तमान में क्षेत्रवाद की 'दूसरी लहर' का साक्षी बन रहा है।

डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) के शुभारंभ की याद में, आरआईएस ने 25 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित ''डब्ल्यूटीओ एमसी12 के समक्ष मुद्दे : डब्ल्यूटीडीआर का लॉन्च'' कार्यक्रम में अपनी प्रमुख रिपोर्ट 'विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट' जारी की। रिपोर्ट में वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में मौजूद प्रौद्योगिकी और विकास की सांठगांठ की पेचीदगियों पर केंद्रित था। व्यापार का डिजिटलीकरण, कोविड —19 के दौरान स्वास्थ्य उपकरणों की उत्पादन गतिविधियों की बहाली, कोविड —19 टीकों के संदर्भ में ट्रिप्स पर बहुपक्षीय चर्चा, मत्स्य पालन सब्सिडी, विकासशील देशों के लिए एसएनडीटी प्रावधान, एलडीसी और एसआईडीएस, व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार, डब्ल्यूटीओ में सुधार तथा डब्ल्यूटीओ में सुधार के लिए वैश्विक शासन संरचना में आवश्यक परिवर्तन आदि जैसे कई अन्य मुद्दों पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण से चर्चा की गई। डब्ल्यूटीडीआर लॉन्च किए जाने के बाद एक पैनल चर्चा आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, राजदूत मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस, राजदूत जयंत दासगुप्ता, डब्ल्यूटीओ में पूर्व भारतीय राजदूत, श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, प्रो. अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह—संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, प्रोफेसर अभिजीत दास, प्रमुख, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज, आईआईएफटी, प्रो निशा तनेजा, प्रो एस के मोहंती, आरआईएस, डॉ प्रियदर्शी दास, डॉ सब्यसाची साहा और डॉ पंखुरी गौड़ शामिल थे। पैनल ने दोहा विकास एजेंडा (डीडीए) में 2001 से लंबित मत्स्य पालन सब्सिडी मुद्दे के सफल निष्कर्ष तक पहुंचने की आशा व्यक्त की।

डब्ल्यूटीओ का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी12) पहले 30 नवंबर—3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाला था, लेकिन दुनिया भर में ओमिक्रॉन फैलने के कारण इसे 12 से 17 जून

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

2022 तक स्थगित कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ में चर्चा के दौरान विकासशील देशों के हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एकजुटता के साथ और सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए आरआईएस ने विकासशील देशों के आर्थिक हितों की मजबूती और संरक्षण के लिए एक ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया। चर्चा में भाग लेने वालों में कार्लोस कोरिया, कार्यकारी निदेशक, साउथ सेंटर, राजदूत जयंत दासगुप्ता, राजदूत मोहन कुमार, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डॉ नागेश कुमार और डॉ पंखुरी गौड़ शामिल थे। यह चर्चा मोटे तौर पर मत्स्य पालन सब्सिडी (एफएस), कृषि सब्सिडी, ट्रिप्स छूट और एसएनडीटी जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विकासशील देशों की स्थिति मजबूत बनाने पर केंद्रित थी।

काफी अर्से से लंबित मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दा

मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को लेकर पिछले दो दशकों से बहुपक्षीय चर्चाओं में गतिरोध बरकरार रहा। अल्प संसाधन वाले और समृद्ध संसाधन वाले देशों के बीच मत्स्य पालन सब्सिडी की असमान प्रथाएं जारी रहने के कारण विकासशील देशों, विशेष रूप से एलडीसी और एसआईडीएस के आजीविका सुरक्षा संबंधी मामलों को समर्थन देने के लिए संतुलित और न्यायसंगत मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता आवश्यक था। डब्ल्यूटीओ का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, एमसी –12, जिसका आयोजन पहले 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक होना निर्धारित था, उससे पूर्व 29 मई 2021 को 'मत्स्य पालन सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ में चर्चा: मुद्दे, संभावनाएं और भविष्य की राह' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें स्वागत भाषण प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने दिया और सत्र की अध्यक्षता श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस ने की। पैनल चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भारत की आधिकारिक स्थिति, 'मई ड्राफ्ट' की तकनीकी व्याख्या, मत्स्य पालन सब्सिडी के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव और भारत में मत्स्य श्रमिकों की राय सहित मत्स्य पालन सब्सिडी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस चर्चा में डॉ तरुण श्रीधरण, श्री मुकेश भटनागर, प्रोफेसर एस.के. मोहंती, सुश्री रांजा सेनगुप्ता और श्री जयप्रकाश पैनल ने भाग लिया। चर्चा में सूक्ष्म–प्रबंधन के मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला को भी शामिल किया गया, जिनमें एलडीसी और एसआईडीसी के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट (एसएनडीटी) व्यवस्था में उपयुक्त प्रावधान, अवैध, गैर–सूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने से संबंधित सब्सिडी से जुड़े मुद्दे, 12 समुद्री मील क्षेत्रीय जल के भीतर सब्सिडी आदि शामिल थे। जून 2022 में डब्ल्यूटीओ (एमसी12) के समापन के बाद, मत्स्य पालन सब्सिडी का मुद्दा समावेशी रहा। इस मामले को डब्ल्यूटीओ के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।

क्षेत्रवाद से निपटना

क्षेत्रवाद के प्रति क्षेत्रीय दृष्टिकोण में, भारत को पिछले दो दशकों में क्षेत्रवाद/द्विपक्षवाद पर प्राथमिकता दी गई है। हाल के मुक्त व्यापार समझौतों में, वार्ताकार देश समझौते में नए प्रावधान शामिल करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो लगभग 21 वीं सदी के समझौतों के अनुरूप हैं। क्षेत्रवाद के प्रति भारत का दृष्टिकोण नए समझौतों पर हस्ताक्षर करना और समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा समझौतों को अद्यतन करना रहा है। आरआईएस ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कुछ देशों के साथ ऐसे संवाद शुरु किए हैं। आरआईएस ने आईसीडब्ल्यूए और कोरियन नेशनल डिप्लोमैटिक एकेडमी (केएनडीए) और कोरियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (केआईईपी) के सहयोग से 'उभरते क्षेत्रीय क्रम में भारत–कोरिया संबंधों को नया आकार देना: 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' को सुसंगत बनाने हेतु' विषय पर 'भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय संवाद' आयोजित किया, 27 अक्टूबर 2021 को एक वेबिनार का आयोजन किया गया। दोनों देशों के थिंक टैंक के विशेषज्ञों ने दिन भर की इस चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा बदलती वैश्विक व्यवस्था में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों, कोविड के बाद की स्थिति पर प्रतिक्रिया और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक आयाम सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्रित थी।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

आरआईएस ने 9 दिसंबर 2021 को चुंग–हुआ आर्थिक अनुसंधान संस्थान (सीआईईआर) के साथ "भारत में उभरती ग्लोबल वेल्यू चेन्स (जीवीसी) : भारत में ताइवान का निवेश बढ़ाना" विषय पर एक अन्य वेबिनार का आयोजन किया। इसमें दोनों थिंक टैंक के विशेषज्ञों ने सेमी–कंडक्टर प्रोडक्शन और वेल्यू चेन्स क्षेत्रों में द्विपक्षीय संपर्क, आईसीटी के साथ–साथ सेमी–कंडक्टर क्षेत्रों पर भारत का विजन, प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत–ताइवान सहयोग, प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने में जी2जी संबद्धता की भूमिका, वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति में कोविड –19 की प्रतिक्रिया तथा व्यापार और निवेश में घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी विकसित करना सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा की।

नाइजीरियाई रिसोर्स सेंटर (एनएआरसी) के सहयोग से आरआईएस ने 14 जुलाई 2021 को "औद्योगीकरण बढ़ाने हेतु एमएसएमई को प्रोत्साहनः चुनौतियां और संभावनाएं" विषय पर एक वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार को प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, महामहिम श्री अभय ठाकुर, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री गरबा अयोदजी वहाब, महानिदेशक, एनएआरसी, प्रोफेसर एस.के. मोहंती, आरआईएस, प्रोफेसर एम.एच. बाला सुब्रमण्य, आईआईएस, श्री जोसेफ ओलाटायो ओमिडीजी, नेक्सिम बैंक, श्री अदेयमी फोलोरुन्शो, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया और डॉ पंकज वशिष्ठ, आरआईएस ने संबोधित किया। वेबिनार में दोनों देशों में एमएसएमई की स्थिति और इस क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में सहयोग की आवश्यकता पर विचार–विमर्श किया गया।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

डॉ प्रियदर्शी दाश
सह प्रोफेसर

वित्तीय सहयोग के लिए व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करने का समय

कोविड –19 महामारी और उसके बाद रूस–यूक्रेन युद्ध ने पिछले तीन वर्षों में वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को पूर्णतया बदल कर रख दिया है। यह पूंजी प्रवाह के अचानक उलट जाने, 'पहले अपना घर सुरक्षित करने' के प्रयासों के कारण निवेश घटने, वित्तीय गुंजाइश सिकुड़ने, ऋण का बोझ बढ़ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की मांग बढ़ने, बढ़ती कीमतों और निजी क्षेत्र के निवेशकों की विमुखता के रूप में देखा गया। लम्बी अवधि तक चले लॉक–डाउन के परिणामस्वरूप घटी आर्थिक गतिविधियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े खर्चों के कारण कर राजस्व में गिरावट आई। विकासशील व एलडीसी को सबसे बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि बजट संबंधी बाधाओं ने बढ़ती ग़रीबी, रोज़ग़ार छिनने और कामग़ारों के अपने मूल स्थान की ओर लौटने की प्रक्रिया से निबटने के लिए नीतियों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की गुंजाइश को भी बहुत संकुचित कर दिया। हालांकि वित्तीय प्रोत्साहन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न–भिन्न रहा, लेकिन कोविड –19 के बाद देश को सामान्य स्थिति में लाने हेतु अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए देशों के सामने यही एक विकल्प था। अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां छिन जाने से सामाजिक–आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो गई और इससे राजकोष पर व्यापक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का पूरा दबाव आ गया।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने महामारी के दौरान उत्पादक क्षेत्रों के साथ–साथ घरेलू खपत में भी ऋण प्रवाह बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावित आबादी को राहत पहुंचाने के लिए ऋण चुकौती कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई और ऋण की पुनर्संरचना की गई। लॉक–डाउन के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिनटेक समाधान विभिन्न खुदरा लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने और लाखों लाभार्थियों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित करने में सरकारों को सक्षम बनाने में सहायक रहे। भारत सरकार ने सभी जन धन खाताधारकों के खातों में कोविड पैकेज हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेजोड़ तरीके से सफलतापूर्वक लाभ उठाया।

जहां एक ओर, महामारी के दौरान वित्तीय गुंजाइश काफी घट गई, वहीं कई देशों के लिए ऋण चुकौती के बोझ ने उनके बकाया भुगतान देय की स्थिति को बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दिया। आईएमएफ संकट वित्तपोषण ही उनके लिए एकमात्र विकल्प दिखाई दिया, हालांकि कर्ज चुकौती निलंबन पहल (डीएसएसआई) ने उन्हें अस्थायी रूप से कुछ राहत अवश्य दी। ऐसा कुछ समय से चल ही रहा है, इसलिए आईएमएफ ने भी अपने संकट वित्तपोषण की गुंजाइश कुछ बढ़ाने का प्रयास किया है। वास्तव में, दो दिन पहले ही आईएमएफ़ ने रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट की घोषणा की है जो जल्द ही पात्र देशों के लिए रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (आरएसएफ़) का संचालन करेगा। अब समय आ गया है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में आईएमएफ के अलावा, क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्थाओं या देशों के बीच कुछ इसी तरह की व्यवस्था के जरिए वित्तीय सहयोग को मजबूत किया जाए।

व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के क्षेत्र में अपने योगदान का प्रदर्शन चुके आरआईएस के पास वित्तीय सहयोग, बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, एसडीजी वित्तपोषण तथा विकास वित्तपोषण पर अनुसंधान तथा नीतिगत परामर्श के लिए एक समर्पित स्तंभ है। आरआईएस की वित्तीय टीम ने हाल ही में थिंक 20 (टी20) को बुनियादी ढांचे के लिए अभिनव वित्तपोषण, एसडीजी

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

के लिए मिश्रित वित्त, ऋण प्रबंधन ढांचे, आदि के क्षेत्रों में अनेक नीतिगत सार–पत्रों या पॉलिसी ब्रीफ का योगदान दिया है।

आरआईएस ने बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय प्रणालियों पर व्यापक चर्चा के लिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) के सहयोग से 2021 में एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। इस श्रृंखला के तहत विभिन्न विषयों पर कुल छह वेबिनार (वित्त वर्ष 2020–21 में तीन और वित्त वर्ष 2021–22 में तीन) आयोजित किए गए। इनमें कई जाने–माने विशेषज्ञों ने समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से विचार मंथन किया। 23 अप्रैल, 2021 को आयोजित "बैंक, वित्त और प्रौद्योगिकी के बदलते स्वरूपः फिनटैक के साथ नए विकल्प'' पर वेबिनार में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ऋण, खुदरा भुगतान आदि में फिनटेक समाधानों की रेंज के अनुप्रयोग को शामिल किया गया। वेबिनार ने वित्तीय समावेशन, एसएमई ऋण आदि जैसे फिनटेक अनुप्रयोगों के कई आशाजनक क्षेत्रों की पहचान की। सुश्री उषा थोराट, पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में "बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की भूमिकाः महामारी की चुनौतियों से निपटना'' पर एक समर्पित सत्र आयोजित किया गया, जिसमें महामारी के दौरान बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने, ऋण चुकौती को कुछ समय के लिए स्थगित करने और एमएसएमई क्षेत्रों को कार्यशील पूंजी की सहायता प्रदान करने जैसी समय पर की गई कार्रवाइयों पर चर्चा की गई। श्रृंखला का अंतिम वेबिनार भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन द्वारा "लचीली वित्तीय प्रणाली और शासन'' विषय पर दिए गए व्याख्यान पर केंद्रित रहा। सेमिनार उभरती प्रौद्योगिकियों, जोखिम प्रबंधन ढांचे और विकसित होती शासन संरचनाओं पर केंद्रित रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर, और सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र (सीएसईपी) के अध्यक्ष डॉ. राकेश मोहन ने सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए इस विषय पर अपने विचार साझा किए। वेबिनार श्रृंखला में हुआ विचार–विमर्श निष्कर्ष दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

पिछले वर्ष की गई उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, वित्त क्षेत्र से संबंधित कई शोध अध्ययन वर्तमान में अपने विभिन्न चरणों में हैं। आरआईएस आईएसआईडी, नई दिल्ली और जीआईएफ़टी, तिरुवनंतपुरम के साथ मिलकर एसेक्स यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन के सहयोग से फिनटेक पर एक अध्ययन कर रहा है। वर्तमान में जिन शोध पत्रों पर अनुसंधान चल रहा है, उनमें फिनटेक कॉरिडोर, ग्रीन फाइनेंस आदि शामिल हैं।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

मत्स्य सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ में चर्चाएंः मुद्दे, संभावनाएं एवं आगे की राह

डब्ल्यूटीओ ने अपने सदस्य देशों के लिए 'स्पष्ट एवं पूर्ण' मत्स्य पालन वार्ता का मूल पाठ अपने–अपने व्यापार मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 जुलाई की समय सीमा तय की है, ताकि उन्हें कोई समझौता करने में मदद मिल सके। हालांकि, उससे ठीक पहले विशेषज्ञों ने भारत सहित विकासशील देशों से संसाधनों के मामले में गरीब एवं कम आय वाले मछुआरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

29 मई 2021 को 'मत्स्य सब्सिडी और डब्ल्यूटीओ में चर्चाएंः मुद्दे, संभावनाएं एवं आगे की राह' विषय पर आयोजित वेबिनार में डॉ. मुकेश भटनागर, प्रोफेसर, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहा कि भारत 'विशेष और अलग व्यवहार (एसडीटी)' व्यवस्था का उपयोग करने पर विचार कर रहा है, ताकि संसाधनों के मामले में गरीब एवं कम आय वाले मछुआरों, अथवा मछली पकड़ने की आजीविका के साथ–साथ विकासशील देशों की अपनी–अपनी क्षेत्रीय समुद्री जल सीमा (तटीय देशों के तटों से 12 समुद्री मील) में मछली पकड़ने से संबंधित उनकी गतिविधियों को 'गैर–सूचित और गैर–नियंत्रित ढंग से मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध' से छूट के जरिए संरक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके।

विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए वार्ता संबंधी हालिया मसौदा पाठ में एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए उनके तट से 12 समुद्री मील के भीतर गैर–कानूनी, गैर–सूचित और गैर–नियंत्रित (आईयूयू) मछली पकड़ने (उनके गरीब मछुआरों की मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों हेतु) के लिए सब्सिडी पर प्रतिबंध से छूट को दो साल की समयावधि (जिस तारीख से अंतिम समझौता लागू होगा) में समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

मसौदा पाठ के अनुसार, लागू समयावधि के रूप में दो वर्ष से इस प्रावधान पर चर्चा शुरू की जा सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों ने कहा कि मसौदा पाठ में ऐसे कई बिंदु हैं (सब्सिडी पर प्रतिबंध से छूट के लिए इस समयसीमा से जुड़े बिंदु के साथ–साथ 'पारंपरिक ढंग से मछली पकड़ने' की परिभाषा सहित) जिन पर सदस्य देशों द्वारा अभी तक अपनी सहमति नहीं दी गई है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, 'वर्ष 2017 में ब्यूनस आयर्स में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य 14.6 के अधिदेश के तहत वार्ताकारों को आईयूयू मछली पकड़ने के लिए दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने और उन कुछ खास मत्स्य सब्सिडी को प्रतिबंधित करने के विषयों पर समझौता करने का काम दिया गया है जिनसे मछली पकड़ने की अत्यधिक क्षमता हासिल करने, और अत्यधिक मछली पकड़ने को काफी बढ़ावा मिलता है। वहीं, एसडीटी इन वार्ताओं का एक अभिन्न अंग है।'

पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में पूर्व सचिव श्री तरुण श्रीधर ने कहा कि यह वाजिब सवाल है कि क्या विश्व व्यापार संगठन मत्स्य पालन संबंधी वार्ता, विशेषकर 'अत्यधिक मछली पकड़ने' की परिभाषा जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए उपयुक्त निकाय है, जबकि इस उद्देश्य के लिए अन्य विशेष एजेंसियां हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ मुख्य रूप से टैरिफ यानी शुल्क से जुड़े मुद्दे पर गौर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सहित विकासशील देशों के पास विभिन्न अधिसूचनाओं का पालन करने और इन वार्ताओं में प्रभावकारी ढंग से भाग लेने के लिए पर्याप्त क्षमता या व्यवस्था नहीं है। श्रीधर ने नियमों को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा किया जैसे कि यह निर्धारित करना कि मछली पकड़ने की एक छोटी नाव ने मछली पकड़ने के लिए 12 समुद्री मील की दूरी वाली तय सीमा को पार कर लिया है या नहीं।

प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस ने विकासशील देशों के लिए और भी अधिक लचीलेपन वाले कुछ विकल्प प्रस्तावित किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि एलडीसी को 12 समुद्री मील की तय सीमा के भीतर छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर प्रतिबंध से पूर्ण छूट दी जा सकती है, और इस तरह की सब्सिडी को समाप्त करने के लिए विकासशील देशों के लिए लंबी समयावधि (उदाहरण के लिए 7–10 वर्ष) तय की जा सकती है। सुश्री रांजा सेनगुप्ता, वरिष्ठ शोधकर्ता, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क ने कहा कि विकासशील देशों के लिए बनाई गई एसडीटी व्यवस्था को विकसित देशों द्वारा पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी लक्ष्य 14.6 में एसडीटी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है (इसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि वर्ष 2020 तक सदस्य देशों को उन कुछ खास मत्स्य सब्सिडी को प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिनसे मछली पकड़ने की अत्यधिक क्षमता हासिल करने, और अत्यधिक मछली पकड़ने को काफी बढ़ावा मिलता है; उन सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए जिनसे आईयूयू मछली पकड़ने को काफी बढ़ावा मिलता है और ठीक इसी तरह की नई सब्सिडी शुरू करने से बचना चाहिए, यह मानते हुए कि विकासशील देशों और एलडीसी के लिए उपयुक्त एवं प्रभावकारी एसडीटी व्यवस्था को विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य सब्सिडी संबंधी वार्ता का एक अभिन्न अंग होना चाहिए)।

अखिल भारतीय मत्स्य मजदूर महासंघ के श्री पी. जयप्रकाश ने कहा कि जितनी 'जल्दबाजी' में डब्ल्यूटीओ वर्चुअल प्रारूप में 'पर्याप्त पारदर्शिता के बिना' ही वार्ताएं आयोजित कर रहा है और जिस तरह से खासकर ऐसे समय में जल्द ही वार्ता समाप्त करने के लिए सदस्य देशों पर 'भारी दबाव' डाला जा रहा है जब विकासशील देशों को कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट से उबरना मुश्किल हो रहा है, उसके मद्देनजर यह सब कुछ निश्चित तौर पर 'अलोकतांत्रिक' है। वर्चुअल वार्ताओं में प्रभावकारी रूप से भाग लेने में विकासशील देशों द्वारा सामना की जा रही बाधाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

विश्व व्यापार संगठन को महामारी पर काबू पाने के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने तक मत्स्य पालन संबंधी वार्ताओं को तत्काल स्थगित कर देना चाहिए।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि एसडीटी प्रावधानों का उपयोग करने और डब्ल्यूटीओ द्वारा सब्सिडी संबंधी नियम बनाने की दृष्टि से मत्स्य पालन संबंधी वार्ताएं निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री राजीव खेर, प्रतिष्ठित फेलो, आरआईएस एवं भारत के पूर्व वाणिज्य सचिव ने कहा कि मत्स्य पालन संबंधी वार्ताओं से विश्व व्यापार संगठन को बहुपक्षवाद में नई जान फूंकने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन वार्ताओं के दौरान प्रति व्यक्ति ज्यादा जीडीपी वाले कुछ खास विकासशील देशों और संसाधनों की भारी कमी से जूझ रहे बाकी विकासशील देशों के बीच किस तरह से अंतर करने का प्रयास किया जाएगा। ■

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की भूमिकाः महामारी की चुनौतियों पर काबू पाना

आरबीआई को विशेषकर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित महंगाई दर और कोर डब्ल्यूपीआई महंगाई दर में निरंतर हो रही वृद्धि के साथ–साथ आर्थिक विकास पर फोकस करते हुए कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी जून माह की अपनी मौद्रिक नीति में विकास और महंगाई के बीच बड़ी सावधानी से उचित संतुलन बनाने की 'बड़ी चुनौती' का सामना करना पड़ेगा। आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर सुश्री उषा थोराट ने यह बात कही है।

आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 21 मई 2021 को 'बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की भूमिकाः महामारी की चुनौतियों पर काबू पाना' विषय पर आयोजित वेबिनार में सुश्री थोराट ने कहा, 'हम देख रहे हैं कि जिंसों (कमोडिटी) की कीमतों पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूपीआई के साथ–साथ कोर महंगाई भी बढ़ रही है। हम (कोविड–19) दूसरी लहर के प्रभाव और विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति एवं मांग में भारी कमी को लेकर भी काफी चिंतित हैं। अतः मुझे लगता है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति संबंधी अगले विचार–विमर्श के दौरान बड़ी सावधानी से इस तरह का उचित संतुलन बनाने की बात स्पष्ट रूप से सामने आएगी।' सुश्री थोराट, जो वर्तमान में फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की अध्यक्ष हैं, इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से जुड़े अपने रुख या नजरिए पर पुनर्विचार करना चाहिए। डब्ल्यूपीआई आधारित महंगाई दर कुछ खाद्य उत्पादों, ईंधन, खनिज और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण मार्च के 7.4 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में पिछले 11 वर्षों के उच्चतम स्तर 10.5 प्रतिशत को छू गई थी। हालांकि, खुदरा महंगाई दर अप्रैल में गिरकर पिछले तीन महीनों के न्यूनतम स्तर 4.3 प्रतिशत पर आ गई थी।

उन्होंने बताया कि इससे पहले यह होता था कि बैंकिंग प्रणाली में मौजूद अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए आरबीआई अपने समायोजन या सरल रुख से पीछे हट जाया करता था, लेकिन पिछली मौद्रिक नीति में देश में धीमे आर्थिक विकास को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। सुश्री थोराट ने कहा, 'कोई भी उन संकेतों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता है जो वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू हालात से आ रहे हैं। यही कारण है कि हमें स्पष्ट रूप से यही नजर आ रहा है कि जून में पेश की जाने वाली मौद्रिक नीति में बड़ी सावधानी से उचित संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने जीडीपी आउटलुक को किस हद तक बदलने जा रहे हैं, जिसे 10.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आउटलुक को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इन दोनों आउटलुक के आंकड़ों, जो हर मौद्रिक नीति में पेश किए जाते हैं, को इस आधार पर बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि आरबीआई के पास किस तरह की जानकारी है।

इस अवसर पर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, और सदस्य, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आरबीआई ने कहा कि महंगाई लक्ष्य (4 प्रतिशत, जिसमें +/–2 प्रतिशत की गुंजाइश है) 'उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर एक साधन या माध्यम होगा, जो विकास और प्रगति है।' उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आरबीआई के 50,000 करोड़ रुपये के तरलता पैकेज की हालिया घोषणा और वित्त मंत्रालय द्वारा महंगाई के रुख को कम करने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक मंडल के चेयरमैन श्री मनीष सभरवाल ने कहा कि ऋण की उपलब्धता दरअसल ऋण की लागत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, '"सरकार और आरबीआई (महंगाई को कम करने पर) के बीच वास्तव में शायद ही कोई विवाद है। महंगाई आने वाले समय के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है। यह गरीबों पर सबसे बड़ा टैक्स है। दरअसल यह लड़ाई (सरकार और आरबीआई के बीच) खत्म हो गई है कि किसी को महंगाई पसंद है और किसी को नहीं। महंगाई किसी को भी पसंद नहीं है। यह केवल आम लोग ही हैं जो इस कठिन पल को किसी तरह गुजारते हैं और जो इसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं।' सुश्री दक्षिता दास, अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड एवं पूर्व प्रबंध निदेशक, नेशनल हाउसिंग बैंक और श्री संग्राम सिंह, ईवीपी एवं प्रमुख (वाणिज्यिक बैंकिंग कवरेज समूह), एक्सिस बैंक ने उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया जो अंततः कर्ज विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए महामारी के बाद होने वाली आर्थिक बेहतरी में निभाएगा और इसके साथ ही उन्होंने उधारी के उस अपेक्षित मार्ग के बारे में बताया जिन्हें बैंकों और एनबीएफसी द्वारा शुरू किए जाने की उम्मीद है। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

एशिया की महामारी के बाद की व्यवस्था और एकीकरणः आसियान का दृष्टिकोण पर इंडो–पेसिफिक

आसियान अध्ययन केंद्र, चुलालगकोन विश्वविद्यालय, बैंकॉक; समकालीन साउथ ईष्ट एशिया अनुसंधान संस्थान, बैंकॉक; और आसियान–भारत केंद्र, आर आई एस द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें महामारी के बाद की व्यवस्था का एकीकरण और आसियान का इंडो पेसिफिक पर दृष्टिकोण दिनांक 8 और 9 जुलाई 2021 को किया गया। दो दिवसीय सम्मेलन में छः तकनीकी सत्र शामिल थेः दक्षिण पूर्व एशिया और भारत और चीन द्वारा एशिया की परिकल्पना और क्षेत्रीय इंडो–पेसिफिक व्यवस्था; इंडो–पेसिफिक दक्षिण पूर्व एशिया के परिपेक्ष्य में; केन्द्रीयता और बहुपक्षता डांवाडोल परिस्थिति में; भू–राजनीति इंडो–पेसिफिक में; महामारी के बाद के एशिया में एकीकरण; आसियान में एकिकरण और सम्पर्क सम्बन्ध की चुनौतियाँ; इंडो–पेसिफिक का क्या अर्थ है; इंडो–पेसिफिक में सुरक्षा व सामरिक चुनौतियाँ। भारत प्रशांत क्या है, इस विषय पर आसियान में प्रतिस्पर्धी संयोजक रणनीतिक और एकीकरण चुनौतियां पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही साथ एशिया मे महामारी के पश्चात एकीकरण पर भी वार्ता हुई। ■

सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली और गवर्नेंस

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉ. महेश कुमार जैन

जब तक पारंपरिक वित्तीय कंपनियां नवीनतम तकनीकों को अपनाकर और तकनीकी सुदृढ़ता दिखाते हुए स्वयं को बिजनेस करने के नए तौर–तरीकों के अनुकूल नहीं बना देती हैं, तब तक उन्हें उन बिग टेक और अभिनव फिनटेक कंपनियों द्वारा जल्द ही हाशिए पर डाल दिए जाने की प्रबल आशंका है जो वित्तीय लेन–देन में क्रांति ला रही हैं। यह बात आरबीआई के डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन ने कही।

आरआईएस और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से 18 जून 2021 को 'सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली और गवर्नेंस' विषय पर आयोजित वेबिनार में श्री जैन ने कहा, 'प्रौद्योगिकी दरअसल वित्तीय प्रणाली के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में क्रांति ला रही है।' उन्होंने यह भी कहा, 'प्रौद्योगिकी पर वित्तीय संस्थानों की निर्भरता बढ़ती ही जा रही है और प्रौद्योगिकी सुदृढ़ता को अब वित्तीय सुदृढ़ता जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है, भले ही यह उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो।' हालांकि, श्री जैन ने वित्तीय प्रणाली में विविधता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया जिसके तहत विभिन्न कंपनियों को अलग–अलग बिजनेस मॉडल को अपनाना चाहिए, भले ही वे बिजनेस करने के नए तौर–तरीकों को अपना लें। उन्होंने कहा, 'एक जैसी वित्तीय प्रणाली कम सुदृढ़ होगी और अंतर्निहित आर्थिक स्थितियों में बदलाव आने पर प्रणालीगत संकट का अंदेशा रहेगा।'

एक प्रमुख कारक के रूप में सुशासन की रूपरेखा, जो किसी भी कंपनी की सुदृढ़ता को बढ़ा देती है, का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नेंस की गुणवत्ता दरअसल गवर्नेंस के स्वरूप और संस्कृति पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा, 'वैसे तो सरकार या आरबीआई के लिए किसी बैंक के भीतर गवर्नेंस के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए कानून/नियम बनाना संभव है, लेकिन उचित कार्य–संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसके लिए कानून नहीं बनाया जा सकता है। बैंकों और बोर्डों को ही संबंधित संगठनों के भीतर अपेक्षित कार्य–संस्कृति विकसित करनी होगी।'

गवर्नेंस की रूपरेखा के संदर्भ में मुआवजे की नीतियों के महत्व पर श्री जैन ने कहा, 'जब किसी मुआवजा या क्षतिपूर्ति व्यवस्था के तहत दीर्घकालिक जोखिम या नकारात्मक बाह्य कारकों पर विचार किए बिना ही अल्पकालिक जोखिम लेने को पुरस्कृत किया जाता है, तो वैसी स्थिति में संबंधित संस्थानों की सुदृढ़ता के साथ–साथ प्रणालीगत सुदृढ़ता भी खतरे में पड़ सकती है। इसके साथ ही अपर्याप्त मुआवजा मिलने की स्थिति में विभिन्न झटकों का अनुमान लगाने, उन्हें झेलने और उनके अनुकूल बनने के लिए वित्तीय संस्थान की क्षमता विकसित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के शीर्ष/वरिष्ठ प्रबंधन को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन नहीं मिलने का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।'

इस अवसर पर डॉ. राकेश मोहन, पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई एवं प्रतिष्ठित फेलो, सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र ने आरबीआई द्वारा डूबते ऋणों के वास्तविक स्तर या संभावित एनपीए पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, भले ही महामारी से उत्पन्न मौजूदा संकट के कारण नियामकीय ढील/ऋण स्थगन आवश्यक क्यों न हो गया हो। उन्होंने कहा कि इससे नियामकीय ढील/ऋण स्थगन हटने के बाद किसी भी स्थिति के लिए आकस्मिक योजना बनाने में मदद मिलेगी। डॉ. मोहन ने निकट भविष्य में दिवाला और दिवालियापन संहिता से संबंधित मामलों की भरमार हो जाने की संभावना पर भी चिंता व्यक्त की।

प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस एवं शासी बोर्ड के सदस्य, आरबीआई ने कहा कि आरबीआई ने नियामक की ओर से नई पहल करने और नई तकनीकों को अपनाने के लिए 'उत्कर्ष' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। हालांकि, संबंधित चुनौतियों में वित्तीय

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

कंपनियों और फिनटेक की भरमार होने के साथ–साथ हरित वित्त तक अधिक–से–अधिक पहुंच के जरिए हरित रिकवरी सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है।

बिजनेस स्टैंडर्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अशोक भट्टाचार्य ने सरकार एवं वित्तीय प्रणाली के बीच संबंधों पर और भी अधिक स्पष्टता की आवश्यकता के साथ–साथ वित्तीय क्षेत्र में परस्पर जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए शीर्ष स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद को मजबूत करने के विशेष महत्व के बारे में बताया। श्री एन.एन. वोहरा, अध्यक्ष, आईआईसी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। ■

व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करना: लोच, समावेशन और सतत्वा

व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करना: लोच, समावेशन और सतत्वा पर संवाद 20 जुलाई 2021 को हुआ। प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आर आई एस ने स्वागत भाशण में टिप्पणी प्रस्तुत की। आचार्य मनोज पंत, निदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। परिचर्चा में शामिल थे: डॉक्टर टरीडी ह्ट्जेनबगृ, दक्षिण अफ्रीका; सुश्री ओलगास पोनोमेरवा, रूस ने चर्चा में भाग लिया। डॉक्टर निशा तनेजा, भारत; और डॉक्टर सुश्री झांग चुआनहोग, चीन, डॉ सब्यसाची साहा, सहभागी आचार्य, आर आई एस, भारत, ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।■

एमएसएमई को बढ़ावा देने पर भारत–नाइजीरिया वेबीनार

एम एस एम ई का औद्योगीकरण के लिए बढ़ावा देने पर 14 जुलाई 2021 को विशेष वैबिनार का आयोजन हुआ। आर आई एस, नाइजीरिया सेना संसाधन संस्थान तथा नाइजीरिया में भारत का दूतावास ने इसका संयुक्त आयोजन किया। आचार्य सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। श्री अभय ठाकुर, भारत के नाइजीरिया उच्चायुक्त ने आरंभिक टिप्पणि की। मेजर जनरल (सेवानिर्वृत्त) श्री गरबा अयोदजी वहाब, महानिदेशक, नाइजीरिया सेना संसाधन संस्थान, नाइजीरिया ने विशेष टिप्पणी प्रस्तुत की। पहला सत्र भारत में एमएसएमई चुनौतियां और आगे का रास्ता एवं दूसरा सत्र नाइजीरिया में एमएसएमई क्षेत्र पर था। वक्ताओं में शामिल थे, प्रोफेसर एम. एच. बाला सुब्रमण्यम, प्रबंधन अध्ययन विभाग, भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर; आचार्य एस. के. मोहंती, आर आई एस; श्री जोसेफ ओलाटायो ओमिडीजी , डिप्टी महाप्रबंधक और प्रमुख सामरिक योजना विभाग नेक्सिम बैंक और श्री उद्येमी फोलोरुशो नाइजीरिया। डॉ पंकज वशिष्ठ आर आई एस, ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।■

दक्षिण एशिया में कृषि और खाद्य प्रणालियों का प्रदर्शन

कोविड–19 महामारी गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव ने खाद्य प्रणालियों को बाधित कर दिया। साथ ही साथ इस संकट ने आजीविका कमाने की परेशानी को भी बढ़ा दिया। महामारी प्रतिक्रियाओं ने भी प्रदर्शित किया है कि अच्छी तरह से तैयार की गई नीतियों की शक्ति से बड़े से बड़े झटकों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है जिसमें सशक्त तथा लचीली खादय प्रणाली शामिल है। इन सबकी चर्चा खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 में विस्तार से की गई है। इस पर विचार विमर्श के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशिया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और आर आई एस ने 8 जुलाई 2021 को एक बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट वक्ता थे:– डॉ बिनायक सेन, डॉ दुशनी वीराकून, डॉ जोहन स्वीनेन, डॉ त्रिलोचन मोहापात्रा, डॉ पी. के. आनन्द, डॉ स्वर्निम वागले एव डॉ शाहीदुर राशिद, निदेशक, इफपरि, दक्षिण एशिया।

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

एमसी–12 के स्थगन से अधिक काम की गुंजाइश बढ़ी

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट (डब्लयू) 2021 के उद्‌भघाटन के बाद 27 नवंबर, 2021 को आरआईएस द्वारा आयोजित एक वेबिनार में प्रमुख वक्ता।

ओमीक्रोन के प्रसार के कारण, वेबिनार शुरू होने से पहले ही एमसी–12 को स्थगित करने की घोषणा की खबर आ चुकी थी। लेकिन वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के स्थगन का उपयोग भारत को दक्षिण के साथ जुड़ने के लिए करना चाहिए। वैश्विक दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार, विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–12) के स्थगन के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहिए और इसके फिर से आयोजित होने तक के समय का अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहिए। एमसी–12 (30 नवंबर – 3 दिसंबर, 2021 के लिए निर्धारित) को स्थगित करने का निर्णय विश्व व्यापार संगठन सामान्य परिशद द्वारा कोविड–19 वायरस के एक विशेष रूप से संक्रमणीय स्ट्रेन के प्रकोप के बाद लिया गया था।

वेबिनार में बोलते हुए, प्रोफेसर कार्लोस कोरिया, कार्यकारी निदेशक, दक्षिण केंद्र, जिनेवा, ने कहा कि दक्षिण केंद्र और आरआईएस जैसे विकासशील देशों के विचार मंडलों को सभी प्रस्तावों का विश्लेषण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एमसी12 के स्थगन से मत्स्य पालन सब्सिडी, कृषि, ट्रिप्स छूट और विशेष तथा विभेदी व्यवहार सहित विभिन्न मुद्दों पर विकासशील देश की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

प्रौद्योगिकी और व्यापार एक–दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इस बात को डब्लूटीडीआर द्वारा कितना महत्व दिया जा रहा है का उल्लेख करते हुए प्रो कौरिया ने कहा कि इस मुद्दे को, जो हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया है, विशेष रूप से कोविड पश्चात के परिदृष्य में जिस प्रकार डिजिटलीकरण में तेजी देखी गई, ।

आरआईएस के अध्यक्ष, डॉ मोहन कुमार ने कहा कि विकासशील देशों को एमसी–12 के स्थगित होने के कारण सामने आए अवसरों और चुनौतियों को देखते हुए एक साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'किसी भी कीमत पर एमसी–12 की सफलता' सुनिष्चित करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि 'सफलता' पर केवल विकसित दुनिया का कब्जा हो जाए और विकासशील देश मात्र इसकी कीमत चुकाने के लिए रह जाएं।

विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत श्री जयंत दासगुप्ता ने कहा कि एमसी–12 को स्थगित करने से विकासशील देशों को ऐसे प्रस्तावों के विरुद्ध, जो उनके हितों के खिलाफ हैं, मजबूती से अपनी बात रखने के लिए तैयार होने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को सतत्ता और जातीयता जैसे मुद्दों पर सफाई देनी होगी जिनके माध्यम से वे परोक्ष रूप से विकासशील देशों के बाजार में पहुंच हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

डॉ नागेश कुमार, निदेशक, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, ने भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा ट्रिप्स छूट पर प्रस्ताव के महत्व का उल्लेख किया और कहा कि विश्व व्यापार संगठन को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि विकासशील देशों में अरबों गरीब लोगों के जीवन की सुरक्षा कोविड वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट और दवाइयाँ विकसित करने वाली कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निचली पंक्ति की सुरक्षा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए निवेश सुविधा पर चर्चा से निवेशकों, अपने देश और मेजबान देश के अधिकारों और जिम्मेदारियों में संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे प्रमुख विकासशील देशों को निवेश सुविधा सहित बहुपक्षीय देशों का हिस्सा होना चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका परिणाम विकासशील देशों के हितों के खिलाफ नहीं है।

आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, ने कहा कि विकासशील देशों के गठबंधनों को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दक्षिण एमसी–12 के विभिन्न मुद्दों पर एक एकजुट इकाई के रूप में बना रहे, जिसमें संयुक्त वक्तव्य पहल भी शामिल है। यह सुनिश्चित भी हो सके कि राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने में विकासशील देश के सरकार द्विपक्षीय संवाद नीति के अवसर से वंचित ना कर रहे। उन्होंने कहा कि व्यापार घरेलू उत्पादन और घरेलू विकास के लिए उत्प्रेरक होना चाहिए न कि केवल अधिक आयात के लिए। भारत को डब्लूटीओ मंत्रिस्तरीय के स्थगन का उपयोग दक्षिण के साथ जुड़ने के लिए करना चाहिए। आरआईएस के प्रो एस. के. मोहंती और डॉ पंखुरी गौर ने डब्लूटीडीआर का विवरण प्रस्तुत किया। और डॉ सब्यसाची साहा, आरआईएस ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

द्विपीक्षीय व्यापार

प्रथम भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता

आरआईएस, भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) और कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (केआईईपी) ने 27 अक्टूबर 2021 को उभरती क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पनाः 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी और न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर पहली भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन सत्र से हुई। राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्लूए; प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ. होंग ह्यूनिक, चांसलर, केएनडीए; डॉ. किम ह्युंगचोंग, अध्यक्ष, केआईईपी; राजदूत चांग जे–बोक, भारत में दक्षिण कोरियाई राजदूत; और कोरिया गणराज्य में भारतीय राजदूत, राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने संवाद को संबोधित किया।

राजदूत नलिन सूरी, विशिष्ट फेलो, दिल्ली पॉलिसी ग्रुप ने बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ में भारत–कोरिया संबंधः सामरिक दृष्टिकोण पर सत्र की अध्यक्षता की। वक्ताओं में डॉ चो वोंडुक, अनुसंधान प्रोफेसर (केएनडीए); और डॉ जगन्नाथ पांडा, रिसर्च फेलो, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली (एमपी–आईडीएसए) शामिल थे। डॉ जोजिन वी जॉन, रिसर्च फेलो, आईसीडब्ल्यूए; और डॉ पाइक वूयल, एसोसिएट प्रोफेसर, योन्सी विश्वविद्यालय ने परिचर्चा में भाग लिया।

कोविड–19 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को पुनर्संदर्भित करने वाले सत्र की अध्यक्षता सेंटर फॉर एरिया स्टडीज, केआईईपी, के उपाध्यक्ष डॉ चो चोंगजे ने की। प्रोफेसर एस. के. मोहंती, आरआईएस; और डॉ. हान ह्योंगमिन, एसोसिएट रिसर्च फेलो, केआईईपी, प्रमुख वक्ता थे। चर्चा में भाग लेने वाले थेः डॉ ली सून–चुल, प्रोफेसर, बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस।

कोरिया गणराज्य के पूर्व भारतीय राजदूत स्कंद तायल ने आगे की राहः भारत–कोरिया द्विपक्षीय संबंध पर सत्र की अध्यक्षता की। वक्ता थेः डॉ किम चानवान, प्रोफेसर, हांकुक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और डॉ जितेंद्र उत्तम, सहायक प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

समापन सत्र में चर्चा में शामिल थेः डॉ किम ह्यूंगचोंग, अध्यक्ष, केआईईपी; डॉ. होंग ह्यूनिक, चांसलर, केएनडीए; प्रो. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; और राजदूत विजय ठाकुर सिंह, महानिदेशक, आईसीडब्ल्यूए। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

महामारी के बाद भारत–अफ्रीका संबंधों पर चर्चा

हाइब्रिड मोड में चल रही गोलमेज चर्चा।

ओस्लो विश्वविद्यालय, नॉर्वे के सहयोग से आरआईएस ने 9 दिसंबर, 2021 को महामारी के बाद की दुनिया में भारत–अफ्रीका संबंध पर हाइब्रिड मोड में चर्चा का आयोजन किया। उद्देश्य था भारत–अफ्रीका संबंधों के भविष्य का आकलन करना। स्वास्थ्य, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण, पारंपरिक चिकित्सा, आदि के क्षेत्रों में समग्र विदेश नीति अभिविन्यास और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित यह चर्चा दो सत्रों में हुई।

अपने स्वागत भाषण में प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस ने भारत–अफ्रीका संबंधों के प्रमुख मील के पत्थर और साथ ही, उनकी विकास साझेदारी में हाल के रुझानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत आज विकास और अवसंरचना परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए अधिक उत्सुक है। प्रगति की निगरानी की पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है। उन्होंने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में विकास सहयोग की सुविधा के लिए भारत की विकास एजेंसी स्थापित करने का भी सुझाव दिया। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डैन बानिक ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की पिछली नीति से अब बड़ा परिवर्तन आया है। हाल के दिनों में अधिक ऊंचे दर्जे के दौरे हुए हैं। भारत और अफ्रीका के बीच रक्षा सहयोग भी विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश नीति का आदर्शवाद से अधिक व्यावहारिकता की ओर झुकाव बदलाव का एक प्रमुख पहलू है।

भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (ईआर) श्री दम्मू रवि ने अपनी विशेष टिप्पणी में कहा कि भारत के लिए अफ्रीका के साथ सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। अफ्रीका के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित करते हुए श्री रवि ने कहा कि वर्तमान में नई दिल्ली स्वास्थ्य, नवीकरणीय और आईटी–वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा रही है। भारत ने कोविड के टीकों के अलावा अफ्रीकी देशों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है और भविश्य में भी सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन में अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को गहरा करने की भी गुंजाइश है। अफ्रीका में व्यापार की स्थिति उतनी ठीक नहीं है। आज अफ्रीका केवल कच्चे माल का निर्यात ही नहीं, विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है। इसलिए, भारत अफ्रीकी देशों के सहयोग से वहां विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना चाहेगा। श्री रवि ने कहा कि भारत अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन के साथ त्रिकोणीय सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है।

चर्चा में स्वास्थ्य और फिनटेक के क्षेत्रों में भारत–अफ्रीका सहयोग पर व्यापक रूप से विचार साझा किए गए। सहभागियों ने यह भी उल्लेख किया कि कृषि क्षेत्र भी भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग के अवसर प्रदान करता है।

यह भी सुझाव दिया गया कि भारत को अफ्रीका में यूरोपीय देशों के साथ, उनके औपनिवेशिक शासन के कारण, सहयोग विकसित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। चर्चा में यह भी कहा गया कि अफ्रीका में बहुत विविधता है, इसलिए भारत को अपनी अफ्रीका नीति को गैर–महाद्वीपीय बनानी चाहिए। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 का लोकार्पण

आरआईएस ने विश्व व्यापार संगठन (डबलूटीओ) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सन्मुखः मुद्दे विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट के विमोचन पर 25 नवंबर 2021 को एक कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण से हुआ। आरआईएस के अध्यक्ष, डॉ मोहन कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री श्यामल मिश्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया।

25 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में विष्व व्यापार और विकास रिपोर्ट का लोकार्पण

आरआईएस के प्रोफेसर एस के मोहंती, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ प्रियदर्शी दाश और सहायक प्रोफेसर, डॉ पंखुरी गौर ने डब्लयूटीडीआर के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रस्तुति की। उसके बाद परिचर्चा में, श्री जयंत दासगुप्ता, विश्व व्यापार संगठन के पूर्व राजदूत; श्री अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच; प्रोफेसर अभिजीत दास, प्रमुख, विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र, आईआईएफटी; और डॉ. निशा तनेजा, प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर ने अपने विचार साझा किए। डॉ सब्यसाची साहा, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

भारत में जीवीसी विकसित करनाः भारत में ताइवान के निवेश को बढ़ाना

कोविड–19 महामारी ने वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की भेद्यता को उजागर किया, जो कि उच्च श्रम शक्ति की आवश्यकताओं के कारण उद्योगों को विवश करती है, जैसे कि विनिर्माण उद्योग उत्पादन बंद करने के लिए विवश थे। तालाबन्दी के चरणों के दौरान महामारी का प्रभाव और भी बढ़ गया था, जिसने औद्योगिक क्षेत्रों में मंदी को उत्प्रेरित किया। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अधिक हानिकारक थी, जिनकी जीडीपी में, सरकार के अनुमान के अनुसार, 2020–21 में 7.3 प्रतिशत की कमी आई, जबकि दुनिया में –3.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसलिए, वैक्सीन उपलब्धी और आर्थिक सुधार में वृद्धि के साथ–साथ जीवीसी के क्षेत्रों और संभावित भौतिक क्षेत्रों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उत्पादों पर भारत और ताइवान के लंबे आपूर्ति श्रृंखला सहयोग के आधार पर, 'भारत में जीवीसी विकसित करनाः भारत में ताइवान के निवेष को बढ़ाना' विषय पर वेबिनार, जो कि 9 दिसंबर, 2021 को हुआ, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के मुद्दे पर केंद्रित था। विषयों में शामिल थे (1) इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में ताइवान के अनुभव; (2) इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी क्षेत्रों और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) उद्योगों के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण और वर्तमान विकास; और (3) प्रौद्योगिकी उद्योग आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत–ताइवान सहयोग – सरकारों की भूमिकाएं और व्यावसायिक दृष्टिकोण। यह अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोविड–19 महामारी और वैश्विक आर्थिक उथल–पुथल से निपटने में प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग पर भारत और ताइवान के बीच समझ को गहरा करेगा। भारत और ताइवान के बीच संवाद में वृद्धि और भविष्य में दोनों देशों के घनिष्ठ व्यापार भागीदार बनने से दोनों पक्षों को लाभ होगा।

प्रतिभागियों में शामिल थेः प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; डॉ चुआंग–चांग चांग, अध्यक्ष, चुंग–हुआ आर्थिक अनुसंधान संस्थान (सीआईईआर), ताइवान; डॉ क्रिस्टी सुन त्जु, सू, निदेशक, सीआईईआर; डॉ षिन–हॉर्नग, चेन, रिसर्च फेलो, निदेशक, द सेकेंड रिसर्च डिवीजन, चुंग हुआ इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक रिसर्च, ताइवान; अश्विनी के अग्रवाल, निदेशक, अप्लाइड मटीरियल्स, भारत; राजदूत अनिल वाधवा, पूर्व भारतीय राजदूत और विशिष्ट फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ); डॉ संजीव के वार्शण्ेय, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली; डॉ चुएन–हुई, हंग, उप महा निदेशक, मार्केट इंटेलिजेंस एंड कंसल्टिंग इंस्टीट्यूट (एमआईसी), इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ताइवान। (रिकॉर्ड की गई प्रस्तुति); श्री सुनील आचार्य, उपाध्यक्ष, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन; और श्री ग्रांट कुओ, सीईओ और संस्थापक, डिजिटल डॉक्टर प्राइवेट लिमिटेड, भारत। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवां ईएएस सम्मेलन

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार और राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ), नई दिल्ली, आरआईएस, में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), और पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अध्ययन के लिए अनुसंधान केंद्र, कोलकाता के साथ साझेदारी में संकर मोड में 23–24 नवंबर, 2021 को कोलकाता में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पांचवें ईएएस सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजकों की ओर से डॉ प्रबीर डे, कैप्टन सरबजीत सिंह परमार और मेजर जनरल अरुण रॉय ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस; वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान, महानिदेषक, राश्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन; और पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, अध्यक्ष, पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय अध्ययन अनुसंधान केंद्र, कोलकाता द्वारा विशेष टिप्पणी दी गई। सुश्री मेगन जोन्स, निदेशक, क्षेत्रीय समुद्री जुड़ाव और कार्यक्रम, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामले और व्यापार विभाग (डीएफएटी), कैनबरा ने विशेष भाषण दिया। मुख्य भाषण राजदूत रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिया गया।

दो दिवसीय सम्मेलन में पांच पूर्ण सत्र थे: (1) समुद्री सुरक्षा, (2) संसाधन साझा करना, (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, महामारी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, (4) समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वें ईएएस सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र पर सूचना और संसाधनों की साझेदारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, आपदा जोखिम में कमी और महामारी प्रबंधन और आगे की राह पर एक परिचर्चा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद–प्रशांत महासागरीय पहल और इसके सात स्तंभों के महत्व पर चर्चा हुई, जिनमें इस क्षेत्र में भारत की व्यावहारिक कूटनीति को मजबूत करने की क्षमता है। आईपीओआई प्रतिभागी देशों के साझा हितों के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित है। हिंद–प्रशांत में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के अभिसरण को सुविधाजनक बनाने की तत्काल आवष्यकता है और आईपीओआई ऐसे परिदृश्य के लिए उपयुक्त है। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

बिम्सटेक में खाद्य और कृषि व्यापार

आरआईएस–आईएफपीआरआई राष्ट्रीय साझेदारों की बैठक 30 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इस बैठक में कृषि पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के संबंध में बिम्सटेक द्वारा उठाई गई महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया गया। बिम्सटेक दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है और रहेगा, हालांकि अधिकांश बिम्सटेक देशों के कृषि क्षेत्रों का अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। खाद्य और कृषि व्यापार 1995 से वास्तविक रूप से दोगुना होकर 2018 में 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। आश्चर्यजनक रूप से, उभरते हुए और विकासशील देश वैश्विक व्यापार के एक–तिहाई भाग के लिए उत्तरदायी हैं। बिम्सटेक बुनियादी सुविधाओं, विषेश रूप से खाद्य प्रसंस्करण, परीक्षण के मानकों, विपणन और लॉजिस्टिक्स संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता पर चर्चा करेगा। बिम्सटेक देशों से होने वाले खाद्य निर्यात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में, यह पिछले रुझान को उलटते हुए, नेपाल में हुए कुल व्यापारिक माल के निर्यात का 45.3 प्रतिशत था। यदि यही सिलसिला बरकरार रहा, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिम्सटेक कृषि पर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में बल दे रहा है और इसे विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। व्यापार सुविधा, व्यापार वित्तपोषण, सीमा पार भुगतान का निपटान, और अन्य कारक खाद्य और कृषि क्षेत्रों को फलने–फूलने में सहायता कर सकते हैं।

प्रतिभागियों ने बिम्सटेक लिंकेज, साझेदारियों और सहयोग के वैचारिक ढांचे पर विचार–विमर्श किया। आर्थिक आघातों, जलवायु परिवर्तन और देशों के बीच टकराव के कारण गरीबी और खाद्य असुरक्षा; गरीबी का बढ़ता अनुपात; बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण कम कमाई, बिम्सटेक की कुछ चुनौतियां हैं जबकि प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत तथा व्यापार और निवेश लाभ इसकी कुछ ताकतों में शामिल हैं। म्यांमार एकमात्र बिम्सटेक देश है जो कृषि में अग्रणी है। भारत पर्यटन, परिवहन, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद से निपटने में अग्रणी है। इसी तरह, प्रत्येक बिम्सटेक देश में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण ीय लिंकेज (एकीकृत फ्रेमवर्क) में अग्रणी क्षेत्र हैं।

बिम्सटेक देशों के बीच सहयोग के कुछ क्षेत्र हैं – जलवायु के अनुकूल एफटीए का कार्यान्वयन और जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी की सीमा, पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं पर टैरिफ और गैर–टैरिफ बाध ाओं में कमी, व्यापार और निवेश लाभ के लिए घरेलू नीति की आवश्यकता, आदि। इसका अंतिम लक्ष्य साक्ष्य–आधारित नीतिगत अंतर्दृष्टि तैयार करना है।

वैसे तो बिम्सटेक का क्षेत्रीय मॉडल अन्य क्षेत्रीय समझौतों से अलग है, लेकिन इसकी तुलना आसियान और दक्षेस (सार्क) से की गई है। दक्षेस के सदस्य देश बिम्सटेक के भी सदस्य हैं, इसलिए दक्षेस से सबक सीखे जा सकते हैं। नेपाल के विपरीत, जहां किसान बेहद वंचित हैं और उनका पक्ष भी नहीं सुना जाता, भारत की नीतियां किसानों पर केंद्रित हैं। भारत किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। कृषि व्यापार घाटा ऐसे देश के लिए खतरनाक है, जो 1970 के दशक की शुरुआत में चावल का बड़ा निर्यातक हुआ करता था। बांग्लादेश ने कृषि में काफी प्रगति की है और अब वह खाद्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। कृषि एक वैविध्यपूर्ण उद्योग है जिसमें अद्वि तीय चुनौतियां हैं। कृषि में मूल्यवर्धन कठिन है। साथ ही, व्यापार और उद्योग से अलग–थलग रहते हुए कृषि का विकास नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियों में जीडीपी को 1.6 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए एनटीबी के उन्मूलन को दिखाया गया है। टैरिफ उदारीकरण अन्य देशों की टैरिफ व्यवस्थाओं पर गौर किए बिना अधूरा है। बिम्सटेक देश व्यापारिक बाधाओं को दूर करके और संपर्क में सुधार करके एक सक्षम वातावरण बना सकते हैं। बिम्सटेक खाद्य और पोशण सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में योगदान दे सकता है। ■

व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग पर पहल

नवीनतम प्रकाशन

रिपोर्ट्स

- भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकास केस स्टडी, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- नीतिगत थिंक टैंकों के बिम्सटेक नेटवर्क (बीएनपीटीटी) की पांचवीं बैठक पर रिपोर्ट, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- भारत में नई पीढ़ी के डीएफआई: अवसर और चुनौतियां, *आरआईएस और आईआईईसी, नई दिल्ली, 2021*

- भारत में घटती बचत दर नया निधि विकल्प, *आरआईएस और आईआईईसी, नई दिल्ली 2021*

- डिजिटलीकरण और विकास: एशिया की ओर से अहम विचार, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- कोविड–19 के बाद बिम्सटेक में आर्थिक सहयोग पर दोबारा गौर करना, *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

आरआईएस के परिचर्चा पत्र

#266: विनिर्मित वस्तुओं में उद्योग के अंदर व्यापार: भारत से जुड़ी एक खास बात *द्वारा मनमोहन अग्रवाल और नेहा बेताई*

#264: जुलाई में बैठक के लिए मई के मूल पाठ से एमसी12 सबक से पहले मत्स्य सब्सिडी मुद्दे *द्वारा एस. के. मोहंती और पंखुड़ी गौड़*

#268: भारत की आयात निर्भरता औषधीय में चीन पर मुद्दे और नीति द्वारा अमित कुमार

#267: भारतीय कृषि को बाजार मुक्त करना द्वारा दमु रवि

आरआईएस का नीतिगत सार

#105 भारत इबीआरडी साझेदारी वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ता द्वारा डॉ प्रसन्ना सालीआन और श्री सुभासीस धल

अध्याय 3

व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर/समन्वयक,
आसियान–भारत केन्द्र,
आरआईएस

बहुपक्षवाद का संसाधन

विश्व के शक्ति संतुलन में आमूल–चूल बदलाव आ रहा है। उभरते रुझान भारत सहित विकासशील देशों के उच्च भू–राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव के साथ बहुध्रुवीय दुनिया की ओर इंगित कर रहे हैं। नई विश्व व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए दक्षिण के देश और आरआईएस जैसे संगठन अपने वर्क प्रोग्राम्स के माध्यम से निरंतर आधार पर अपनी स्थिति को पुनर्निर्धारित करते रहे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, उत्पादन नेटवर्क और लोगों के आपसी संपर्क को बढ़ावा मिलता है। विकास, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता और लचीलेपन के लिए कनेक्टिविटी मायने रखती है। व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग आरआईएस में एक ऐसा वर्टिकल है जो वैश्विक और क्षेत्रीय विकास रणनीतियों को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत करने में योगदान देता आया है।

महामारी के बाद के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आरआईएस के वर्क प्रोग्रामों में व्यापार सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक रेंज को शामिल किया गया। कोविड–19 महामारी के दौरान दुनिया भर के देशों को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। इसलिए कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग में लचीलेपन की आवश्यकता को अत्यधिक महत्व मिला। आज, देश एफटीए की बहुलता, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन द्वारा संचालित वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के साक्षी बने हैं। आरआईएस नजदीकी और विस्तारित पड़ोस के देशों को सहयोग के माध्यम से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में सहायता देता रहा है।

अपनी वैश्विक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, हम आरआईएस में कनेक्टिविटी को सीमाओं के भीतर और बाहर विकास के एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में देखते हैं। महामारी के दौर की अड़चनों के बावजूद, आरआईएस ने 2021–22 में अध्ययनों, सम्मेलनों, संवादों, संगोष्ठियों, वेबिनार आदि के माध्यम से कनेक्टिविटी से संबंधित गतिविधियों को उत्कृष्टता के साथ संचालित करने का सिलसिला जारी रखा तथा लेखन और प्रसार द्वारा क्रॉस–कटिंग वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर आवाज उठाई और उन्हें महत्व दिया। आरआईएस के अनुसंधान कार्यक्रम व्यापार और कनेक्टिविटी से लेकर संस्कृति और सभ्यता तक, और एकीकरण से लेकर सहयोग तक के विषयों की श्रृंखला को कवर करते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से संबद्ध किया जा सकता है: पहला, उच्च प्रभाव अध्ययन और विशेष अनुसंधान इनपुट; दूसरा, सम्मेलन, सेमिनार, संवाद और व्याख्यान श्रृंखला; और तीसरा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

प्रमुख अध्ययन

वर्ष 2021–22 में आरआईएस ने कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग पर दो प्रमुख अध्ययन कराए: (1) विकास, मांग और लोकतंत्र के लिए भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी; और (2) त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तार: पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास निहितार्थ। ये अध्ययन नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और व्यवसायियों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं।

हिंद–प्रशांत में कनेक्टिविटी सहयोग

हिंद–प्रशांत, क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग के एजेंडे को नए सिरे से आकार दे रहा है। 2019 में भारत ने हिंद–प्रशांत विजन, अर्थात् हिंद–प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) प्रस्तुत की। आईपीओआई सात स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करती हैः (1) समुद्री सुरक्षा; (2) समुद्री पारिस्थितिकी; (3) समुद्री संसाधन; (4) क्षमता निर्माण और संसाधन साझा करना; (5) आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन; (6) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग; और (7) व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन। आरआईएस को आईपीओआई के स्तंभ–7 के लिए नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया गया है। स्तंभ–7 में जापान शीर्ष कनेक्टिविटी पार्टनर है। आरआईएस ने आईपीओआई के स्तंभ–7 संबंधित जानकारी को विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया। अन्य अध्ययनों के बीच, इस अध्ययन ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने की एक रणनीति की पहचान की।

भारत और जापान दोनों का मानना है कि हिंद–प्रशांत में उनका विकास सहयोग, क्षेत्र में एक समान, सकारात्मक और दूरंदेशी परिवर्तन की संभावना प्रकट करने में योगदान दे सकता है और दक्षिण–पूर्व एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर–प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के सामाजिक–आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। कनेक्टिविटी गलियारे के साथ औद्योगिक विकास सहित हम भारत की आईपीओआई और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो–पैसिफिक (एफओआईपी) के बीच संबद्धता पाते हैं। आरआईएस ने नई दिल्ली में जापान के दूतावास (ईओजे) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) की साझेदारी में मार्च 2021 से 'मुक्त, खुले और समावेशी हिंद–प्रशांत के लिए कनेक्टिविटी सहयोग' पर आभासी माध्यम से संगोष्ठी श्रृंखला शुरू की। आसियान स्टडीज सेंटर, चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी, बैंकॉक;बैंकॉक के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कंटेम्परारी साउथ–ईस्ट एशिया (आईआरएएसईसी–सीएनआरएस) और आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने 8–9 जुलाई 2021 को "महामारी के पश्चात एशिया की व्यवस्था और एकीकरण : क्रॉसरोड्स पर आसियान और हिंद–प्रशांत का दृष्टिकोण" विषय पर आभासी माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह तकनीकी सत्र थे जिनमें हिंद–प्रशांत संबंधों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। आरआईएस ने जर्नल ऑफ एशियन इंटीग्रेशन का हिंद–प्रशांत को समर्पित एक विशेषांक (इंडो–पैसिफिकः ए न्यू पैराडाइम) भी निकाला।

समुद्री सुरक्षाः हिंद–प्रशांत में प्रमुख स्तंभ

हिंद–प्रशांत, हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की समान चुनौतियों के इर्द–गिर्द विकसित हो रहा है। आरआईएस ने विदेश मंत्रालय, ऑस्ट्रेलियाई सरकार, नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन (एनएमएफ) और रिसर्च सेंटर फॉर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्टडीज, कोलकाता (सीईएनईआरएस–के) के साथ साझेदारी में 23–24 नवंबर 2021 को कोलकाता में हाइब्रिड मोड में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ईस्ट एशिया समिट (ईएएस) सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन किया। 5वें ईएएस सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र के संबंध में सूचना और संसाधनों को साझा करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, आपदा जोखिम में कमी और महामारी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और आगे की राह पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा के दौरान आईपीओआई और इस क्षेत्र में भारत की व्यावहारिक कूटनीति को मजबूत बनाने की क्षमता वाले इसके सात स्तंभों के महत्व पर विचार मंथन किया गया।

भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी

भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) कनेक्टिविटी साझेदारी, ईयू की ग्लोबल गेटवे पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है। ईयू की इस पहल का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, संस्थानों, बैंकों, व्यवसायों और दुनिया भर के लोगों को जोड़ने हेतु गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में निवेश के माध्यम से 'निर्भरता नहीं, बल्कि लिंक्स' का सृजन करना है। भारत–ईयू कनेक्टिविटी का उद्देश्य, यूरोपीय संघ और भारत के बीच तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, हिंद–प्रशांत सहित तीसरे देशों और क्षेत्र के साथ पारदर्शी, समावेशी और नियम–आधारित कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। यह सतत विकास, साझा मानदंडों और मूल्यों से सामाजिक–आर्थिक लाभों को कायम रखते हुए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के माध्यम से नए अवसरों की भी पहचान करती है। आरआईएस ने 28 अक्टूबर 2021 को 'भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटीः पार्टनर्शिप फॉर डेवलेपमेंट, डिमांड एंड डेमोक्रेसी' शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की। इस रिपोर्ट को लॉन्च करते समय, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम एस्टुटो ने कहा कि यूरोपीयन इनवेस्टमेंट बैंक और निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाना भारत–यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के प्रभावी कार्यान्वयन की कुंजी साबित होगा।

आसियान–भारत कनेक्टिविटी सहयोग

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (ए ई पी) के दृष्टिकोण को साकार करने का प्रमुख आधार है। भारत और आसियान के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय राजमार्ग (टीएच) विकसित किया जा रहा है, और टीएच को कंबोडिया, लाओ पीडीआर, और वियतनाम तक विस्तारित करने की योजना है। टीएच के पूरा होने से भारत और आसियान के बीच माल और लोगों की त्वरित आवाजाही में सुगमता होने तथा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की गति में तेजी आने की संभावना है। "त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तारः पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास के निहितार्थ" शीर्षक वाली आरआईएस की रिपोर्ट पूर्वोत्तर भारत के बाजार के मूलभूत आर्थिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है तथा टीएच विकास की दृष्टि से इसकी क्षमता के बेहतर उपयोग की संभावनाओं के संबंध में नए विचार प्रस्तुत करती है। यह अध्ययन एनईआर के आर्थिक संबंधों की स्थिति का आकलन करता है, भारत–म्यांमार सीमा के पीछे और उस पर मौजूद बाधाओं की पहचान करता है तथा पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करता है। यह अध्ययन संस्थागत व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करता है और टीएच के साथ भारत–म्यांमार सीमा पर माल और लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्वों की पहचान करता है। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर टीएच के विकास के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है।

बिम्सटेक में क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती प्रदान करना

आरआईएस क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण में अपने योगदान के लिए विख्यात है। वर्ष 2021–22 में इसने बिम्सटेक और आसियान पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान केंद्रित किया। बिम्सटेक और आसियान के साथ मजबूत साझेदारी न केवल हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का समर्थन करती है, बल्कि 'एक्ट ईस्ट' नीति को भी प्रेरित करती है। अनुसंधान के जरिए जानकारी सृजित करने के अलावा आरआईएस ने कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए।उदाहरण के लिए, आरआईएस ने सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस), कोलकाता के सहयोग से 25–26 अक्टूबर 2021 को "बिम्सटेकः वृद्धि और विकास का वाहन" नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया। 28 अक्टूबर 2021 को आरआईएस ने अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) के सहयोग से 'बिम्सटेक क्षेत्र में सतत कृषि और मूल्यवर्धन में सहयोग तलाशना' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस ने साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट (एसएडब्ल्यूटीईई), नेपाल; इंडियन स्टडी सेंटर (आईएससी), चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी, थाईलैंड; पाथफाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका; सेंटर फॉर रिसर्च ऑन भूटानीज सोसाइटी (सीआरबीएस), भूटान के सहयोग से आभासी माध्यम से द्वितीय बंगाल की खाड़ी आर्थिक संवाद 2022 का आयोजन किया। साउथ एशियन नेटवर्क ऑन इकोनॉमिक मॉडलिंग(एसएएनईएम),ढाका ने अगुवाई की।

आसियान–भारत साझेदारी बढ़ाना

आसियान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी (ए ई पी) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है। आरआईएस और उसका आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) अनुसंधान अध्ययनों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से आसियान–भारत संबंधों पर काम करते रहे हैं। आरआईएस ने 29 जुलाई, 2021 को 'एशिया प्रशांत में कोविड के पश्चात आर्थिक लचीलेपन का निर्माण' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। आरआईएस ने वीएएसएस के वियतनाम इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन एंड साउथवेस्ट एशियन स्टडीज (वीआईआईएसएएस) के सहयोग से 7–8 अक्टूबर 2021 को हनोई और नई दिल्ली में आसियान–भारत सांस्कृतिक और सभ्यतागत लिंक्स (एआईसीसीएल) पर तृतीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का हाइब्रिड मोड में आयोजन किया। आरआईएस ने 18वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021 से पूर्व एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और आसियान–इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) के सहयोग से 18 अक्टूबर 2021 को 'भारत–आसियान संबंधों को प्रगाढ़ बनानाः संबद्धता के लिए नए रास्ते तलाशना' विषय पर आभासी मोड में एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में भारत–आसियान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के मौजूदा मुद्दों, क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण बढ़ाने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान और कोविड–19 के बाद की दुनिया में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आरआईएस ने 18वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन और 14वें ईस्ट एशिया समिट से पूर्व 21 अक्टूबर 2021 को 'आसियान–भारतः कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलापन का उपयोग' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। आरआईएस ने एशियन कंफ्लुएंस के सहयोग से 18 नवंबर 2021 को 'आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021 और प्रमुख संदेश' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। आरआईएस और इंडोनेशिया के दूतावास ने 29 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से आभासी प्रारूप में 'भारत–इंडोनेशिया आर्थिक संबद्धता को प्रगाढ़ बनाने हेतु संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए आसियान–भारत एफटीए पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

आसियान–भारत संबंधों के तीस वर्षों का जश्न

आसियान–भारत संवाद साझेदारी के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आरआईएस ने आसियान–भारत संबंधों की स्थायी चुनौतियों और उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आभासी स्वरूप में संगोष्ठियों का आयोजन किया। इस तरह का प्रथम आयोजन 18 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। दो विशेष भाषण श्री ऑन्ग शॉन, राजदूत, कंबोडिया दूतावास, नई दिल्ली और आसियान में भारत के राजदूत जयंत एन. खोबरागड़े, भारतीय मिशन, आसियान, जकार्ता द्वारा दिए गए।

आरआईएस ने चुलालोंगकोर्न यूनिवर्सिटी के सहयोग से "आसियान–भारत संबंधों के तीस सालः आसियान–भारत की साझेदारी को मजबूत बनाना और महामारी के बाद का भविष्य" नामक स्मारक खंड भी प्रकाशित किया।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और प्रसार

वर्ष 2021–21 में आरआईएस ने विदेश मंत्रालय (एमईए) के सहयोग से 16–20 अगस्त 2021 को "आसियान–भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम (एआईडीपीपी)" नामक एक ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किया। एआईडीपीपी को 16–20 अगस्त 2021 को आरआईएस के एआईसी में एशियन कंफ्लुएंस और आसियान स्टडी सेंटर ऑफ आईएसईएएस–यूसुफ आइजक इंस्टीट्यूट, सिंगापुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया। एआईडीपीपी कार्यक्रम में कई व्याख्यान और इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए, जिनमें भू–राजनीति, आर्थिक संबंध, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, व्यापार सुविधा और आसियान–भारत संबंधों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल थे। आरआईएस के एआईसी ने 14–19 जून 2021 के दौरान 'भारत और अंतरराष्ट्रीय विकास' विषय पर सप्ताह भर ऑनलाइन सार्वजनिक व्याख्यानों का आयोजन किया। अनुसंधान और नीतिगत प्रसार के मोर्चे पर आरआईएस के एआईसी ने 2021–22 में सेज का जर्नल ऑफ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन (जेएईआई) जारी किया। वॉल्यूम–3 के दो अंक प्रकाशित किए। इसके अलावा, आरआईएस के एआईसी ने कई क्रॉस–कटिंग विषयों पर कमेंट्री सीरीज़ और वर्किंग पेपर प्रकाशित करना जारी रखा।

आगे की राह

कनेक्टिविटी साधन है, अपने आप में उद्देश्य रहित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को सुगम बनाना है। सतत विकास के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। देशों के बीच कनेक्टिविटी साझेदारी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। मजबूत संपर्क और सहयोग के परिणामस्वरूप केवल लचीलापन ही नहीं, बल्कि जन–केंद्रित और समावेशी क्षेत्रीय एकीकरण हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, एईपी की पृष्ठभूमि में कनेक्टिविटी परियोजनाओं की वास्तविक क्षमता को समझने के लिए वर्तमान मामलों, चुनौतियों और अवसरों का आकलन करने की आवश्यकता है। मौजूदा मूल्यांकन हिंद–प्रशांत विजन को साकार करने हेतु भारत के लिए एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने में मददगार होगा।

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

भारत–आसियान संबंधों में गहनता लानाः जुड़ाव की नई राहें तलाशना

एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी) के सहयोग से 18वें आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021 से पहले 'भारत–आसियान संबंधों में गहनता लानाः जुड़ाव की नई राहें तलाशना' पर 18 अक्टूबर, 2021 को आभासी मोड में एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार कार्यक्रम का लक्ष्य भारत–आसियान द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े मौजूदा मुद्दे, क्षेत्रीय व्यापार और एकीकरण को और विस्तारित करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने, और कोविड–19 के बाद की दुनिया में अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना था। उद्घाटन भाषण सुश्री हर्शा बंगारी, प्रबंध निदेषक, निर्यात–आयात बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था। जबकि विशेष संबोधन दातो रमेश कोडम्मल, सह–अध्यक्ष, आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (एआईबीसी), कुआलालंपुर और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, द्वारा दिया गया था। सुश्री रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मुख्य भाषण दिया। इस वेबिनार में इंडिया एक्ज़िम बैंक रिसर्च प्रकाशन 'मूल्य श्रृंखला का निर्माणः भारत और आसियान के लिए अवसर' का भी विमोचन किया गया। डॉ प्रबीर डे, समन्वयक, एआईसी, आरआईएस, नई दिल्ली ने पैनल चर्चा का संचालन किया, जिसमें हिस्सा लेने वालों में विशेषज्ञ थे – डॉ राजन रत्न, उप–प्रमुख और वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी, यूएनएस्केप, नई दिल्ली; प्रोफेसर रूथ बानोमॉन्ग, डीन, थम्मासैट बिजनेस स्कूल, थम्मासैट विश्वविद्यालय, बैंकॉक; सचिव कार्लिटो जी गैल्वेस, जूनियर, शांति प्रक्रिया पर राष्ट्रपति के सलाहकार कार्यालय, मुख्य कार्यान्वयनकर्ता और वैक्सीन ज़ार, कोविड–19 के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य बल, फिलीपींस सरकार; और श्री मोहम्मद इरशाद, आसियान के लिए कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एशिया पैसिफिक, सिंगापुर। निर्यात–आयात बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री डेविड सिनेट ने समापन टिप्पणी दी और धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021: प्रमुख तथ्य

38वें और 39वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित कार्यक्रम अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह में हुए। आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने एशियन कोनफलूयनस के सहयोग से 18 नवंबर 2021 को 'आसियान–भारत शिखर सम्मेलन 2021: प्रमुख तथ्य, 2021 पर एक वेबिनार का आयोजन किया। विभिन्न आसियान देशों और भारत के युवा छात्रों और शोध छात्रों ने वेबिनार में भाग लिया और हाल ही में आयोजित आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की। वेबिनार में आसियान–भारत शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की गई। एशियन कॉन्फ्लुएंस के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची दत्ता द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान इंडिया सेंटर (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। पैनलिस्ट में सुश्री जोआन लिन वेइलिंग, लीड रिसर्चर, आईएसईएएस–यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट, सिंगापुर; डॉ वो जुआन विन्ह, उप महानिदेशक, दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, वीएएसएस, वियतनाम; डॉ सृष्टि पुखरेम, सीनियर रिसर्च फेलो, इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली; श्री सुपावित केवखुनोक, शोधकर्ता, थाईलैंड राजनीतिक डेटाबेस अनुसंधान केंद्र, बैंकॉक; सुश्री महिमा दुग्गल, रिसर्च एसोसिएट, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज (सीएपीएस), नई दिल्ली और डॉ संपा कुंडू, सलाहकार, एआईसी, आरआईएस, नई दिल्ली शामिल थे। ■

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

आसियान–भारत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी संपर्क पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

वियतनाम इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन एंड साउथवेस्ट एशियन स्टडीज के सहयोग से आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र (एआईसी) ने आसियान–भारत सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधी संपर्क पर 7–8 अक्टूबर, 2021 को हनोई और नई दिल्ली में संकर मोड में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

तीसरा संस्करण दो दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पांच पूर्ण सत्र और सांस्कृतिक सहयोग पर एक विशेष सत्र शामिल था। पांच पूर्ण सत्र थे: (1) समकालीन सांस्कृतिक बातचीत और विविधता, (2) संस्कृति और डिजिटलीकरण, (3) संस्कृति और पर्यटन, (4) शिक्षा और युवा, और (5) साझा विरासत।

इस सम्मेलन में विषय विशेषज्ञों, विद्वानों, चिकित्सकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ आसियान देशों और भारत के कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आरआईएस, नई दिल्ली के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी; प्रो डॉ डांग गुयेन एन्ह, उपाध्यक्ष, वियतनाम सामाजिक विज्ञान अकादमी (वीएएसएस), हनोई; राजदूत प्रणय वर्मा, वियतनाम में भारत के राजदूत, हनोई; राजदूत फाम सान चाऊ, भारत में वियतनाम के राजदूत; और श्री ट्रॅन डुक बिन्ह, उप महासचिव (डीएसजी) आसियान समुदाय और कॉर्पोरेट मामलों के लिए, आसियान सचिवालय, जकार्ता द्वारा विषेश टिप्पणी की गई। महामहिम श्री गुयेन क्वोक जुंग, उप विदेश मंत्री और आसियान सोम नेता, वियतनाम ने उद्घाटन भाषण दिया। विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय, डॉ राजकुमार रंजन सिंह ने मुख्य भाषण दिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने की। महामहिम सुश्री पेन मोनी मकरा, राज्य सचिव और सोमका अध्यक्ष, कंबोडिया ने समापन सत्र में एक विशेष भाषण दिया। राजदूत रीवा गांगुली दास, सचिव (पूर्व), विदेष मंत्रालय ने समापन भाषण दिया। आसियान, जकार्ता में भारत के राजदूत जयंत एन खोबरागड़े और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय (एएससीसी), आसियान सचिवालय, जकार्ता के लिए आसियान के उप महासचिव श्री कुंग फोक ने भी सम्मेलन में विशेष टिप्पणी की। वीआईआईएसएएस और आरआईएस में आसियान–इंडिया सेंटर (एआईसी) की ओर से क्रमशः डॉ फाम काओ कुओंग और प्रो प्रबीर डे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

बिम्सटेक क्षेत्र में सतत कृषि विकास और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज

श्री बिशोव पराजुली

प्रोफेसर मुस्तफिजुर रेहमान

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

प्रोफेसर एस. के. मोहन्ती

28 अक्टूबर, 2021 को, आरआईएस ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 'बिम्सटेक क्षेत्र में सतत कृषि विकास और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज' पर एक वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें सदस्य राज्यों के विशिष्ट वक्ताओं, अध्यक्षों और पैनलिस्टों ने भाग लिया।

वेबिनार की शुरुआत आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी के स्वागत भाषण के साथ हुई। उन्होंने सदस्य राज्यों के क्षमता निर्माण और सहयोगात्मक कार्य, क्षेत्र में विकास की सीमाओं का विस्तार, निवेश के अवसरों की पहचान, और कई अन्य मुद्दों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। डॉ सुरेश बाबू, सीनियर रिसर्च फेलो और क्षमता सुदृढ़ीकरण के प्रमुख, एफपरी, वाशिंगटन ने इस क्षेत्र में गठबंधन की प्राथमिकता के महत्व की ओर इशारा करते हुए अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि कैसे एक स्थायी खाद्य प्रणाली एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्रह एसडीजी में से नौ को प्रभावित करती है। .

प्रोफेसर सतीश वाई देवधर

श्री राजीव खेर

उद्घाटन भाषण भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में अर्थशास्त्र क्षेत्र के प्रोफेसर सतीश वाई देवधर ने दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सम्पर्क–सम्बन्ध में प्रोत्साहन की आवष्यकता, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, मौसम पूर्वानुमान, मूल्य श्रृंखला, ज्ञान साझा आदि के बारे में बात की और कृषि में एकतरफा उत्पादन की समस्या पर भी प्रकाश डाला।

उद्घाटन सत्र के बाद तीन सत्र थे। पहला तकनीकी सत्र 'बिम्सटेक में कृषि में व्यापार को बढ़ावा देना' विशय पर था। इसमें अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन अत्यधिक संवेदनषील है, इसलिए, खाद्य सुरक्षा और मूल्य श्रृंखला में व्यवधान का जोखिम है। श्रम उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता से उत्पादन करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा नियमों, क्षेत्रीय व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने आदि जैसे कई सुझाव भी दिए गए थे।

दूसरा तकनीकी सत्र 'बिम्सटेक में खाद्य प्रसंस्करण और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं की संभावनाओं' पर था, जिसमें बाधाओं को दूर करने और उन पर काबू पाने, मूल्य श्रृंखला में किसानों की उच्च भागीदारी, कृषि स्तर पर पैकेजिंग में सुधार, विभिन्न प्रसंस्कृत खाद्य उपक्षेत्रों में उच्च क्षेत्रीय प्रदर्शन, मूल्य श्रृंखला उन्नयन, डेटा का कुशल उपयोग और बेहतर डेटा संग्रह, आदि का सुझाव दिया गया था। 'कृषि में खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा के मुद्दे' पर हुए तीसरे सत्र में कृषि और पोषण के बीच गठजोड़ पर ध्यान देने, उपज में विविधता लाने, खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने पर खर्च करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान देने आदि पर फोकस करने की ओर इशारा किया गया।

डॉ सुरेश बाबू की अध्यक्षता में समापन सत्र का कार्यक्रम समाप्त हुआ। प्रमुख सिफारिशें डॉ प्रियदर्शी दाश, एसोसिएट प्रोफेसर, आरआईएस द्वारा प्रस्तुत की गईं। विदाई भाषण श्री हान थीन क्याव, प्रभारी निदेशक (कृषि सहयोग), बिम्सटेक सचिवालय, ढाका, बांग्लादेश द्वारा दिया गया। डॉ अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस, नई दिल्ली ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। ■

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

बिम्सटेकः विकास और प्रगति का एक साधन

25–26 अक्टूबर 2021 को 'बिम्सटेकरू ए व्हीकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट' (बिम्सटेकः विकास और प्रगति का एक साधन) पर एक रोचक संगोष्ठी हुई। इसे सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (Institute of Social and Cultural Studies & ISCS), कोलकाता और RIS द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्घाटन सत्र में, आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में परिवहन कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी, पारंपरिक दवाओं के महत्व और कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए क्षेत्रीय विकास बैंकों की क्षमता का दोहन करने के बारे में बात की। आईएससीएस, भारत (ISCS, India) के निदेशक श्री अरिंदम मुखर्जी ने आतंकवाद, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, व्यापार और समुद्री सहयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

बिम्सटेक के महासचिव महामहिम राजदूत तेनजिन लेचफेल ने एक विषेश भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बिम्सटेक क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा की, और क्रॉस–कंट्री संगठित अपराध, समुद्री संपर्क, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों और सुरक्षा को सहयोग के क्षेत्रों के रूप में की पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने भारत में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र और बिम्सटेक चार्टर की भूमिका पर भी प्रकाष डाला।

भारत के विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव, महामहिम राजदूत हर्शवर्धन श्रृंगला ने उद्घाटन भाषण दिया और माल की सीमा पार आवाजाही, ऊर्जा, बिजली (पावर ग्रिड कनेक्टिविटी), व्यापार, तटीय सुरक्षा, समुद्री संपर्क, आतंकवाद का मुकाबला और पर्यटन में क्षेत्रीय सहयोग पर कई बहुमूल्य सुझाव दिए।

संगोष्ठी का समापन राजदूत सुमित नकंदला की अध्यक्षता में एक समापन सत्र के साथ हुआ, जो भारत–लंका अध्ययन (प्दकव–स्ंदां ˋजनकपमे), पाथ फाइंडर फाउंडेशन, श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक (पूर्व महासचिव, बिम्सटेक) हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पीपी एंड आर डिवीजन (च्च–त क्पअपेपवद) में संयुक्त सचिव राजदूत डॉ अनुपम रे ने विशेष टिप्पणी की। भारत में जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सुरंजन दास ने एक विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लिया, और तैए भारत में सहायक प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने संगोष्ठी रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी। त्रैए भारत में कार्यक्रम समन्वयक श्री कृष्णु बक्सी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

इंडो–पेसिफिक में समुद्री अर्थव्यवस्था

आधुनिक समुद्री प्रौद्योगिकियों की उन्नति एवं महासागर संस्थानों का कुशल दोहन, उच्च सामाजिक आर्थिक विकास और सतत विकास में सहयोग कर रहा है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर विचार करते हुए भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने तटीय अर्थव्यवस्था और श्रीलंका में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय स्तर पर बिम्सटेक तथा हिंद महासागरीय संघ में कई पहल की हैं।

आर आई एस ने 23 सितम्बर 2021 को हिंद महासागर तथा प्रषान्त महासागर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर वेबिनार का आयोजन किया। आरआईएस के प्रोफेसर एस के मोहंती ने स्वागत टिप्पणी और डॉ मालिनी वी शंकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्रीलंका के उप आयुक्त माननीय श्री मान निलूका कादूरुगामुआ ने विशेष टिप्पणी दी। डॉक्टर गणेशन विगनराज, वरिष्ठ सहचर, आर आई एस, ने

A Webinar on 'Maritime Economy in Indo-Pacific' is in progress.

इंडो–पेसिफिक समुद्री व्यापार पर प्रस्तुति दी। डॉक्टर विश्वपति त्रिवेदी पूर्व सचिव, जहाजरानी मंत्रालय और खान, भारत सरकार ने भी चर्चा में भाग लिया । ढ

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

आसियान–भारत एफटीए की समीक्षाः भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करना

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र और इंडोनेशिया के दूतावास ने संयुक्त रूप से आभासी प्रारूप में भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने की संभावनाओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए आसियान–भारत एफटीए पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन 29 नवम्बर, 2021 को किया। श्री मस्नी एरिज़ा, मिशन के उप प्रमुख, दिल्ली में इंडोनेशियाई दूतावास; और श्री विश्वास विदु सपकाल, संयुक्त सचिव (दक्षिण और हिंद–प्रशांत), विदेश मंत्रालय ने उद्घाटन भाषण दिया। सत्र का संचालन डॉ. प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आसियान–भारत केंद्र (एआईसी), आरआईएस, नई दिल्ली द्वारा किया गया था। प्रमुख वक्ता थेः श्रीमती दीना कुर्नियासारी, आसियान वार्ता की निदेशक, व्यापार मंत्रालय, इंडोनेशिया; सुश्री इंदु नायर, निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत; डॉ लीना एलेक्जेंड्रा, वरिष्ठ शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र (सीएसआईएस), जकार्ता; और श्री प्रणव कुमार, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली। प्रख्यात पैनल ने आसियान–भारत एफटीए समीक्षा के आलोक में भारत–इंडोनेशिया आर्थिक जुड़ाव की संभावनाओं पर चर्चा की। ▪

भारत–यूरोपीय संघ संपर्कः विकास और लोकतंत्र के लिए साझेदारी

भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत, यूगो एस्टुटो के अनुसार, भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) कनेक्टिविटी पार्टनरषिप यूरोपीय संघ की ग्लोबल गेटवे पहल का एक महत्वपूर्ण घटक होगा जिसका उद्देश्य दुनिया भर में वस्तुओं, सेवाओं, संस्थानों, बैंकों, व्यवसायों और लोगों को जोड़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में निवेश के माध्यम से 'निर्भरता नहीं, संपर्क' बनाना है।

28 अक्टूबर 2021 को, आरआईएस द्वारा 'भारत–यूरोपीय संघ संपर्कः विकास, मांग और लोकतंत्र के लिए साझेदारी' शीर्षक से एक रिपोर्ट का अनावरण करते हुए, राजदूत एस्टुटो ने यह भी कहा कि यूरोपीय निवेश बैंक और निजी क्षेत्र की ताकत का लाभ भारत–यूरोपीय संघ सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पूर्व राजदूत सुश्री भास्वति मुखर्जी

आरआईएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, श्री संदीप चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम), विदेश मंत्रालय, ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने सुनिश्चित किया है कि उनकी द्विपक्षीय सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी 'उच्च मानक' की होगी, और लोगों से लोगों के संपर्क के साथ–साथ यह गतिशीलता पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा कि 'सुरक्षित और भरोसेमंद' आपूर्ति श्रृंखला बनाने के महत्व को देखते हुए द्वि पक्षीय साझेदारी ने अन्य देशों और क्षेत्रों में समान विचारों को प्रेरित किया है। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस संदर्भ में व्यवहार्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही एक भारत–यूरोपीय संघ 'कनेक्टिविटी फोरम' शुरू करने की योजना है।

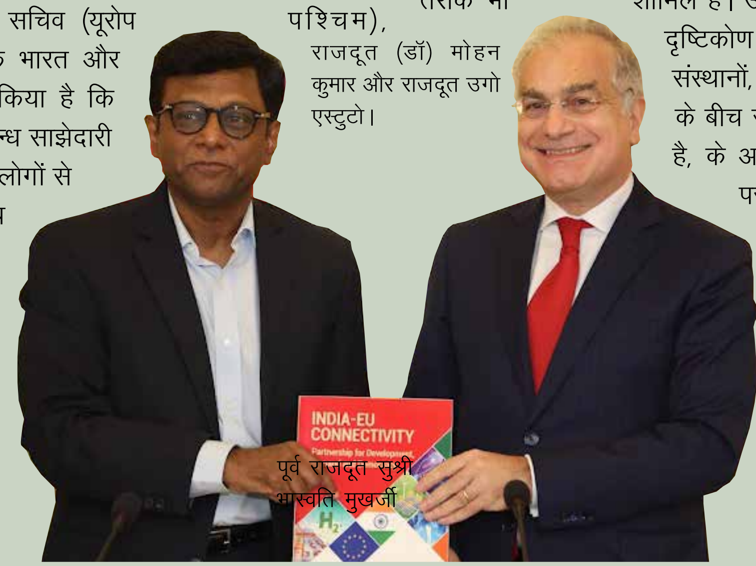

राजदूत (डॉ) मोहन कुमार और राजदूत उगो एस्टुटो।

राजदूत (डॉ) मोहन कुमार, अध्यक्ष, आरआईएस, ने भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी साझेदारी के कार्यनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय संपर्क समझौते के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत–यूरोपीय संघ व्यापार और निवेष समझौतों पर बातचीत में तेजी लाने की आवष्यकता पर बल दिया। आरआईएस के महानिदेशक, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि आरआईएस रिपोर्ट में भारत–यूरोपीय संघ के व्यापार और निवेष, सम्पर्क–सम्बन्ध में सहयोग के क्षेत्रों का गहन विश्लेशण है। साथ ही, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) का लाभ उठाकर सतत विकास और हरित संक्रमण के लिए कनेक्टिविटी का उपयोग करने के तरीके भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में संस्थागत दृष्टिकोण से वित्तीय संपर्क, जहां वित्तीय संस्थानों, बैंकों और फिनटेक के प्रदाताओं के बीच संबंधों की विस्तार से जांच की गई है, के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर रोशनी डाली गई है, जैसे कि हरित हाइड्रोजन, सौर और अन्य प्रकार की गैर–पारंपरिक ऊर्जा।

बाद की परिचर्चा के दौरान, नीदरलैंड में भारत की पूर्व राजदूत, सुश्री भास्वती मुखर्जी ने संधारण ीयता सहित सम्पर्क–सम्बन्ध

व्यापार में सुविधा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण

सिद्धांतों पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच अभिसरण की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि साझेदारी समझौता वित्तीय और पर्यावरणीय संधारणीयता सहित उभरती चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के अध्यक्ष, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने कहा कि भारत–यूरोपीय संघ सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी में तीसरी दुनिया के देशों में भी सम्पर्क–सम्बन्ध बढ़ाने के संबंध में बड़ी संभावनाएं और भू–राजनीतिक मूल्य हैं, और यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विकल्प होगा।

सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र के फेलो डॉ कांस्टेंटिनो जेवियर ने कहा कि चूंकि द्विपक्षीय सम्पर्क–सम्बन्ध साझेदारी लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है और पारदर्षिता और सुशासन के अलावा अंतर–संचालन पर जोर देती है, इसलिए यह क्षेत्रीय मानकों को निर्धारित करने में मदद कर सकती है और यहां तक कि एक वैश्विक संपर्क साझेदारी के गठन में भी मदद कर सकती है। भारत और यूरोपीय संघ का यह सुनिश्चित करने का निर्णय कि वे सरकारी स्तर पर नेतृत्व करेंगे और सुविधा प्रदान करेंगे, लेकिन एक भारी भूमिका नहीं निभाएंगे, एक और महत्वपूर्ण पहलू था।

प्रोफेसर एस के मोहंती, आरआईएस ने उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी गहन व्यापार भारत–यूरोपीय संघ व्यापार के मूल में है, जबकि उनके द्विपक्षीय सेवा व्यापार में पूरकताएं हैं। विकास वित्त के रुझानों के बारे में बोलते हुए, आरआईएस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रियदर्शी दाश ने कहा कि अब ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानदंड पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच अधिक वित्तीय संपर्क की आवश्यकता है ताकि दोनों पक्षों को फिनटेक सहित अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिल सके। ■

आसियान भारत विकास भागीदारी कार्यक्रमः ऑनलाइन परीक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विदेष मंत्रालय द्वारा समर्थित आसियान भारत विकास भागीदारी कार्यक्रम (एआईडीपीपी) का आयोजन आर आई एस, भारत आसियान केंद्र, संगम और युसूफ इस्साक संस्थान, सिंगापुर ने 16 से 20 अगस्त 2021 को किया। कार्यक्रम में भू–राजनीती, आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा निवेश, व्यापार सरलीकरण, आसियान–भारत सम्बन्धों में प्राथमिक क्षेत्र इत्यादि पर चर्चा हुई। नीति, शिक्षण, विधि और उद्योगिक क्षेत्र से विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान भी दिये।■

आसियान–भारत कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का दोहन

आरआईएस में आसियान–भारत केंद्र ने 18वें आसियान–भारत और 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से पहले 21 अक्टूबर 2021 को 'आसियान–भारतः कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन का दोहन' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। पैनल में विशय विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति नियोजक और व्यवसायी शामिल थे। इस अवसर पर वेबिनार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के अवसरों, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बढ़ी हुई कनेक्टिविटी, कोविड –19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और चुनौतियों एवं कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तारः पूर्वोत्तर भारत के लिए विकास निहितार्थ' शीर्षक के साथ एआईसी–आरआईएस की रिपोर्ट जारी की गई। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और आरआईएस के अध्यक्ष डॉ मोहन कुमार ने उद्घाटन भाषण दिया। सुश्री एलिस चेंग, उप उच्चायुक्त, भारत में सिंगापुर गणराज्य के उच्चायोग, नई दिल्ली और राजदूत जयंत एन खोबरागड़े, आसियान, जकार्ता में भारतीय राजदूत द्वारा विशेष टिप्पणियां दी गईं। डॉ प्रबीर डे, प्रोफेसर और समन्वयक, आरआईएस में एआईसी, ने परिचर्चा की अध्यक्षता की और 'त्रिपक्षीय राजमार्ग और कंबोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम तक इसका विस्तारः पूर्वोत्तर भारत के लिए निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी। सत्र के वक्ता थे – डॉ अंबुमोझी वेंकटचलम, अनुसंधान रणनीति और नवाचार के निदेशक, आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए), जकार्ता; श्री सो उमेज़ाकी, निदेशक, आर्थिक एकीकरण अध्ययन समूह, विकास अध्ययन केंद्र, विकासशील अर्थव्यवस्था संस्थान (आईडीई–जेट्रो), चिबा, जापान; श्री भरत जोशी, निदेशक, एसोसिएटेड कंटेनर टर्मिनल्स लिमिटेड (एसीटीएल), नई दिल्ली; प्रोफेसर सीएच

प्रियरंजन सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल; डॉ टिन हटू नाइंग, निदेशक, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज केंद्र (सीईईएस म्यांमार), म्यांमार; और डॉ फाम काओ कुओंग, कार्यवाहक उप महानिदेशक, वियतनाम भारतीय और दक्षिण पश्चिम एशियाई अध्ययन संस्थान। डॉ संपा कुंडू, सलाहकार, एआईसी, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

कंचनजंगा संवाद

28 दिसंबर, 2021 को आयोजित यह विचार–मंथन सत्र भूटान, बांग्लादेष, भारत और नेपाल के शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और सामुदायिक विकास व्यवसायियों को सामुदायिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्तीय और अवसंरचना विकास आदि के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के मुद्दों के साथ–साथ चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ ले आया। विषयगत रूप से, स्थानीय और जमीनी स्तर के विकास और प्रथाओं के मुद्दों, विषेश रूप से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, पर्यावरण–पर्यटन, जैविक भोजन, पुष्पकृषि, सांस्कृतिक बातचीत आदि के क्षेत्रों पर चर्चा की गई। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों में विकास सहयोग और सामुदायिक प्रथाओं के लिए उप–क्षेत्रीय तंत्र की सुविधा के लिए विचार–विमर्श और संवाद के लिए एक अकादमिक मंच के रूप में संकल्पित, पहली कंचनजंगा वार्ता फरवरी 2022 में सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में होगी। ■

अध्याय 4

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

डॉ. अमित कुमार
सहायक प्रोफेसर

डॉ स्नेहा सिन्हा
सलाहकार

एसटीआई वर्क प्रोग्राम

एसटीआई वर्क प्रोग्राम आरआईएस का एक कुशल कार्यक्रम है, जो सरकार की आवश्यकता के साथ ही साथ समकालीन वैश्विक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए निरंतरता के साथ तथा दृष्टिकोण और फोकस में परिवर्तन सहित विविध विषयों और मुद्दों पर काम करता है। इसमें एसटीआई नीति कार्यक्रम (एसटीआईपीपी) और विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम (एसडीपी) शामिल हैं। एसडीपी कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित है और भारत में विज्ञान कूटनीति पर अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम है। एसटीआई नीति कार्यक्रम नीतिगत अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इसकी गतिविधियों और प्रकाशनों का दायरा इससे अधिक है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ भारत और विदेशों में संस्थाओं के साथ सहयोग, नेटवर्किंग और संयुक्त अनुसंधान शामिल हैं।

एसटीआई नीति कार्यक्रम

वर्ष 2021–22 के दौरान, एसटीआई नीति कार्यक्रम (एसटीआईपीपी) ने विभिन्न विषयों जैसे कोविड–19 महामारी के दौरान एसटीआई का विकास, डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स छूट, एसडीजी के लिए एसटीआई, उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे एआई, रोबोटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी, डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई), टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर्ज, डिजिटल व्यापार, डिजिटल भुगतान प्रणाली, फिनटेक, डिजिटल स्वास्थ्य, 4आईआर, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन आदि को कवर किया। वर्ष 2021 में, कोविड महामारी के मद्देनजर, वैक्सीन तक पहुंच कायम कर वैश्विक संकट को दूर करने के लिए, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स परिषद के समक्ष बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) पर छूट की मांग करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अनेक विकासशील देशों ने किया जबकि अन्य विषयों के साथ–साथ इसका विरोध यूरोपीय आयोग और अमरीका द्वारा किया गया। बाद में अमरीका आंशिक छूट पर सहमत हो गया। आरआईएस ने साउथ सेंटर, जिनेवा के सहयोग से ट्रिप्स छूट पर चर्चा करने और समर्थन जुटाने के लिए सिलसिलेवार वेबिनार आयोजित किए।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए एसटीआई पर वैश्विक पायलट परियोजना (एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु एजेंडा 2030 के भाग के रूप में शुरू किए गए प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र के तहत एक पहल) में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय के ज्ञान भागीदार के रूप में आरआईएस ने हितधारकों के साथ मिलकर सिलसिलेवार वेबिनार आयोजित किए और पीएसए के कार्यालय को चार चयनित एसडीजी अर्थात् एसडीजी 2,3,6 और 7 पर विस्तृत प्रौद्योगिकी–रोडमैप के साथ अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस परियोजना के अंतर्गत अनेक कार्यशालाओं और परामर्शों का आयोजन किया गया।

एसटीआईपीपी की एक प्रमुख विशेषता उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों पर अनुसंधान करना रही है। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में उभर रही है और एसटीआईपीपी, इसके प्रभावों, विशेष रूप से नैतिक, कानूनी और सामाजिक प्रभावों (ईएलएसआई) के पहलुओं पर काम कर रहा है। वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने और किसी का भी पीछे नहीं छूटना सुनिश्चित करने के लिए समावेशी और जिम्मेदार एआई पर जोर दिया जाना महत्वपूर्ण है। आरआईएस इस मुद्दे पर यूनेस्को के साथ काम करेगा, क्योंकि यूनेस्को ने एआई नैतिक सिद्धांतों पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। एआई के अन्य प्रभावों पर शोध जारी है और परिणामों के अंतर्गत अधिक कार्यक्रम और प्रकाशन शामिल होंगे।

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) गवर्नेंस विशेष रूप से सिद्धांत और व्यवहार में पहुंच और लाभ साझाकरण (एबीएस) में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर रहा है। जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) के तहत बातचीत अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और जल्द ही किसी समाधान तक पहुंचा जा सकता है। आरआईएस सीबीडी और एबीएस से संबंधित विषयों पर काम कर रहा है। आरआईएस ने 31 अगस्त 2021 को 'डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई): मुद्दे और प्रभाव' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

इस मुद्दे पर यूके की एजेंसियों द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल में आरआईएस का एक संकाय सदस्य भी शामिल है। अन्य विषयों के साथ–साथ एआई, रोबोटिक्स, जीनोम एडिटिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और जीन ड्राइव जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां एसटीआईपीपी के तहत अनुसंधान का विषय हैं। आरआईएस संकाय सदस्य इससे संबंधित साहित्य में योगदान दे रहे हैं जैसा कि प्रकाशनों से स्पष्ट है। इसके अलावा वे सिंथेटिक बायोलॉजी पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के साथ काम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (टीए) विज्ञान नीति में एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका व्यापक रूप से अभ्यास भी किया जाता है। आरआईएस अफ्रीका में टीए के अंतर्गत क्षमता निर्माण से संबंधित एक परियोजना का हिस्सा है। यूएनसीटीएडी के नेतृत्व वाली इस परियोजना में आईटीएएस, केआईटी (जर्मनी) एक भागीदार संस्था है। इसके अंतर्गत बैठकों का आयोजन किया गया है और आरआईएस संकाय सदस्य इस परियोजना के लिए टीए पर एक नियमावली सहित प्रस्तावित प्रकाशनों में योगदान दे रहे हैं। आरआईएस ग्लोबल टीए प्रोजेक्ट के आगामी संस्करण *'टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड– फेसिंग द चैलेंजेज ऑफ ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस'* में भी योगदान कर रहा है।

विकास सहयोग के संबंध में दक्षिण–दक्षिण सहयोग (एसएससी) आरआईएस वर्क के अंतर्गत एक प्रमुख थीम है और एसटीआई में एसएससी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रोग्राम से जुड़े संकाय सदस्यों ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग और यूएनडीपी पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रकाशित *'मैपिंग साउथ–साउथ कोऑपरेशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस'* का सह–लेखन किया। ट्रिप्स छूट पर आरआईएस–साउथ सेंटर वेबिनार श्रृंखला के अंतर्गत चार वेबिनार 'ट्रिप्स छूटः मुद्दे और चुनौतियां' (5 जून 2021), 'ट्रिप्स छूटः अफ्रीका के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (12 जून 2021), 'ट्रिप्स छूटः लैटिन अमेरिका के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (19 जून 2021) और 'ट्रिप्स छूटः दक्षिण पूर्व एशिया के लिए मुद्दे और चुनौतियां' (26 जून 2021) विषयों पर इन क्षेत्रों के विविध विशेषज्ञों के साथ आयोजित किए। इन वेबिनारों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

डिजिटलीकरण और विकास एक अन्य थीम है जिस पर एसटीआई प्रोग्राम कार्य कर रहा है। आरआईएस यूरोपीय आयोग द्वारा वित्त पोषित पीआरओडीआईजीईएस परियोजना में एक भागीदार संस्था है। कोविड के कारण इस परियोजना की गतिविधियां प्रभावित हुईं। हालांकि परियोजना की बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गईं और प्रकाशन की योजनाओं पर काम शुरू किया गया। वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में इस परियोजना की ओर से एक संकाय आईडीओएस बॉन भेजा जाएगा। आरआईएस वर्ष 2022 की शुरुआत में पूर्ण हो चुकी न्यू होराइजन्स परियोजना सहित उत्तरदायित्वपूर्ण अनुसंधान एवं नवाचार (आरआरआई) से संबद्ध परियोजनाओं का अंग रहा है। आरआईएस ने आरआरआई को समृद्ध करने और आरआरआई परियोजनाओं से सीखने के लिए भारत से अवधारणाएं और उदाहरण लाकर इस परियोजना में योगदान दिया है।

इनके अलावा, आरआईएस संकाय नियमित रूप से बाहरी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, यूनेस्को जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ काम करते हैं और विद्वत समीक्षाएं करते हैं। उदाहरण के लिए, आरआईएस संकाय सदस्य डीएसटी और पीएसए के कार्यालय द्वारा शुरू की गई भारत की आगामी एसटीआई नीति की परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थे और उन्होंने एसटीआई नीति के मसौदे की विद्वत समीक्षा की थी।

आरआईएस एआई और डीएसआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के विषय पर प्रमुख संस्थाओं और विशेषज्ञों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। आरआईएस ने 19 मई 2021 को "एआई एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इसमें आईआईटी, नीति

आयोग, एमईआईटीवाई, यूएनडीपी आदि के पैनलिस्टों ने भू–राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, निजता और नैतिक मुद्दों और एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों की चुनौतियों का समाधान करने पर बल दिया।

एसडीजी पर अनुसंधान आरआईएस वर्क प्रोग्राम का अभिन्न अंग है। इसलिए विकास के मुद्दों से निपटने और एसडीजी हासिल करने तथा केन्या और भारत में फिनटेक की सफलता की कहानियों के लिए वित्त के महत्व को पहचानते हुए, आरआईएस, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) ने एसेक्स विश्वविद्यालय, यूके के सहयोग से 23 अप्रैल 2021 को 'बैंक, वित्त और प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूपः फिनटेक के साथ नए विकल्प' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। कई हितधारकों को एक साथ लाते हुए इस वेबिनार में एशिया और अफ्रीका में नवोन्मेषी विकास सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग के मॉडल दोहराने और फिनटेक का समावेशी तरीके से उपयोग करने और डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, आरआईएस ने 13 नवंबर 2021 को 'नवाचार प्रोत्साहनों पर भारतीय दृष्टिकोण : स्वास्थ्य प्रभाव कोष एवं हरित प्रभाव कोष प्रौद्योगिकी' (येल यूनिवर्सिटी के ग्लोबल जस्टिस प्रोग्राम के साथ) विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया, साथ ही 26 दिसंबर 2021 को भोपाल में सतत अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवोन्मेषों और डेटा पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया।

एसटीआईपी फोरम व्याख्यान श्रृंखला (सितंबर 2017 में प्रारंभ) के तत्वावधान में, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान आठ सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए गए। ये सार्वजनिक व्याख्यान प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा डेटा विश्लेषण और दीर्घकालिक कोविड–19; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और महामारी; खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां और ग्रामीण अर्थव्यवस्था; सौर भौतिकी; सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा स्वराज्य; पारम्परिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रांसलेशनल रिसर्च; वैश्विक ऊर्जा संक्रमण; और रीवायरिंग द ब्रेन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दिए गए। आरआईएस ने इनमें से तीन सार्वजनिक व्याख्यानों का; जबकि अन्य एसटीआईपी फोरम भागीदार संस्थाओं (टेरी और विज्ञान प्रसार) ने शेष सार्वजनिक व्याख्यानों का समन्वय किया। मार्च 2022 तक ऐसे कुल 42 सार्वजनिक व्याख्यान सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके थे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम की स्थापना अगस्त 2017 में आरआईएस द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर, टेरी, सीईएफआईपीआरए और विज्ञान प्रसार के सहयोग से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रसार के साथ–साथ सामाजिक आकांक्षाओं पर चर्चा को आम बनाना तथा जिम्मेदारीपूर्ण अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और समाज के बीच की खाई को पाटना है।

वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान, आरआईएस ने कई अग्रणी और प्रमुख रिपोर्टें प्रस्तुत कीं हैं और इसके संकाय सदस्यों ने प्रतिष्ठित विद्वत–समीक्षित पत्रिकाओं, पुस्तकों में अनेक शोध पत्र, लेख और अध्याय प्रकाशित किए हैं तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) और नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों और विकास के मुद्दों से संबंधित विभिन्न विषयों पर कई पॉलिसी ब्रीफ और चर्चा पत्र लिखे हैं। संकाय सदस्यों द्वारा लिखित अनेक लघु लेखों/राय/टिप्पणियों का प्रकाशन प्रमुख समाचार पत्रों सहित लोकप्रिय मीडिया में किया गया है। उन्होंने आरआईएस की प्रमुख रिपोर्टों के लेखन में अपार योगदान दिया है। इस अवधि के दौरान प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में *वर्ल्ड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021; रिपोर्ट ऑन इंडिया–ईयू कनेक्टिविटी पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डिमांड एंड डेमोक्रेसी; और रिपोर्ट ऑन डिजिटाइजे□ान एंड डेवलपमेंट* शामिल हैं।

आरआईएस के संकाय सदस्यों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समीक्षा समिति के लिए *'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समिति रिपोर्ट'* लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी भी इस समिति के सदस्य थे। इस रिपोर्ट में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई और प्रमुख नीतिगत सिफारिशें प्रदान की गईं। यह रिपोर्ट 21 जुलाई 2021 को माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने जारी की।

वर्ष 2021–22 के दौरान आरआईएस और एसटीआई वर्क प्रोग्राम से संबद्ध उसके संकाय सदस्यों के प्रकाशनों के अंतर्गत व्यापक विषयों को कवर किया गया, जिनमें एसडीजी के लिए एसटीआई, टेक्नोलॉजी ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड वॉर्ज, ग्लोबल हैल्थ गवर्नेंस, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान प्रणालियां, फिनटेक, एसटीईएम में महिलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 4आईआर, ग्रीन हाइड्रोजन और ऑफ–ग्रिड सोलर

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

एनर्जी सिस्टम आदि जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इन प्रकाशनों में ग्लोबल गवर्नेंस, सामाजिक–आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन और एआई जैसी उभरती 4आईआर प्रौद्योगिकियों में नैतिकता के मुद्दों को भी शामिल किया गया है। इन प्रकाशनों में एसटीआई में दक्षिण–दक्षिण सहयोग, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, डब्ल्यूटीओ और ट्रिप्स छूट (विशेष रूप से कोविड–19 के संदर्भ में वैक्सीन और औषधियों जैसे चिकित्सा विधान) से संबंधित विषयों को भी शामिल किया गया है। आरआईएस के संकाय सदस्य ने ग्लोबल टीए से संबंधित संस्करण के लिए भारत में टीए पर एक लेख में योगदान देने के अलावा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी असेसमेंट (टीए) पर दो अध्यायों का सह–लिखन किया है। इस अवधि के दौरान दुनिया भर के अनेक शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों के योगदान के साथ प्रकाशित आरआईएस के अंतरराष्ट्रीय, ओपन–एक्सेस और पीयर–रिव्यू जर्नल, *एशियन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट रिव्यू* (एबीडीआर) के तीन अंकों में सिंथेटिक बायोलॉजी पर एबीडीआर के विशेषांक सहित एसटीआई, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता से संबंधित अनेक प्रमुख और समकालीन विषयों को कवर किया गया है।

विज्ञान कूटनीति कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्लोबल–साउथ के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों के साथ ही साथ विकास के अनेक मुद्दों के समाधान तलाशने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विदेश और सार्वजनिक नीति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रबंधन में विज्ञान कूटनीति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की आवश्यकता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान कूटनीति पर वर्तमान विमर्श ग्लोबल–नार्थ पर केंद्रित है। आरआईएस–फोरम फॉर इंडियन साइंस डिप्लोमेसी (एफआईएसडी) का उद्देश्य क्षमता बढ़ाना, विज्ञान कूटनीति में नेटवर्क विकसित करना तथा अनुसंधान और रणनीतिक सोच में योगदान देना है। यह एसटीआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, एसडीजी हासिल करने और भारतीय एसटीआई उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजारों की पेशकश करने हेतु अन्य विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त विज्ञान कूटनीति को सक्षम बनाएगा। इसी तरह, वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) का उद्देश्य ग्लोबल साउथ में समकक्ष देशों के बीच सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान, नवाचार और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने और उनको संभावित रूप से दोहराने/अपनाने के माध्यम से वैकल्पिक विकास परिप्रेक्ष्य में योगदान देना है।

इस अवधि के दौरान, आरआईएस, एफआईएसडी और जीडीसी ने एसडीजी हासिल करने, सेमीकंडक्टर्स में तकनीकी क्षमता, वियतनाम, ताइवान, केन्या, इथियोपिया, मोजाम्बिक, मलावी, रवांडा और दक्षिण सूडान जैसे देशों के साथ भारत का वैक्सीन प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान साझा करने में एस एंड टी सहयोग की संभावनाओं पर कई वेबिनार, कार्यक्रम, तकनीकी द्विपक्षीय सत्र आयोजित किए। इनमें संबंधित संस्थाओं, स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों आदि सहित कई हितधारकों की भागीदारी रही, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यूरोपीय संघ के होराइजन 2020 के समाप्ति की ओर बढ़ने के साथ ही साथ और भारत–ईयू विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, आरआईएस–एफआईएसडी ने 23 अगस्त 2021 को *'होराइजन यूरोपः विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत–यूरोपीय संघ सहयोग में आगे की राह'* विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। .

दुनिया भर में विज्ञान कूटनीति, विज्ञान नीतिगत गतिविधियों/पाठ्यक्रमों से संबद्ध संस्थानों के साथ नेटवर्किंग को सुगम बनाने के लिए, एफआईएसडी ने 110 से अधिक संस्थाओं का डेटाबेस तैयार किया है। एफआईएसडी टीम के सदस्यों ने विज्ञान कूटनीति और संबंधित मुद्दों पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, स्कूलों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों आदि में भाग लिया, प्रस्तुति दी, व्याख्यान दिया। दक्षिण–दक्षिण सहयोग आरआईएस वर्क प्रोग्राम का अभिन्न अंग है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के माध्यम से भारत के प्रयासों और ग्लोबल नार्थ और साउथ में कूटनीतिक संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

साथ ही साथ भारत की आर्थिक कूटनीति और जलवायु परिवर्तन पर विदेश नीति को देखते हुए, आरआईएस ने वैश्विक विकास केंद्र (जीडीसी) और एफआईएसडी के साथ मिलकर 17 जून 2021 को *'टैपिंग सोलर एनर्जीः शेयरिंग इंडियाज एक्सपीरियंस एंड फोर्जिंग पार्टनरशिप विद एशिया, पैसिफिक आईलैंड कंट्रीज'* विषय पर एक वेबिनार और क्रमशः 29 जून 2021 को *'चैनलाइजिंग द सनः आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियाज न्यू क्लाइमेट डिप्लोमेसी'* पर विषय एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया।

एफआईएसडी वैज्ञानिक अनुसंधान, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय प्रगति, विज्ञान कूटनीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति और गवर्नेंस में भारतीय और वैश्विक घटनाओं पर नजर रखता है तथा राजनयिकों, पूर्व और वर्तमान विज्ञान परामर्शदाताओं, दुनिया भर में विज्ञान नीति/विज्ञान कूटनीति/विज्ञान प्रौद्योगिकी अध्ययन में संलग्न संस्थाओं, स्थानीय दूतावासों और नीति निर्माताओं आदि सहित 8000 से अधिक सदस्यों को अपना पाक्षिक *साइंस डिप्लोमेसी न्यूज अलर्ट* इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाता है। अप्रैल 2021–मार्च 2022 के दौरान, इसके चौबीस अंक प्रकाशित किए गए। इस अवधि में, विज्ञान कूटनीति और भारत–वियतनाम और भारत–ताइवान एसटीआई सहयोग जैसे अंतरराष्ट्रीय एसटीआई सहयोग के विषय पर भी कई प्रकाशन सामने आए। इस अवधि के दौरान *साइंस डिप्लोमेसी रिव्यू* (एसडीआर) के तीन अंक निकाले गए, जिनमें विज्ञान कूटनीति से संबंधित कई प्रमुख और समकालीन विषयों पर दुनिया भर के अनेक शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों का योगदान था।

अप्रैल 2022–मार्च 2023 में और अधिक गतिविधियों के संचालन की तैयारी है और विभिन्न संस्करणों में दस अध्यायों के प्रकाशन सहित और अधिक सामग्री प्रकाशित की जाएगी। एसटीआई कार्यक्रम टी–20/जी–20 प्रक्रिया में योगदान दे रहा है और 2023 में यह पूरी तरह से उनके साथ संबद्ध हो जाएगा, क्योंकि 2023 में जी–20 की अध्यक्षता भारत संभालेंगा।

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

बैंक, वित्त और प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूप: फिनटेक के साथ नए विकल्प

फिनटेक–आधारित खुदरा भुगतान के क्षेत्र में केवल दो थर्ड–पार्टी सेवा प्रदाताओं के हाथों में कारोबार केंद्रित हो जाने से प्रतिस्पर्धा–रोधी माहौल बन जाने का खतरा है। आरबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगाह करते हुए यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि नियामकों के लिए चुनौती वित्तीय क्षेत्र में 'बिग टेक कंपनियों' के प्रवेश को कुछ इस तरह से प्रबंधित करना है जिससे कि इस क्षेत्र में निर्धारित नियमों का कोई उल्लंघन न हो।

23 अप्रैल 2021 को ब्रिटेन के एसेक्स विश्वविद्यालय के सहयोग से आरआईएस, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'बैंक, वित्त और प्रौद्योगिकी का बदलता स्वरूप: फिनटेक के साथ नए विकल्प' विषय पर आयोजित वेबिनार में श्री टी. रबि शंकर ने कहा, 'खुदरा भुगतान के इस क्षेत्र में दो या तीन थर्ड–पार्टी सेवा प्रदाताओं के हाथों में कारोबार केंद्रित हो जाने से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बजाय घट सकती है। यह एक चुनौती है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है और फिर आगे चलकर इससे निपटना होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रणाली की पूर्णता या स्थिरता को कम किए बिना ही वित्तीय क्षेत्र में फिनटेक के समावेश में तेजी लाने का समग्र विषय अगले तकरीबन एक दशक में नियामकों के लिए मुख्य चुनौती बना रहेगा।

इस अवसर पर डॉ. श्रीनिवास यानामंद्रा, अनुपालन प्रमुख, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई ने कहा कि अलग–अलग नियामकीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है जिनमें से एक नियामकीय दृष्टिकोण स्टार्ट–अप के लिए होना चाहिए, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके, और दूसरा नियामकीय दृष्टिकोण बिग टेक कंपनियों के लिए होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी एकाधिकारवादी और प्रतिस्पर्धा–रोधी तौर–तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। चीन में कुछ प्रमुख बिग टेक कंपनियों के खिलाफ पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा हाल ही में उठाए गए विश्वास रोधी कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अन्य देश भी उस नजरिए पर गौर कर रहे हैं और इसे अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में दोहराने पर विचार कर रहे हैं।

प्रोफेसर थैंकोम अरुण, निदेशक, जवाबदेही और वैश्विक विकास केंद्र (सीएजीडी), एसेक्स विश्वविद्यालय, ब्रिटेन ने कहा कि वैसे तो नई तकनीकों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को नया स्वरूप प्रदान करने की क्षमता है, लेकिन पूरी आबादी की बेहतरी के लिए इस तरह की तकनीकों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि फिनटेक के जरिए आदर्श रूप से वित्तीय मध्यस्थता की लागत कम की जानी चाहिए और इसके साथ ही वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि केन्या में एम–पेसा और भारत में यूपीआई को मिली शानदार सफलता की गाथाओं के बाद फिनटेक में निवेश वैश्विक स्तर पर बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई विकासशील देश इस संबंध में भारत और केन्या जैसे देशों का अनुकरण करना चाह रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में अभिनव विकास सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से सहयोग के इस तरह के मॉडलों को दोहराए जाने की काफी गुंजाइश है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नियामकों और संबंधित कंपनियों के लिए डिजिटल लेन–देन की सुरक्षा एवं हिफाजत सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।■

जलवायु कूटनीति पर एफआईएसडी व्याख्यान

भारतीय विज्ञान कूटनीति के लिए फोरम (एफआईएसडी) ने मंगलवार, 29 जून 2021 को 'जलवायु कूटनीति' पर डॉ. व्योमा झा, जे.एस.डी, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया। राजदूत डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस और भारत के पूर्व राजदूत ने आरंभिक भाषण दिया। इस व्याख्यान के लिए उपयुक्त माहौल बनाते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य ही विज्ञान कूटनीति के दो प्रमुख उभरते क्षेत्र हैं। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन इस सदी की एक निर्णायक चुनौती है। विकासशील देशों (जिन्हें प्रमुख उत्सर्जक बताया जाता है) में उत्सर्जन और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति उच्च उत्सर्जन के बीच व्यापक असमानता को संतुलित करने की आवश्यकता है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जैसे देशों, जो उत्सर्जन में अपनी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा न होने के बावजूद काफी ज्यादा ठोस प्रयास इसमें कमी करने के लिए कर रहे हैं और जो भारी दबाव में हैं, से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। वर्ष 2050 तक 'शून्य शुद्ध उत्सर्जन' के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयासों को मजबूत करने की जरूरत है और विकासशील देशों को वित्त एवं प्रौद्योगिकी अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर धरती सुनिश्चित करने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के स्तर को नीचे लाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य 'ऋणात्मक शुद्ध उत्सर्जन' हो सकते हैं।

डॉ. व्योमा झा, जे.एस.डी, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल

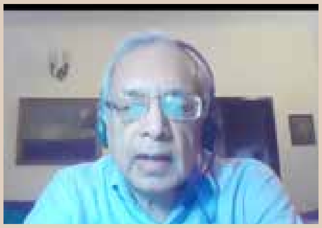

राजदूत डॉ. भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति फेलो, आरआईएस और भारत के पूर्व राजदूत

टेरी के प्रतिष्ठित फेलो राजदूत मंजीव सिंह पुरी

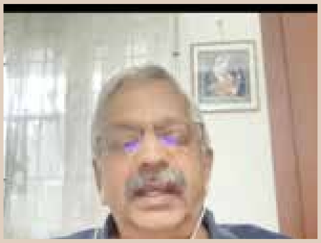

प्रो. टी. जयरामन, सीनियर फेलो, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (एमएसएसआरएफ)

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

सुश्री रेनाटा डेसलियन

प्रोफेसर वी. कामाकोटि

डॉ. ग्रेस ईडन

प्रोफेसर बर्न्ड स्टाल

एआई से जुड़ी नैतिकता और उत्तरदायी एआई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के डेवलपरों और नीति निर्माताओं को गोपनीयता को प्रभावित करने वाले सरासर झूठ (डीपफेक) और पूर्वाग्रहों के साथ–साथ उभरती प्रौद्योगिकी के हानिकारक भू–राजनीतिक निहितार्थों और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से उत्पन्न खतरों को दूर करने की आवश्यकता है। यह राय विशेषज्ञों ने दी है।

भारत में संयुक्त राष्ट्र की निवासी समन्वयक सुश्री रेनाटा डेसलियन ने नई दिल्ली स्थित अनुसंधान संस्थान आरआईएस द्वारा 19 मई 2021 को 'एआई से जुड़ी नैतिकता और उत्तरदायी एआई' विषय पर आयोजित वेबिनार में कहा कि एआई के भू–राजनीतिक निहितार्थ काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यह उभरती तकनीक विभिन्न देशों के बीच मौजूदा शक्ति संतुलन को विकृत कर रही है।

इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईआईटी मद्रास के कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर वी. कामाकोटि ने एआई के खतरों के बारे में चर्चा की, जिसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जिनमें इस प्रौद्योगिकी का उपयोग उचित ढंग से और पूरी जवाबदेही के साथ नहीं किया गया था। उन्होंने कहा, 'पहले किए गए एआई के कुछ इस्तेमाल के तहत रंगरूप के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में पूर्वाग्रह नजरिया देखा गया था।

आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि एआई, जिसकी विकासशील देशों में आर्थिक अनिवार्यता है, के नैतिक पहलुओं पर गौर करते समय लोगों तक इसकी पहुंच, समानता और समावेशन संबंधी रूपरेखा के साथ–साथ मानवीय मूल्य प्रणाली काफी अहम नजर आती है। उन्होंने कहा कि समावेशी और उत्तरदायी एआई यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत जरूरी है कि कोई भी वंचित न रह जाए और इसके साथ ही वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी यह आवश्यक है।

प्रोफेसर बर्न्ड स्टाल, निदेशक, कंप्यूटिंग और सामाजिक उत्तरदायित्व केंद्र, डी मोंटफोर्ट विश्वविद्यालय, ब्रिटेन ने कहा कि एआई से जुड़ी नैतिकता पर नियंत्रण पाने के लिए 'यह आवश्यक है कि इसे महज एक तकनीक न समझें, बल्कि एआई की परिकल्पना ऐसे इंटरलॉकिंग इकोसिस्टम के एक समूह के रूप में करें जो एआई द्वारा ही कुछ हद तक संचालित और सक्षम किए जाते हैं।' उन्होंने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां मानव के तेजी से तरक्की करने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं, यह सुनिश्चित करने का अच्छा तरीका यही है कि इसे प्रौद्योगिकी के स्वरूप के साथ–साथ सांस्कृतिक और कानूनी संदर्भ में समझा जाए।

श्री संतोष के. मिश्रा, आईएएस, सीईओ, तमिलनाडु ई–गवर्नेंस एजेंसी ने कहा कि दरअसल सरकार की एक परस्पर भूमिका है जो एआई का प्रमोटर होने के साथ–साथ एआई का नियामक होने और एआई का उपयोगकर्ता होने के भी रूप में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नैतिक मूल्यों वाले एआई पर एक नीति पेश की है। इस अधिकारी ने कहा कि ऐसा करने वाली यह संभवतः देश की पहली राज्य सरकार है और यहां तक कि महज कुछ ही सरकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि इस नीति के अनुसार, ऐसी कोई भी संस्था जो सार्वजनिक तौर पर एआई सॉल्यूशन पेश कर रही है उसे 'डीईईपीएमएएक्स' के सिद्धांत का पालन करना होगा जिसमें विविधता, समानता, नैतिकता, गोपनीयता, दुरुपयोग से संरक्षण, जवाबदेही, और विभिन्न देशों में उपयोग करना शामिल हैं और फिर उसके बाद ही यह तय करना चाहिए कि इसका उपयोग शुरू करना सुरक्षित है या नहीं।

डॉ. ग्रेस ईडन, सहायक प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली; श्री अमीन जौहर, सीनियर रेजिडेंट फेलो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी; श्री रोहित सतीश, सलाहकार, नीति आयोग एवं सीनियर फेलो, वाधवानी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस; सुश्री विदुषी मर्दा, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, अनुच्छेद 19 एवं अनिवासी अनुसंधान विश्लेषक, कार्नेगी इंडिया; और डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने भी इस अवसर पर अपने–अपने विचार व्यक्त किए। विभिन्न सरकारों और अंतर सरकारी संगठनों ने एआई सिद्धांतों के कुछ सेट विकसित किए हैं/कर रहे हैं जिनका उद्देश्य एआई से जुड़े नैतिक मुद्दों को सुलझाना है। ओईसीडी, जी20, यूरोपीय संघ, यूनेस्को, आईईईई,डब्ल्यूईएफ, और कई राष्ट्रीय सरकारों ने या तो एआई की नैतिकता से संबंधित रूपरेखा तैयार कर ली है या वे इस तरह की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

कोविड–19: मध्यमकालिक और दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने की तैयारी करने की आवश्यकता

डॉ. अमिताभ बनर्जी

35वां स्टिप फोरम व्याख्यान डॉ. अमिताभ बनर्जी, क्लिनिकल डेटा साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (ब्रिटेन), मानद सलाहकार हृदय रोग विशेषज्ञ, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन हॉस्पिटल्स, और सहायक एसोसिएट प्रोफेसर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारत द्वारा 25 मई 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय था 'कोविड–19: आईसीयू, अस्पताल और अल्पकालिक उपायों से परे तत्काल आवश्यकता'। प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), नई दिल्ली ने सत्र की अध्यक्षता की। श्री सुनीत टंडन, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर; और डॉ. के. रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस ने संक्षिप्त स्वागत भाषण दिए।

डॉ. बनर्जी ने यह दलील दी कि वर्तमान महामारी को 'सिंडेमिक' (जो दो या दो से अधिक कष्टों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का एक समूह होता है, जो आपस में सहक्रियाशील होते हैं, और जो विशाल आबादी में बीमारी का अतिरिक्त बोझ बढ़ा देते हैं) कहना शायद ज्यादा सही होगा, अतः इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बेहतर समेकित एकीकृत देखभाल वाले तौर–तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।

अपने संबोधन का समापन करते समय डॉ. अमिताभ बनर्जी ने स्पष्ट किया कि कोविड–19 प्रोटोकॉल को अपनाना और टीकाकरण सहित सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय ही इस महामारी से निपटने का मुख्य आधार हैं, और एक अत्यंत सक्रिय सरकार के साथ–साथ समुदाय की व्यापक भागीदारी वाली मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ही इस महामारी से प्रभावकारी ढंग से निपटने में काफी मददगार साबित होगी। डॉ. अमित कुमार, सहायक प्रोफेसर, आरआईएस ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ■

36वाँ विज्ञान तकनीकी नवरचना नीति व्याख्यान

36 वां विज्ञान तकनीकी नवरचना नीति संगोष्ठी व्याख्यान डॉक्टर रेनू स्वरूप, सचिव, जैव प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने दिनांक 5 अगस्त 2021 को ऑन लाइन माध्यम से दिया। विषय था: 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी और महामारी।' कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ विभा घवन, महानिदेशक, टेरी ने की। डॉक्टर भास्कर बालाकृष्णन, विज्ञान कूटनीति सहचर, आर आई एस ने स्वागत अभ्युक्ति दी। श्री सुमित टंडन, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर ने संक्षिप्त टिप्पणी की।

The lecture in progress.

अपने बहुत ही व्यवहारिक संबोधन में डॉ स्वरूप ने प्रमुख पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। विज्ञान क्या कर रहा है और किस तरह महामारी के लिए प्रौद्योगिकी प्रतिक्रिया और विरोधी प्रतिक्रिया में सक्षम नीति वातावरण बनाया गया। परिचलित नीति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण द्वारा हमारी शैक्षणिक संस्थानों में उद्योगों को एक साथ लाना आवश्यक है तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग संबोधित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

37वाँ एसटीआईपी संगोष्ठी व्याख्यान

37वाँ एसटीआईपी फोरम व्याख्यान डॉ आशुतोष, आचार्य, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अध्यक्ष, अकादमिक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान ने 29 सितंबर 2021 को ऑनलाइन माध्यम से दिया। व्याख्यान का विषय था: "खादय प्रसंस्करण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था : किसानों तथा स्वयं सहायता समूह के लिए प्रौद्योगिक विकल्प।" कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉ देवप्रिया दत्ता, वैज्ञानिक–जी, प्रमुख, बीज प्रभाव और राष्ट्रीय भूस्थानिक कार्यक्रम विज्ञान विभाग और प्रौद्योगिकी ने। डॉक्टर भास्कर बालकृष्णन, विज्ञान राजनेय सहचर, आर आई एस ने स्वागत टिप्पणी दी। श्री सुमित टंडन ने भी टिप्पणी दी। अपने बहुत ही व्यवहारिक संबोधन में डॉ उपाध्याय ने विषय से संबंधित मुद्दों पर बात की जिनमें प्रमुख है भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण का महत्व, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। खादय प्रसंस्करण के कम शेयर को देखते हुए, भारत में खादय पदार्थ की बर्बादी की गंभीर समस्या है। विशेष रुप से फलों और सब्जियों के संदर्भ में। इसलिए खादय प्रसंस्करण क्षेत्र में एक विशाल गुंजाइश और अवसर है जिसका उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किया जा सकता है।

डॉ उपाध्याय ने कुछ सफल प्रकरणों का भी उल्लेख किया। जिनमें एनआईएफटीएम के हस्तक्षेप ने स्वयं–सहायता समूह के भीतर बेहतर समझ पैदा की जिससे वह और वैज्ञानिक पद्धतियां से बेहतर खादय प्रसंस्करण कर सके। संस्थागत सहायता समूह ने भी इन समूहों की मदद की ताकि वह गुणवत्ता तथा सुरक्षा मापदंड के अनुसार उत्पादन कर सके।

जिससे कई तरह की खाद्य प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकियों उपलब्ध है जिससे बेहतर संपुष्टि के द्वारा फलों और सब्जियों का बेहतर इस्तेमाल संभव हो सकता है।

उन्होंने इस बात का भी विस्तृत विवरण दिया कि किस प्रकार और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कोशिश की है जैसे प्रधानमंत्री छोटी खाद्य प्रसंसकरण उद्योगों का और परिकरण ा। इसका उद्येश्य है वित्त तकनीकी तथा अन्य आवश्यक सहायता के माध्यम से छोटे उद्यमों का उन्नयन किया जा सके। यह योजना 2020 में शुरु की गई थी। ■

38वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंच व्याख्यान

38वां विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति मंच व्याख्यान, प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, निदेशक, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल, उत्तराखंड ने 29 अक्टूबर, 2021 को ऑनलाइन माध्यम से दिया। विषय था 'भारत में जमीन और अंतरिक्ष आधारित मंचों से सौर भौतिकी का विकास'। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अर्नब राय चौधरी, भौतिकी विभाग, आईआईएससी, बेंगलुरु ने की। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉ नकुल पाराशर ने स्वागत भाषण दिया।

अपने दूरदर्शितापूर्ण संबोधन में प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने भारत में सौर भौतिकी की स्थिति और संभावना का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने देश भर में विभिन्न स्थानों पर मौजूद सौर सुविधाओं का विस्तृत विवरण देकर अपने व्याख्यान की शुरुआत की और विषय की तकनीकी बारीकियों को समझाया। उन्होंने बहु–अनुप्रयोग सौर दूरबीन, यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जैसे परिष्कृत उपकरणों के बारे में बात की, जो सूर्य, सनस्पॉट, सोलर फ्लेयर्स आदि में अलग–अलग टाइमस्केल की परिवर्तनशीलता का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है। प्रो बैनर्जी ने प्रस्तावित राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन के बारे में भी विस्तार से बताया जो कि 2एम क्लास ऑप्टिकल और देश में नियर इंफ्रा–रेड ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी होगा। इसे 0.1–0.3 आर्क–सेकंड के स्थानिक विभेदन पर सौर चुंबकीय क्षेत्रों की उत्पत्ति और गतिशीलता से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक मुद्दों की एक सारणी को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंतरिक्ष–आधारित मिशन और जमीन–आधारित एमएएसटी टेलीस्कोप (उदयपुर) से बड़ी संख्या में सौर वायुमंडलीय पर्यवेक्षणों की सम्भाल और पुष्टि करने के लिए उपकरण में व्यापक प्रबन्ध है। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

39वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान

22 दिसंबर, 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 39वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे, ऊर्जा स्वराज फाउंडेशन के संस्थापक और मध्य प्रदेश राज्य के लिए सौर ऊर्जा के ब्रांड एंबेसडर द्वारा दिया गया था। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय थाः 'सौर के माध्यम से भारत में ऊर्जा स्वराज्य को साकार करनाः ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन सुनिश्चित करना'। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ भास्कर बालकृष्णन (ग्रीस में भारत के पूर्व राजदूत), विज्ञान राजनेय, आरआईएस ने की। डॉ कृष्णा रवि श्रीनिवास ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद डॉ विभा धवन, डीजी, टेरी और श्री सुनीत टंडन, निदेशक, इंडिया हैबिटेट सेंटर ने संक्षिप्त टिप्पणी की।

प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी

अपने बहुत ही व्यावहारिक और विचारोत्तेजक संबोधन में, प्रोफेसर चेतन एस सोलंकी ने बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की घटना के संदर्भ में मौजूदा खतरनाक स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत किया, जो मानव प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला और इस पृथ्वी पर उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस खतरनाक स्थिति में निर्णायक कारक जीवाश्म ईंधन यानी तेल, गैस और कोयले से प्राप्त ऊर्जा का विशाल उत्पादन और उपयोग है। आज, 80–85 प्रतिशत ऊर्जा खपत जीवाश्म ईंधन से होती है, जो कार्बन आधारित हैं; और जब उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है, तो वे वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन–डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। सीओटू लगभग 300 वर्षों तक वातावरण में रहता है और ग्रीनहाउस गैस होने के कारण, यह पृथ्वी को विश्वव्यापी वार्मिंग की ओर ले जा रहा है, जो कि अगर अभी नहीं रोका गया तो यह विनाशकारी होगा। पिछले तीस वर्षों में गैर–जिम्मेदार मानवीय गतिविधियों ने वातावरण में सीओटू की सांद्रता की अत्यधिक बढ़ा दी है, जो अब लगभग 415 पीपीएम के खतरनाक स्तर पर है। प्रो सोलंकी ने विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच द्विभाजन की ओर इशारा किया और तर्क दिया कि विकास के लिए ऊर्जा आपूर्ति में वृद्धि आवश्यक है; जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए ऊर्जा आपूर्ति में कमी लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार प्रमुख चुनौती यह है कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित किए बिना विकास को कैसे संतुलित किया जाए। उन्होंने इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए कठोर और तत्काल उपाय करने की चेतावनी दी। इस तरह के समाधान की दिशा में, प्रो सोलंकी ने तत्काल (जहां भी संभव हो) सौ प्रतिशत सौर ऊर्जा पर निर्भर करने और आत्म निर्भर बनने और ऊर्जा स्वराज्य को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने ऊर्जा स्वराज्य को साकार करने की कुंजी के रूप में 'सीमित खपत' और 'स्थानीयकृत उत्पादन' के दोहरे सिद्धांतों को सामने रखा। उन्होंने आगे ऊर्जा स्वराज्य से आजीविका सृजन, ऊर्जा स्वतंत्रता, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा अनुशासन, ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता जैसे लाभों की गणना की।

अंत में, प्रो सोलंकी ने ऊर्जा स्वराज्य प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए सभी के लिए तीन–चरणीय दृष्टिकोण के पक्ष का समर्थन किया। पहला कदम है, जितना हो सके ऊर्जा के उपयोग से बचना है (भले ही वह सौर ऊर्जा हो) – कम से कम एक तिहाई कम करने की कोशिश करके। दूसरा कदम अनुशासन का अभ्यास करके और कुशल उपकरणों का उपयोग करके जितना संभव हो सके ऊर्जा के उपयोग को कम करना है, और कम से कम एक तिहाई कम करने का प्रयास करना है; और तीसरा चरण जितना संभव हो उतना कम उत्पन्न करना है (यदि संभव हो तो, केवल एक तिहाई, वह भी स्थानीय रूप से!)। उन्होंने तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन को कम करने और ऊर्जा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बचें, न्यूनतम करें और उत्पन्न करें का यह सिद्धांत या नियम महत्वपूर्ण है। अंत में, उन्होंने ऊर्जा स्वराज्य को जन आंदोलन का स्वरूप देने की अपील की, क्योंकि इतने बड़े अनुपात की चुनौती को दूर करने के लिए अकेले सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

को–विन पर भारत–केन्या द्विपक्षीय सत्र

जीडीसी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारत के डिजिटल टीकाकरण प्लेटफॉर्म कोविन पर केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिभागियों के सामने, केन्याई सरकार द्वारा इसकी संभावित प्रतिकृति की संभावना का पता लगाने के लिए, एक प्रस्तुति दी।

इससे पहले, जीडीसी ने 19 मई, 2021 को 'कोविड से मुकाबला: वैक्सीन प्लेटफॉर्म और रोलआउट में विकासशील देशों के अनुभवों' पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में युगांडा, रवांडा, केन्या और नाइजीरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया। उसके बाद भी, जीडीसी लगातार इन देशों के संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करता रहा था, को–विन प्लेटफॉर्म को संभावित रूप से अपनाने या को–विन की तर्ज पर उनके मौजूदा टीकाकरण प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के अवसरों का पता लगाने के लिए।

प्रस्तुति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत के पर्याप्त अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमताओं के माध्यम से केन्या को संभावित उन्नयन और/या आवश्यकता–आधारित उपयुक्त समाधान प्रदान करने के लिए रास्ते खोलना था।■

अंकीय अनुक्रम सूचना: मुद्दे और निहितार्थ

आर आई एस ने 'अंकीय अनुक्रम सूचना: मुद्दे और निहितार्थ' पर 31 अगस्त 2021 को वैबिनार का आयोजन किया। आचार्य सचिन चतुर्वेदी महानिदेशक आर आई एस ने आरम्भिक टिप्पणियां की। श्री सी अचलेदर रेडी, भारतीय विदेश सेवा, (सेवानिवृत्त), निदेशक, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और अध्यक्ष, एनबीए अंकीय सूचना अनुक्रम समिति सूचना डीएसआई ने मुख्य वक्तव्य दिया।

पहले सत्र मे अंतरराष्ट्रीय विकास और रुझान पर डॉक्टर सिल्वन आबीरी की अध्यक्षता में संघीय वैज्ञानिक सलाहकार, कृषि कार्यालय जूरिख प्रतिष्ठित सहभागी थे, श्री पेरोन वेल्स, रिसर्च स्कॉलर ग्रेसियस सेंटर अंतरराष्ट्रीय कानून अध्ययन के लिए लिडेन विश्वविद्यालय डॉक्टर लोटे असवेल्ड सहायक प्रोफेसर जैव प्रौद्योगिकी विभाग डेलफ्ट विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी , डॉक्टर एमबर हॉटमैन सकॉलेज एबीएस टीम लाइबानिज संस्थान जर्मन का संग्रह सूक्ष्मजीव और कोशिका संवर्धन डॉक्टर विवियाना मूनोज, समन्वयक स्वास्थ्य और बौद्धिक संपदा की जवै विविधता कार्यक्रम दक्षिणी क्षेत्र जिनोवा। सत्र दो बीएसआई और जैव विविधता विषय पर था। भारत के लिए निहितार्थ इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एम के रमेश नेशनल लॉ स्कूल ऑफ भारत विश्वविद्यालय बैंगलोर ने की थी।

सम्मिलित सहभागी थे डॉ शिवेंद्र बजाज कार्यकारी निदेशक फेडरेशन भारत के लिए और बीज उद्योग एवं एलाइंस फॉर एग्री इन्नोवेशन, डॉ विश्वास चौहान कंसलटेंट जैव सूचना विज्ञान पुणे, सुश्री शालिनी भूटानी कानून और निधि विशेषक, नई दिल्ली और सुश्री श्यामा कोरियाकोश कानूनी प्रमुख वन्य जीव संरक्षण भारत, डॉक्टर नम्रता पाठक अनुसंधान सहयोगी, आरआईएस, एवं चर्चा करने वाला समापन टिप्पणी डॉक्टर कृष्णा ने और डॉ रवि श्रीनिवास सलाहकार आर आई एस में धन्यवाद टिप्पणी प्रस्तुत की। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

आईईए के 104वें वार्षिक सम्मेलन में सतत विकासशील अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ नवाचार और डेटा

आरआईएस ने 26 दिसंबर, 2021 को भोपाल में सतत विकासशील अर्थव्यवस्था पर फोकस के साथ नवाचार और डेटा पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इसमें शामिल प्रख्यात प्रतिभागी थेः प्रोफेसर शमिका रवि, पूर्व सदस्य, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, तथा अनुसंधान निदेशक, द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट, दिल्ली; प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन, निदेशक, आईआईएम, बैंगलोर; नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार प्रोफेसर अन्ना रॉय; प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, आरआईएस; डॉ अंकुश अग्रवाल, आईआईटी, नई दिल्ली; और प्रोफेसर डी के नौरियाल, पूर्व कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल। ■

एनआईपीएल द्वारा डिजिटल भुगतान का प्रस्ताव

आरआईएस में जीडीसी ने सेंट्रल बैंक ऑफ मोजाम्बिक से संबद्ध एक सरकारी संस्था सोसाइडेड इंटरबेनकारिया डि मोकाम्बिक (एसआईएमओ) से संपर्क किया। यह संस्था देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के नियामक के रूप में कार्य करती है। एसआईएमओ के आदेश के तहत, यह मोजाम्बिक में डिजिटल भुगतान का प्रबंधन करती है। जीडीसी ने फरवरी 2022 में एसआईएमओ और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के प्रतिनिधियों के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय सत्र का आयोजन किया था। इसके बाद, जीडीसी ने 11 मार्च 2022 को विचार–विमर्श के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (यूएनआईडीओ) और एनआईपीएल के बीच द्विपक्षीय सत्र की मेजबानी की।

दोनों सत्रों का उद्देश्य एनआईपीएल और मोजाम्बिक में डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए इसके द्वारा प्रस्तुत किए जा सकने वाले विशिष्ट समाधानों का विवरण प्रदान करना है। एसआईएमओ और यूएनआईडीओ, मोजाम्बिक दोनों के हितधारकों ने भारत से डिजिटल भुगतान समाधान ग्रहण करने में काफी दिलचस्पी दिखाई। ■

रिजर्व बैंक ऑफ मलावी के प्रतिभागी एनआईपीएल के साथ द्विपक्षीय सत्र में भाग ले रहे हैं।

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत–इथियोपिया द्विपक्षीय सत्र

इथियोपिया के प्रतिभागी द्विपक्षीय सत्र के दौरान एनएचए अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

आरआईएस में जीडीसी ने 5 मार्च 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय, इथियोपिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक द्विपक्षीय सत्र का भी आयोजन किया। डॉ मेसेरेट जेलालेम के नेतृत्व में इथियोपिया के प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान में अपने देश में इस्तेमाल होने वाली जिला स्वास्थ्य सूचना (डीएचआई–2) प्रणाली को आगे बढ़ाने के प्रति इथियोपिया की दिलचस्पी व्यक्त की। उन्होंने सी–19 और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों, दोनों के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के प्रति अपनी दिलचस्पी दोहराई। इस बात पर भी बल दिया गया कि एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जिसे इंटरऑपरेबल कार्य के लिए उनकी वर्तमान प्रणालियों के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने अपने कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया। ■

एनआईपीएल द्वारा डिजिटल भुगतान के प्रस्ताव पर रवांडा के साथ द्विपक्षीय सत्र

जीडीसी ने सह–शिक्षण और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, भारत द्वारा प्रदान किए गए उचित प्रस्तावों को उपयुक्त रूप से अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नेशनल बैंक ऑफ रवांडा के साथ संबंध स्थापित किए हैं। रवांडा की टीम को 5–6 मार्च 2022 को एक्सपो 2020, दुबई में कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। दुर्भाग्यवश कोविड–19 की वजह से यात्रा पर लगे प्रतिबंधों के कारण उन्होंने एक्सपो में स्वयं भाग न लेकर वर्चुअल सत्र में शामिल होने को ज्यादा बेहतर समझा। रवांडा का नेतृत्व नेशनल बैंक ऑफ रवांडा की पेमेंट सर्विसिज के निदेशक श्री करमुका बगिरिश्य जॉन ने किया। इस कार्यक्रम में एनआईपीएल की डिजिटल भुगतान से संबंधित पेशकशों को प्रदर्शित किया गया। इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। 16 मार्च 2022 को आयोजित किए गए इस वर्चुअल सत्र की नेशनल बैंक ऑफ रवांडा के अधिकारियों ने भरपूर सराहना की। ■

को–विन टीकाकरण प्लेटफॉर्म पर भारत–दक्षिण सूडान द्विपक्षीय सत्र

दक्षिण सूडान के प्रतिभागी द्विपक्षीय सत्र के दौरान एनएचए अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं।

आरआईएस में जीडीसी ने 5 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय, के प्रतिनिधियों के बीच एक द्विपक्षीय सत्र का आयोजन किया। दक्षिण सूडान के प्रतिनिधियों और एनएचए के बीच यह व्यापक तकनीकी आदान–प्रदान का अवसर था। दक्षिण सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश में वर्तमान में उपयोग में लाई जाने वाली प्रणाली की तुलना में अधिक क्षमताओं से युक्त डिजिटल प्रणाली ग्रहण करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण रूप से आंकड़ों की प्रविष्टि और उन्हें प्रॉसेस करने में सहायक प्रणालियों के प्रति दिलचस्पी व्यक्त की, जिसके लिए को–विन में सुनिश्चित संख्या है।

एनएचए के प्रतिनिधि ने दक्षिण सूडान की दिलचस्पी के अनुसार को–विन सिस्टम के पहलुओं को लागू करने की भारत की इच्छा साझा की। इस प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते एनएचए की ओर से अपार संभावित सहायता मौजूद है। प्रतिभागियों ने पास्परिक दौरों के आदान–प्रदान, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, आदि के माध्यम से संबद्धता बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

कुंजीपटल भुगतान तल में सहयोग और वित्तीय तकनीक समाधान

अमर सिन्हा

डी जानकीरमन

डॉ इमेन्युअल मुन्गो

प्रियदर्शी दाश

आर आई एस के वैश्विक केन्द्र ने 22 जुलाई 2021 को कुंजीपटल वित्तीय समावेश और विकासशील देशों में तेजी से उभरती भुगतान प्रोद्योगिकी पर वेबीनार का आयोजन किया। जिसमें प्रमुख वक्ता थेः आचार्य डी जानकीरमन, निदेशक, विकास और बैंकिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, आर बी आई; राजदूत डॉ मोहन कुमार, अध्यक्ष, आर आई एस; श्री रितेश शुक्ला, सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्राधिकरण; महोदय, गणेश अनंतानारायण, संचालन अधिकारी, एयरटेल पेमेंट बैंक; महोदय कैनडी किपकेमबोई, नियामक विशेषज्ञ, मोबाइल वित्त कार्यक्रम, कीनया; महोदय मैके आओमू, निदेशक,राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली, बैंक ऑफ युगांडा; और सुश्री ओलाडनिके कोलावोले, प्रमुख, एजेंसी बैंकिंग, नाइजीरिया।

राजदूत अमर सिन्हा, अध्यक्ष, सलाहकार समिति जीडीसी ने भी अपने अनुभव को साझा किया। भारत सहित विकासशील दुनिया और अफ्रीका को मुख्यधारा में कुंजीपटल भुगतान करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। डॉ प्रियदर्शी, सहभागी आचार्य, आर आई एस ने कार्यक्रम का संचालन किया। ▪

डिजिटल भुगतान पर भारत–मलावी द्विपक्षीय सत्र

आरआईएस में जीडीसी ने एनआईपीएल और रिजर्व बैंक ऑफ मलावी के बीच एक द्विपक्षीय सत्र के आयोजन को सुगम बनाया। सत्र की अध्यक्षता आरआईएस शासी परिषद के सदस्य डॉ शेषाद्री चारी ने की। यह द्विपक्षीय सत्र मलावी के स्थानीय संदर्भों के आधार पर वहां की विशिष्ट आवश्यकताओं के संबंध में गहन तकनीकी आदान–प्रदान का एक अवसर था।

सत्र के दौरान, मलावी की टीम ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों की ओर कदम बढ़ाने के संबंध में अपने देश की योजना का विवरण प्रस्तुत किया तथा यूपीआई और रुपे कार्ड के साथ भारत के अनुभव के आधार पर अनुभव साझा करने और एक–दूसरे से सीखने की क्षमता की सराहना की। उन्होंने इस तरह की प्रणाली को लागू करने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ मलावी की प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। दूसरी ओर, एनआईपीएल की टीम ने विस्तृत तकनीकी विवरण, कार्यान्वयन और परिचालन के तौर–तरीकों, वित्त पोषण की व्यवस्था आदि प्रस्तुत किए और मलावी प्रतिनिधिमंडल द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके अलावा संचालन संबंधी लागत, क्षमता निर्माण की आवश्यकताएं सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। एनआईपीएल टीम और मलावी प्रतिनिधिमंडल ने अपने संपर्क के अगले चरणों पर भी सहमति व्यक्त की। ▪

यूरोपीय क्षितिज

आर आई एस और भारतीय विज्ञान मंच ने संयुक्त रूप से यह यूरोपीय क्षितिज पर एक वेबीनार 23 अगस्त 2021 को आयोजन किया गया। कार्यक्रम का केन्द्र था विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आर आई एस ने स्वागत भाषण और आरम्भिक टिप्पणियां दी। सुश्री निएनके बुईसमन, प्रमुख, अनुसंधान और नवप्रवर्तन, यूरोपीय आयोग, डॉ अरविंद मिश्रा, वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार और श्री संदीप चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, यूरोप पश्चिम, विदेश मंत्रालय ने परिचर्चात्मक टिप्पणी की। डॉ भास्कर बालकृष्ण, विज्ञान राजनेय, आर आई एस ने सत्र की अध्यक्षता की। मुख्य सहभागी थेः– सुश्री तानिया फेडरिक, ईयू रिसर्च एंड इन्नोवेशन (आरएनआई) काउंसलर; डॉ एस. के. वार्ष्णेय, प्रमुख ,अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग, विज्ञान और तकनीक विभाग; डॉ रीता ढोडापकर, प्रमुख तकनीकी अधिकारी, विज्ञान सचिव, बीआरसी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी संस्थान; डॉक्टर जैकब विलियम्स ओवर्ग काउंसलर, नवप्रवर्तन रिसर्च और उच्च शिक्षा, रॉयल डेनिस दूतावास; डॉ मधुसूदन रेडी नंदिनी, काउंसलर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दूतावास, बर्लिन, और डॉक्टर के रवि श्रीनिवास, सलाहकार, आरआईएस। डॉक्टर भास्कर बालकृष्णन ने समापन टिप्पणी भी दी। ▪

नवीनतम प्रकाशन

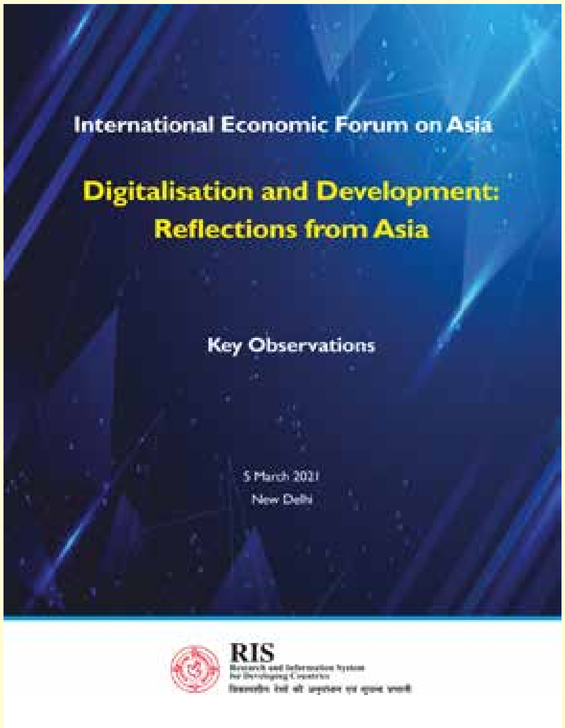

fjikVl

- **फिनटेकः भावी बैंकिंग और वित्त के लिए नई प्रौद्योगिकी**, *आरआईएस और आईआईसी, नई दिल्ली, 2021*

- **डिजिटलीकरण और विकासः एशिया की ओर से अहम विचार, आरआईएस, नई दिल्ली, 2021**

- डिजिटल भुगतान संवाद अनुभव विकासशील देशों के बीच, *जीडीसी, नई दिल्ली 2021*

- लेवरेजिंग इंडियाज डिजिटल एक्सपीरियंस इन पेमेंट्स एंड वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, जीडीसी, नई दिल्ली, 2022

vkjvkÃ,l dk ifjppk i=

#265: भारत और चीन की राष्ट्रीय एआई नीति/रणनीतिः एक तुलनात्मक विश्लेषण *द्वारा अमित कुमार*

#269: सिक्लिंग का आधार सक्रिय बहुआयामी द्वारा प्रमोद कुमार आनंद और कृष्ण कुमार

#271: रोल ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन इन द इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इन प्री–इंडीपेंडेंस इंडिया द्वारा स्नेहा सिन्हा

vkjvkÃ,l dk uhfrxr lkj&i=

#104 **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत में नौकरियों पर इसका प्रभाव** *द्वारा अमित कुमार*

#103 **रोबोटाइजेशन से भारत का वास्ताः अवसर, चुनौतियां और नीतिगत निहितार्थ** *द्वारा डॉ. कपिल पाटिल*

#102 **प्रौद्योगिकियों के जरिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में तेजी लाना** *द्वारा प्रोफेसर टी. सी. जेम्स*

foKku dVuhfr leh{kk

खंडः 3 संख्या : 1ः अप्रैल, 2021

th20 Mkbt LV

खंडः 1 संख्या : 2, अप्रैल, 2021

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे–एफआईटीएम

डॉ नम्रता पाठक
सलाहकार

फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम)

पारम्परिक ज्ञान, औषधीय पौधे, पारम्परिक चिकित्सा और जैव विविधता से संबंधित मुद्दे काफी लंबे अर्से से आरआईएस के एजेंडे में रहे हैं। उसके इसी कार्य की सराहना करते हुए आयुष मंत्रालय ने आरआईएस में फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन (एफआईटीएम) की स्थापना की है। वर्तमान में एफआईटीएम के अनुसंधान का फोकस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमर्शों में पारम्परिक चिकित्सा की बदलती भूमिका पर आधारित है। महामारी के प्रचलनों, विशेषकर गैर संचारी रोगों (एनसीडी) के बोझ में वृद्धि ने पारम्परिक हर्बल औषधियों के प्रति दुनिया भर में दिलचस्पी और प्राथमिकता को बढ़ाया है। आयुर्वेदिक और पारम्परिक चिकित्सा के अन्य उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय निर्यात में बड़े पैमाने पर हो रही वृद्धि से स्पष्ट है कि आज इन चिकित्सा प्रणालियों की मांग केवल उनके मूल देशों तक ही सीमित नहीं है। मानकों और गुणवत्ता पर नियंत्रण की एकरूपता के संदर्भ में नैदानिक अनुसंधान और विनियामक सुधारों से संबद्ध एक निकाय इसकी वैधता में वृद्धि कर रहा है। कोविड–19 ने हर्बल स्वास्थ्य उत्पादों की वैश्विक मांग को और अधिक बढ़ाने में योगदान दिया है। इसने सतत कल्याण के लिए स्वास्थ्य सेवा के निवारक और उपचारात्मक दोनों पहलुओं की स्वीकृति को संभव बनाया है। स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत पारम्परिक चिकित्सा ग्लोबल साउथ में अधिक प्रचलित होने के कारण दक्षिण–दक्षिण सहयोग का भी महत्वपूर्ण साधन बन रही है, जो अफ्रीका, बिम्सटेक और आसियान के साथ और उनके भीतर अनेक रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगों से स्पष्ट हो रहा है। पारम्परिक चिकित्सा के संरक्षण और इसके ज्ञान धारकों के अधिकारों ने ग्लोबल साउथ के साझा सरोकारों को भी डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। साथ ही इन प्रणालियों के जैव विविधता के साथ मजबूत जुड़ाव ने संसाधनों की निरंतरता और इनसे जुड़े समुदायों के अधिकार, दोनों ही मुद्‌दों को उत्पन्न किया है। जूनोटिक रोगों के महामारी के रूप में स्वास्थ्य पर भीषण प्रभाव डालने के कारण स्वास्थ्य और जैव विविधता के निरंतर उपयोग के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण तलाशने की आवश्यकता और अधिक पुष्ट हुई है। इनमें आयुर्वेद, सिद्ध और योग के संबंध में भारत के स्वास्थ्य आधारित ग्रंथों में परिभाषित दीर्घकालिक स्वास्थ्य पद्धतियों के बारे में ज्ञान स्रोतों से जानकारी ग्रहण करना शामिल है।

इस वर्ष एफआईटीएम के अनुसंधान क्षेत्रों में विशेष कर पारम्परिक चिकित्सा प्रणालियों के संदर्भ में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण से संबंधित नई प्रौद्योगिकियों और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एफआईटीएम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'भारत में आयुष क्षेत्रः संभावनाएं और चुनौतियां' एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जो पारम्परिक चिकित्सा से संबंधित वस्तुओं के उद्योग को पूर्णतया समझने की दिशा में अपनी तरह का पहला अकादमिक अभ्यास है। इसमें आयुष पारम्परिक और स्वामित्व वाली वस्तुओं तथा अर्क और औषधीय पौधों से संबद्ध

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे

उद्योगों, उनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार के आकार, निर्यात, क्षेत्रीय वितरण के साथ–साथ आयुष विनिर्माण क्षेत्र में प्रदर्शन और अवसरों का अध्ययन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर बढ़ती मांग से उत्साहित तथा आयुष मंत्रालय द्वारा विनियामक, अनुसंधान एवं विकास और बैकएंड अधोसंरचना द्वारा सक्षम पुख्ता सहायता की बदौलत भारतीय चिकित्सा प्रणाली विशेषकर योग और आयुर्वेद ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है। इस क्षेत्र में अनेक मोर्चों पर कारोबार को सुगम बनाया जा रहा है। 'मेक–इन–इंडिया' और 'स्टार्ट अप इंडिया' के तहत विशेष प्रोत्साहनों सहित भारत आयुष उद्योग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देता है। केंद्रीय स्तर पर खेती/संग्रह के माध्यम से औषधीय पौधों की सतत आपूर्ति तथा संविदा खेती में मार्केट लिंकेज के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह महसूस किया गया कि इस क्षेत्र के आकार का आकलन करके और इसकी प्रमुख शक्तियों की समझ का अध्ययन कर इसकी नीतिगत सहायता में काफी वृद्धि की जा सकती है। अध्ययन के मुताबिक इस उद्योग का अनुमानित आकार 18 बिलियन डॉलर है, इसने नीति निर्माताओं को उत्पादन की मात्रा और इस उद्योग के प्रमुख पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन के संबंध में आवश्यक समझ प्रदान की है।

जहां एक ओर आयुष के बाजार और व्यापार की संभावनाओं का आकलन, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के आयुष मंत्रालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था, वहीं, आवश्यक नीतिगत सहायता के साथ इस क्षेत्र की निर्यात क्षमता बढ़ाने की व्यवस्थाओं के बारे में हितधारकों के विचार जानने के लिए 'आयुष क्षेत्र संवर्धनः वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान' विषय पर एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया।

औषधीय पौधों का प्रमुख स्रोत जैव विविधता है, जो पारम्परिक दवाओं के लिए प्रमुख कच्चा माल है। स्थानीय समुदाय लंबे समय से जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े औषधीय ज्ञान के संरक्षक रहे हैं। पहुंच, इन समुदायों के साथ लाभ साझा करना, अधिकारों और स्वामित्व के विषय में उनकी स्थिति के मुद्दों पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस होती आई है। मानवाधिकारों पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं ने ऐसे लोगों का ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक संदर्भ में उल्लेख करने के लिए उपयुक्त शब्दों पर प्रश्न उठाए हैं। ' मूल निवासी' शब्द का उपयुक्त उपयोग और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों और विकास संबंधी कानूनी आख्यानों आकार देने के तौर–तरीके के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पृष्ठभूमि में, एफआईटीएम ने प्रोफेसर टी.सी. जेम्स, विजिटिंग फेलो, आरआईएस के पत्र 'मूल निवासी और भारत के संबंध में अंतरराष्ट्रीय चर्चा' पर आधारित पैनल चर्चा का आयोजन किया था।

जैव विविधता और इसका सतत उपयोग भी बहुपक्षीय चर्चाओं के केंद्र में रहा है, विशेषकर कोविड–19 जैसे रोगाणुओं के दुनिया भर में प्रचंड रूप से फैलने के मामले में, जहां हमने स्वीकार किया कि इस जोखिम का प्रबंधन किसी एक देश में संभव नहीं है। मनुष्यों, जीव–जंतुओं और पर्यावरण के बीच की कड़ियों, रोग के डायनेमिक्स को समझने में इन लिंक्स का महत्व तथा रोकथाम, शिक्षा, निवेश और नीतिगत विकास के लिए अंतःविषयक दृष्टिकोण के महत्व को समझना अनिवार्य है। वन हैल्थ की अवधारणा सहयोगपूर्ण, बहुक्षेत्रीय और अंतःविषयक दृष्टिकोण है, जो लोगों, जीव–जंतुओं, पौधों और उनके साझा पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध को स्वीकारते हुए इष्टतम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य से स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर काम करती है। 'वन वर्ल्ड वन हेल्थ' की मूल अवधारणा, जूनोसिस की समझ को भारत के पारम्परिक स्वास्थ्य ग्रंथों में खोजा जा सकता है। एफआईटीएम का पहला आमंत्रित व्याख्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष

प्रोफेसर जगदीश कुमार द्वारा दिया गया, जिन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे के लिए एकीकृत, बहु–विषयक दृष्टिकोण के साथ वन हेल्थ की राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिति के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की।

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्र में पारम्परिक चिकित्सा की अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस के बारे में नीतिगत अनुसंधान के अपने अधिदेश के आधार पर, एफआईटीएम ने ट्रेडिशनल मेडिसिन रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य पारम्परिक चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, व्यापार, आईपीआर, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सहयोग, कानून और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर बहस प्रारंभ करने के लिए अकादमिक आउटपुट प्रदान करना है। साल में दो बार प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2022 में निकाले गए दो अंकों में व्यापार संवर्धन, स्वास्थ्य बीमा के लिए विनियामक सुधारों से लेकर डिजिटल प्रौद्योगिकियों, शब्दावली के मानकीकरण और पारम्परिक चिकित्सा स्वास्थ्य प्रणालियों में नवाचार तक जैसे विषयों को शामिल किया गया।

एफआईटीएम के आगामी अनुसंधान आउटपुट में आयुष सेवा क्षेत्र, आयुष एमएसएमई और प्रमुख बाजारों में विनियामक मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण आधारित अध्ययन शामिल है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं में आयुष सेवाओं और संबद्ध क्षेत्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, यह क्षेत्र बेहद बंटा हुआ है, क्योंकि इसके सेवा प्रदाताओं में अस्पतालों से लेकर स्पा तक शामिल हैं। जनसंख्या और क्षेत्र के आकार के बारे में आंकड़े अत्यधिक बंटे हुए हैं। आंकड़े तैयार करने तथा क्षेत्र के निवेश और विकास क्षमता का आकलन करने के लिए इस समय सेवा क्षेत्र का अखिल भारतीय स्तर पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी तरह, आयुष वस्तुओं के उद्योग में एमएसएमई के प्रभुत्व सहित एफआईटीएम का सर्वेक्षण आधारित अध्ययन उन प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालने की दिशा में प्रयासरत है, जो वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकती हैं। तीसरा अध्ययन आयुष वस्तुओं के प्रमुख बाजारों पर केंद्रित निर्यात के लिए देश विशेष की विनियामक आवश्यकताओं के बारे में एक रिपोर्ट है।

समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रांसलेशनल रिसर्च

वैद्य श्री राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार।

40वां एसटीआईपी फोरम व्याख्यान वैद्य श्री राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 फरवरी 2022 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया गया। इस सार्वजनिक व्याख्यान का विषय 'समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से ट्रांसलेशनल रिसर्च (यानी अकादमिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग में रुपांतरण) था। कार्यक्रम का संचालन डॉ. किंकणी दासगुप्ता मिश्रा, वैज्ञानिक एफ, विज्ञान प्रसार ने किया।

वैद्य श्री राजेश कोटेचा ने समग्र स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा की जानकारी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल की प्राप्ति में पारंपरिक चिकित्सा द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारशील संबोधन की शुरुआत की। वैद्य श्री कोटेचा ने आयर्वुद के माध्यम से ट्रांसलेशनल दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए इस बारे में विस्तार से समझाया कि किस प्रकार समस्त आयुर्वेद प्रणाली अपने आप में एक व्यवस्थित ट्रांसलेशनल मॉडल है। आयुर्वेदिक ज्ञान प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना में 'तत्व' (सिद्धांत), 'शास्त्र' (सैद्धांतिक निर्माण) और 'व्यवहार' (व्यावहारिक अनुप्रयोग) शामिल हैं और इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग में रूपांतरण सुनिश्चित करना है। आयुर्वेदिक ज्ञान प्रणाली भी विज्ञान, तर्क और अनुभव के माध्यम से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है।

वैद्य श्री कोटेचा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और कार्यक्रमों की मुख्यधारा में आयुष को सम्मिलित करने के कुछ सफल उदाहरण साझा किए। उन्होंने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), सुप्रजा पहल जैसे राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल (आरसीएच) कार्यक्रम, वायु मित्र के माध्यम से जराचिकित्सा, प्रशामक सेवाओं (कारुण्य) में आयुष को सम्मिलित करने के मामलों को रेखांकित किया। वैद्य श्री कोटेचा ने 75,000 स्कूलों में आयुष प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की दिशा में आयुष मंत्रालय की ओर से की गई एक नई पहल आयुर्विद्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने महामारी के दौरान देश भर में कोविड–19 पर किए गए व्यापक आयुष अनुसंधानों की सूची भी साझा की।

अंत में, वैद्य श्री राजेश कोटेचा ने सफलता की राह के रूप में कुछ प्रमुख संकेतक भी प्रस्तुत किए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ अधिक अंतर्विषयक सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययनों को सुगम बनाने, एक राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान संघ की परिकल्पना करने, उद्योग–अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने तथा साक्ष्यों और अनुभवों को व्यवहार में रूपांतरित करने के लिए ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए सहज ज्ञान या इंट्यूशनल व्यवस्था कायम करने का आह्वान शामिल था। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे–एफआईटीएम

‘आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहन : वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान’

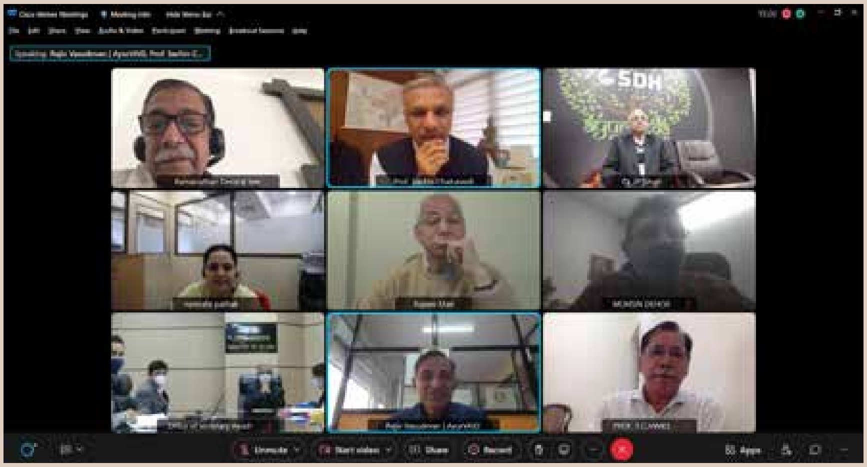

आयुष मंत्रालय ने भारत को वैश्विक क्षमता और पैंठ के साथ आयुष उत्पादों के विनिर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं और वह कई उपक्रमों पर काम कर रहा है। घरेलू क्षमता और निर्यात बढ़ाने तथा भारत को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाने, आयात पर निर्भरता घटाने और घरेलू स्तर पर निर्मित आयुष उत्पादों की लागत में कमी लाते हुए उन्हें किफायती बनाने की रणनीति महत्वपूर्ण हो जाती है।

आरआईएस में एफआईटीएम ने उद्योग जगत के नीतिगत समर्थन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण घटकों की पहचान करने की दृष्टि से उद्योग जगत और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए गोलमेज चर्चा का आयोजन किया। ‘आयुष क्षेत्र को प्रोत्साहनः वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान’ विषय पर वर्चुअल गोलमेज चर्चा 14 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसमें आरआईएस के महानिदेशक प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने उद्घाटन भाषण दिया। वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए आयुष उत्पादों की श्रेणियों पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता श्री राजीव खेर, विशिष्ट फेलो, आरआईएस, नई दिल्ली ने की और धन्यवाद ज्ञापन डॉ नम्रता पाठक, परामर्शदाता, आरआईएस, नई दिल्ली ने दिया। ■

एफआईटीएम की ओर से ‘वन वर्ल्ड वन हैल्थ’ पर आमंत्रित व्याख्यान श्रृंखला

एफआईटीएम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विषय के विशेषज्ञों द्वारा आयुष प्रणाली के विकास और उसकी वैश्विक संबद्धता के बारे में अपने विचारों और अनुभवों पर मंथन किए जाने के उद्देश्य से आमंत्रित व्याख्यान श्रृंखला आरंभ की है। पहला आमंत्रित व्याख्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार द्वारा 16 फरवरी 2022 को ‘वन वर्ड वन हैल्थ’ विषय पर दिया गया। इस अवसर पर आरआईएस के महानिदेशक प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण दिया और कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने की। प्रो. कुमार ने अपने व्याख्यान में वन हैल्थ के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक मूलभूत कदमों के रूप में एकीकृत स्वास्थ्य दृष्टिकोण सहित बीमारियों के जल्द निदान, आंकड़ों के सृजन और उन्हें सार्वजनिक क्लाउड सिस्टम के माध्यम से साझा करने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने मवेशियों के साथ ग्रामीण आबादी और समुदायों की व्यापक संबद्धता के कारण पशुओं के रोगों के प्रति उनकी अरक्षितता पर विचार करते हुए विशेष रूप से ‘वन हैल्थ वन वर्ल्ड’ रणनीति की आवश्यकता का समर्थन किया। उन्होंने पशुओं से इंसानों को होने वाली बीमारियों के निदान और रोकथाम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों के सामर्थ्य को देखते हुए वन हैल्थ के लिए इनके महत्व पर जोर दिया और आधुनिक चिकित्सा के साथ इसके प्रमाणीकरण पर बल दिया। आरआईएस में विजिटिंग फेलो, प्रो. टी.सी. जेम्स ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस व्याख्यान में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जापान आदि के कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। ■

नई प्रौद्योगिकियां और विकास के मुद्दे–एफआईटीएम

मूल निवासी और भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा

जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच और उनके लाभ साझा करने से संबंधित मुद्दों के संबंध में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा अपनाया गया रुख, भारतीय समाज के समृद्ध ताने–बाने की रचना करने वाले विभिन्न समूहों के लोगों को मूल निवासी मानने के उसके दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करता है।

हालांकि, मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं ने अलग–अलग स्थिति वाले लोगों, चाहे वे ऐतिहासिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से अलग हों, को संदर्भित करने वाली उपयुक्त शब्दावलियों पर कुछ सवाल उठाए हैं। 'मूल निवासी' शब्द का उपयुक्त उपयोग तथा अधिकारों और विकास के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर, यह कानूनी आख्यानों को कैसे आकार देता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है।

इसी पृष्ठभूमि में, एफआईटीएम ने 16 मार्च 2022 को आरआईएस के विजिटिंग फेलो प्रोफेसर टी.सी. जेम्स द्वारा लिखित चर्चा पत्र *'इंटरनेशनल डिस्कशंस ऑन इन्डीजनस पीपुल एंड इंडिया'* पर आधारित एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

इस पैनल चर्चा की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने की। इस पैनल चर्चा में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह, दिल्ली उच्च न्यायालय, श्रीमती भास्वती मुखर्जी, नीदरलैंड में भारत की पूर्व राजदूत और श्रीमती उमा शेखर, अपर सचिव (एल एंड टी) विदेश मंत्रालय सम्मिलित हुईं।

माननीय राज्यसभा सदस्य और संसदीय राजभाषा समिति की उप–समिति के संयोजक श्री राम चंद्र जांगड़ा ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। ■

नवीनतम प्रकाशन

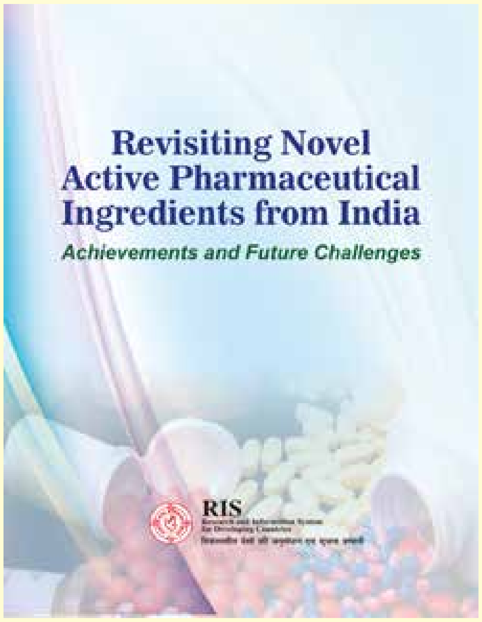

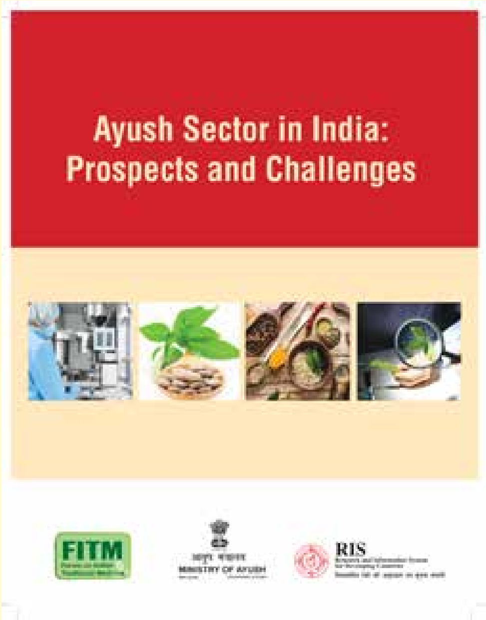

fjikVl

- **भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की सार्वजनिक नीति और आर्थिक विकास केस स्टडी,** *आरआईएस, नई दिल्ली, 2021*

- **भारत में नई पीढ़ी के डीएफआईः अवसर और चुनौतियां,** *आरआईएस और आईआईसी, नई दिल्ली, 2021*

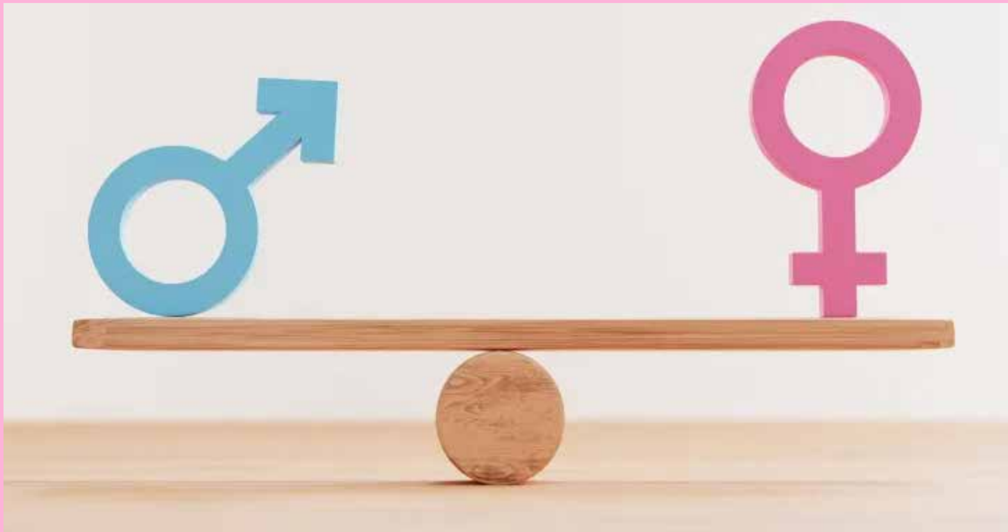

डॉ बीना पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर

सामाजिक एकजुटता के परिप्रेक्ष्य में स्त्री–पुरुष समानता

महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों के आलोक में स्त्री–पुरुष समानता राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा है, जो विकसित और विकासशील, दोनों ही तरह के देशों की महिलाओं के समक्ष मौजूद उन सामान्य समस्याओं पर केंद्रित है, जो लम्बे अर्से से बरकरार हैं। स्त्री–पुरुष समानता केवल एक मौलिक मानवाधिकार भर नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण, सामाजिक एकजुटता और टिकाऊ दुनिया के लिए आवश्यक आधार भी है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी नौकरी तक समान पहुंच तथा राजनीतिक और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान करने से टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा और इससे समाज और मानवता को समग्र रूप से लाभ होगा।

राष्ट्रों के विकास में प्रभावी योगदान देने वाली, विभिन्न जिम्मेदारियों का वहन करने वाली, बच्चों के पालन–पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और परिवार की आय में वृद्धि करने वाली महिलाओं के साथ अभी तक हर स्तर पर खुलेआम भेदभाव किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उपायों, पहलों और प्रयासों के बावजूद, पूरी दुनिया में स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, राजनीतिक भागीदारी के संबंध में स्त्री–पुरुष असमानता अभी तक मौजूद है। हालांकि, प्राथमिकता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में निवेश सामाजिक समानता, समावेशी विकास, सामाजिक एकजुटता और साझा समृद्धि हासिल करने की भी पूर्व शर्त है। स्त्री–पुरुष समानता और सामाजिक एकजुटता के बीच सीधा संबंध है, क्योंकि अधिक समानता वाला समाज अधिक एकजुट समाज होता है।

जेंडर के आधार पर भेदभाव और स्त्री–पुरुष में असमानता का चलन वैश्विक समुदाय के सामने सबसे प्रासंगिक सामाजिक समस्याएं रही हैं। पिछले कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर की गई सिलसिलेवार पहलों के माध्यम से इन समस्याओं पर विशेष रूप से काफी ध्यान दिया गया है। इस प्रक्रिया को औपचारिक रूप से वर्ष 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया विशेष रूप से वर्ष 1975 से शुरू हुई, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में नामित किया गया था, जब मैक्सिको में प्रथम विश्व महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद सन् 1995 में बीजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में इसे प्रमुख बल मिला, जिसने पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण को एक नया विज़न देते हुए एक नए युग का सूत्रपात किया। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में लागू की गई विभिन्न विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन, निरक्षरता, अज्ञानता, भेदभाव, असमानता और हिंसा जैसी समस्याएं आज भी बरकरार हैं। किसी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक तथा समग्र विकास के लिए आवश्यक होता है कि जाति, पंथ, धर्म या जेंडर के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

पिछले कुछ दशकों से, जेंडर और विकास पर वास्तव में काफी चर्चा हुई है। आमतौर पर, ये चर्चाएं मुख्यतः गरीब अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समान अवसर, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही हैं, जहां मानव अभाव को अक्सर भोजन, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और नौकरी के अवसरों तक सीमित और असमान पहुंच के संदर्भ में दर्शाया जाता है। परिणामस्वरूप, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी की गई या उनकी उपेक्षा की गई, जैसा कि सामाजिक विचारकों द्वारा तर्क दिया जाता रहा है कि प्राथमिकता के तौर पर महिलाओं को राजनीतिक या सार्वजनिक निर्णय लेने में भागीदारी के अधिकार की बजाय पर्याप्त भोजन, बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के अवसरों की आवश्यकता है।

जेंडर का मसला संयुक्त राष्ट्र के पहले विकास दशक 1960–70 के दौरान सामने आया, जब यह पाया गया कि समुदाय के जीवन को समग्र रूप से बेहतर बनाने संबंधी नियोजित विकास के प्रयास या तो महिलाओं की मदद नहीं कर पा रहे थे या वास्तव में उन्हें कई तरह से नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसी स्थिति वास्तव में चिंता का प्रमुख कारण थी, खासकर तब, जबकि विकास का लाभ गरीबों या महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। रोज़ग़ार के अवसरों की कमी, भोजन का अभाव और अमीर तथा गरीब के बीच ध्रुवीकरण के सबूत मौजूद थे। इन सबके व निचले स्तर से मिल रहे दबावों के फलस्वरूप विकास के लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की पुनः पड़ताल की गई। दूसरे विकास दशक 1970–80 के दौरान, कई विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों ने विकास कार्यक्रमों में गरीबों और महिलाओं की भागीदारी की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।

इससे पहले 'वीमेन इन डवलपमेंट' (डब्ल्यूआईडी) के बारे में चर्चा की गई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पारंपरिक कौशल तथा क्षमताओं का उपयोग करना था। बाद में इसे बदल कर 'वीमेन एंड डेवलपमेंट' कर दिया गया, ताकि यह धारणा दूर की जा सके कि महिलाएं केवल विकास

की लाभार्थी ही नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया में भागीदार और योगदानकर्ता भी हैं। वर्ष 1980 के बाद से पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की अवधारणा लाए जाने के बाद से अब जेंडर एंड डेवलपमेंट (जीएडी) पर जोर दिया जा रहा है। यह कल्याणकारी दृष्टिकोण से बुनियादी जरूरतों और दक्षता के दृष्टिकोण में और उसके बाद महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण में भी रूपांतरित हो गया।

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, प्रगति की मौजूदा दर के मद्देनजर दुनिया भर में जेंडर के आधार पर भेदभाव को मिटने में 132 साल और लगेंगे। इसलिए, जेंडर संबंधी मुद्दों को सार्वजनिक नीति में शामिल किए जाने के महत्व पर बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वजनिक कार्रवाई और सार्वजनिक नीति, दोनों ही स्त्री–पुरुष समानता और समाजों में सामाजिक एकजुटता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, महामारी के दौरान आर्थिक विकास में सुधार लाने की प्रक्रिया में बजट और मौद्रिक नीतियों में महिलाओं से जुड़े सरोकारों को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए सही मायनों में सामाजिक समावेश पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, जो कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करने तथा मानव कमज़ोरियों या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अंतर्निहित चुनौतियों के कारण मुख्यधारा की विकास नीतियों से बाहर हो चुके समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों की रक्षा करने वाली गरीब–समर्थक नीतियां हैं। जैसा कि दुनिया भर में बुनियादी सेवाओं के प्रावधान और पहुंच में असमानता पायी जाती है, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को समान रूप से लाभ नहीं मिलता या ये समाज की गहरी असमान सामाजिक संरचनाओं के कारण विकास नीतियों की मुख्यधारा से पीछे छूट जाते हैं।

हाल ही में, वर्ष 2020 की शुरुआत से ही दुनिया ने कोविड–19 महामारी के भीषण प्रभावों का सामना किया है, जिसके विविध नए वैरिएंट्स कुछ–कुछ समय के अंतराल पर पनपते रहे हैं। इस महामारी ने पुरुषों, महिलाओं, वृद्धों और यहां तक कि बच्चों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। महामारी के कारण लगे प्रतिबंध एक ही देश के भीतर व विभिन्न देशों के बीच सामाजिक व आर्थिक विकास के स्तर में पहले से ही मौजूद असमानताओं को और भी बदतर करने वाले प्रमुख कारकों में से एक रहे। महामारी के दौरान सामाजिक व आर्थिक असमानताओं के वैश्विक स्तर पर और गहराने को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। दुनिया भर में महिलाओं पर महामारी का प्रभाव न केवल सामाजिक व आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के रूप में रहा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप असमानताएं भी बढ़ी, जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक एकजुटता को बिगाड़ती हैं। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा तंत्र तक पहुंच के अभाव में महिलाओं की यह कमज़ोरी उजागर भी हो गई।

भारत दिसंबर 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए जी–20 की अध्यक्षता करेगा। जी–20 की पिछली कुछ अध्यक्षताओं की ही तरह, महिला सशक्तिकरण जी–20 के एजेंडे के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शुमार है। आमतौर पर, जब श्रम भागीदारी और अच्छी नौकरियों तक पहुंच की बात आती है, तो महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पिछली चार जी–20 अध्यक्षताओं के विश्लेषण से पता लगता है, 2018 में अर्जेंटीना को छोड़कर, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई अलग टास्क फोर्स थीम नहीं रही है। विभिन्न अध्यक्षताओं की कई टास्क फोर्स मुख्य रूप से सामाजिक एकजुटता, वैश्विक शासन प्रणाली और कल्याणकारी प्रणालियों के भविष्य आदि जैसे मुद्दों से संबंधित रही हैं, जो आंशिक रूप से महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को भी छूते हैं।

जी–20 में जेंडर के मुद्दों का पता लगाने के लिए आरआईएस ने महिला दिवस पर ही विशिष्ट पैनलिस्टों की भागीदारी के साथ 'जी–20 में महिलाओं से संबद्ध मुद्दे और आगे की राह' विषय पर विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। शुरुआत में, इस बात को रेखांकित किया गया कि ब्रिस्बेन में, जी–20 के महत्वपूर्ण भाग में वीमेन 20 (डब्ल्यू 20) ने सभी सदस्य देशों से उनकी नीतियों को जी–20 द्वारा निर्धारित '25 बाय 25' के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने का अनुरोध किया, ताकि राष्ट्रीय कार्य योजना को आगे बढ़ाकर वर्ष 2025 तक श्रम बल भागीदारी दर में महिला–पुरुष भेदभाव में कमी लाई जा सके। यह उन प्रतिबद्धताओं में से एक है, जिसे अभी अनेक जी–20 देशों में हासिल किया जाना बाकी है। इसके अलावा, जी–20 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तंत्र की प्रतिबद्धताओं में महिला–पुरुष में भेदभाव, कुशल श्रम, वित्त, जेंडर बजटिंग और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। जी–20 सदस्य देशों के वित्त मंत्रालयों की जी–20 फोरम में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो मानव विकास तथा स्त्री–पुरुष समानता को सार्वजनिक कल्याण के लिए वित्त–पोषित करने वाला एक विशिष्ट मंच है। जी–20 देशों में जेंडर बजटिंग महिलाओं से संबंधित मुद्दों से निबटने की आशाजनक संरचना है।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत की अधिकांश आबादी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आय और समग्र विकास तक पहुंच में व्यापक असमानता होने के कारण संभ्रांत लोगों के समान विकास के लाभों को साझा नहीं कर पाती। भारत का विशाल भौगोलिक क्षेत्र, विशाल जातीय और सांस्कृतिक विविधता और व्यापक स्तर पर मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाज की एकजुटता में कमी लाती हैं। सामाजिक एकजुटता हासिल करने के लिए, जाति, पंथ और जेंडर के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास की आवश्यकता है।

वास्तव में, इटली के टी–20 फाइनल कम्युनिके का मानना है कि जी–20 की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि महामारी से उबरने पर सामाजिक एकजुटता बनी रहे। इनके अलावा, इन जी–20 देशों की सरकारों को सार्वजनिक, निजी संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों के साथ घनिष्ठ साझेदारी में प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, जिससे समाज अधिक एकजुट हों और महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार हो सके।

अन्य मंचों पर नीतिगत संवाद

प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च 2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट में 'विकास सहयोग का भविष्य' पर आयोजित सत्र में पैनलिस्ट।
- ग्लोबल सॉल्यूशन समिट 2022 में 29 मार्च 2022 को टी20 इंडोनेशिया 2022 द्वारा आयोजित 'उभरते देशों की परिवहन अधोसंरचना के विकास में डिजिटल परिवर्तन' विषय पर टास्क फोर्स8 टी 20 के कार्य सत्र में पैनलिस्ट।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च,2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट के दौरान जी–20/जी–7 में एजेंडा 2030 के प्रति नए तरीकों पर आयोजित साइड–इवेंट में 'टी/जी–7/20 में निवेश प्राथमिकताओं के बारे में भारत का परिप्रेक्ष्य' विषय पर प्रस्तुति दी।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा 29 मार्च 2022 को आयोजित ग्लोबल सॉल्यूशंस समिट में 'विकास सहयोग का भविष्य' विषय पर प्रस्तुति दी।
- सेवा इंटरनेशनल द्वारा आपदा प्रबंधन पर 28 मार्च 2022 को आयोजित किए गए सम्मेलन में मुख्य वक्ता।
- कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी में यूएनआईडीओ और एसटीईपीआई द्वारा विकासशील देशों में नवाचार और औद्योगिकीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का क्षमता निर्माण विषय पर 22 मार्च 2022 को आयोजित किए गए ऑनलाइन वेबिनार में 'विकास के लिए नवाचार' पर प्रस्तुति।
- 21वीं साइंस काउंसिल ऑफ एशिया में आईसीएसएसआर द्वारा 15 मार्च 2022 को आयोजित 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान : बेहतर दुनिया के लिए एक साथ' विषय पर आयोजित सम्मेलन में सामाजिक–प्रौद्योगिकीय बदलाव और प्रमुख आर्थिक क्षेत्र' पर सत्र की अध्यक्षता की।
- वित्त उद्योग विकास परिषद (एफआईडीसी) द्वारा 15 मार्च 2022 को आयोजित इंटरैक्टिव बैठक में 'आत्मनिर्भर भारत में एनबीएफसी की भूमिका : अवसर एवं चुनौतिया' पर प्रस्तुति दी।
- जीडीआई/डीआईई द्वारा 10 मार्च 2022 को आयोजित 'यूक्रेन में युद्धः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए निहितार्थ' विषय पर ऑनलाइन गोलमेज चर्चा में पैनलिस्ट।
- सीआईआई राष्ट्रीय समिति में 4 मार्च 2022 को आसियान और महासागरीय क्षेत्र पर 'हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए उभरते अवसर' पर प्रस्तुति दी।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान (आईएससीएस) द्वारा 28 फरवरी 2022 को आयोजित 'बीबीआईएन कनेक्टिविटीः वे फॉरवर्ड' पर वेबिनार में 'बीबीआईएन कनेक्टिविटी' पर प्रस्तुति दी।
- मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी–आईडीएसए) द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, विदेश नीति, आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और महिला–पुरुष समानता के बीच बढ़ते अंतर–संबंध पर विचारोत्तेजक सत्र में भाग लिया।
- मॉरीशस विश्वविद्यालय, विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, मॉरीशस तथा हिन्द महासागर तटीय सहयोग संघ(आईओआरए) सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से 24 फरवरी 2022 को आयोजित किए गए 'कोविड–19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निरंतर नवाचार' विषय पर वर्चुअल विचारोत्तेजक कार्यशाला में 'डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्रांति' सत्र में मुख्य वक्ता।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा 23 फरवरी 2022 को आयोजित 'आर्कटिक में भारत की पहुंच का विस्तार' विषय पर इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया।
- भारत की आजादी के 75 वर्ष के समारोह के संदर्भ में 'यूरोपीय संघ–भारत के संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत में यूरोपीय संघ के नीति और आउटरीच प्रोजेक्ट द्वारा 22 फरवरी 2022 को आयोजित 'ईयू–इंडिया कनेक्टिविटी' पर वर्चुअल सत्र का संचालन किया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2022 को आयोजित 'लाइफ–जलवायु परिवर्तन से निपटने में जीवन शैली की भूमिका' पर विचारोत्तेजक बैठक में भाग लिया।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी 2022 को 'आयुष क्षेत्र संवर्धन : वित्तीय और विनियामक सहायता के लिए उत्पाद श्रेणियों की पहचान' विषय पर आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लिया।
- टी20 सचिवालय द्वारा 9 फरवरी 2022 को टी20 इंडोनेशिया 2022–स्थापना सम्मेलन में आयोजित 'वैश्विक स्वास्थ्य संरचना एवं वित्त पोषण' पर प्रस्तुति दी।
- मलयाला मनोरमा द्वारा 4 फरवरी 2022 को आयोजित 23वां मलयाला मनोरमा वार्षिक बजट प्रस्तुत किया।
- रवांडा कोऑपरेशन, एपीसी कोलंबिया और जर्मन डेवलॅपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से 19 जनवरी 2022 को साउथ–साउथ एंड ट्राइएंगुलर कोपरेशन का दोहनः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान को कैसे बढ़ाया जाए' विषय पर आयोजित साउथ–साउथ एंड ट्राइएंगुलर कोपरेशन फोरम में 'ज्ञान साझा करने में परिचालन नवाचार : प्रभावी और निरंतर संचालन के उदाहरण' विषय पर सत्र का संचालन किया।
- ग्लोबल अलायंस फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस (एपीएआर), इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएलआरआई) और अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी (एयूडीए–एनईपीएडी) द्वारा संयुक्त रूप से 19 जनवरी 2022 को 'एक स्वास्थ्य सुरक्षाः अफ्रीका में पशु चिकित्सा एवं जूनोसिस रोगों के (पुनः)उभरने से बचावः एलएमआईसी में एक स्वास्थ्य रणनीति के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियां और अवसर' में 'निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की राह की महत्वपूर्ण बाधाओं और अवसरों पर ध्यान देना' विषय पर आयोजित पैनल चर्चा में प्रस्तुति दी।
- टी20 सचिवालय द्वारा 17 जनवरी 2022 को टीएफ 8 के सह अध्यक्षों और विषयगत समन्वयकों के लिए आयोजित शुरुआती बैठक में स्थानीय और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास (पी ए–6) के प्रबंधन और वित्तपोषण पर टीएफ8 के सह–अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।
- शिव नादर यूनिवर्सिटी (एसएनयू) द्वारा 5 जनवरी 2022 को सिनर्जेंस 2022– द नॉलेज वीक के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में यूनिवर्सिटी थिंक–टैंक कनेक्ट–इनफेरेंस फॉर इंडिया–चाइना स्टडीज पर प्रस्तुति दी।
- उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की; 25–26 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशः उभरती गतिशीलता (क्लदंउपबे)' और 'मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था' पर सत्र।
- 23 दिसंबर 2021 को इंदौर में मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो के दौरान आयोजित विज्ञान नीति और प्रशासन सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया।
- क्या वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के लिए भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है, इस पर वेबिनार में 'व्यापार वार्ता के मुद्दों' पर एक प्रस्तुति दी? जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और 17 दिसंबर 2021 को आईसीआरआइईआर और एडीबीआइ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित व्यापार चर्चा से कुछ विचार।
- 15 दिसंबर 2021 को सीआईआई पार्टनरशिप समिट के 27वें संस्करण में 'अनुसंधान समुदाय और नीति निर्माताओं की शक्ति का लाभ उठानाः थिंक 20 (टी20) की भूमिका' पर सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 14 दिसंबर 2021 को कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस द्वारा आयोजित वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट) में 'बियॉन्ड बॉर्डर्सः साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द क्वाड' (सीमाओं से परेः क्वाड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग) पर सत्र का संचालन किया।
- 13 दिसंबर, 2021 को ताइवान–एशिया एक्सचेंज फाउंडेशन (टीएईएफ) और ताओयुआन सिटी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ताओयुआन में 2021 रेजिलिएंट सिटीज़ फोरम में सुशासन के माध्यम से सहभागी लोकतांत्रिक शहरों को बढ़ावा देनाः सतत अर्थव्यवस्था, सुशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' की प्रस्तुति दी।
- विज्ञान में रचनात्मकता का जश्न पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) के 7वें संस्करण के दौरान 11 दिसंबर, 2021 को आयोजित 'शमन और अनुकूलन उपायः कार्य योजना' पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- विकल्प की आवश्यकता पर द इंडियन फ्यूचर्स द्वारा 10 दिसंबर,

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

2021 को आयोजित इंद्रप्रस्थ भव्य रणनीति सम्मेलन (इंद्रप्रस्थ ग्रैंड स्ट्रैटेजी सम्मेलन) में 'उभरते वैश्विक आर्थिक मोर्चे' पर प्रस्तुति दी।

- जिग्नासा द्वारा 10 दिसंबर 2021 को आयोजित जिग्नासा आरोग्य मेला और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य में आयुष प्रणाली' पर चर्चा में पैनलिस्ट।
- 5 दिसंबर, 2021 को कलकत्ता विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व छात्र संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर 'क्या भारत की विदेश नीति अपने आर्थिक हितों को पूरा कर रही है' पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- 3 दिसंबर, 2021 को जापान इकोनॉमिक फाउंडेशन (जेईएफ) और चाइना इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट (सीआईआरडी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एशिया प्रशांत मंच 2021 में एशिया प्रशांत की विकास रणनीति पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 दिसंबर 2021 को सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग (सीपीडी), ढाका द्वारा आयोजित बांग्लादेश–भारत साझेदारी के 50 वर्षरू अगले 50 वर्षों की यात्रा की ओर पर संवाद के दौरान भारत बांग्लादेश व्यापार पर एक प्रस्तुति दी।
- सतत विकास उद्देश्यों के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों को बनाए रखने और सुधारने में जी20 की भूमिका पर 1 दिसंबर, 2021 को व्यापार और निवेश अनुसंधान नेटवर्क (टीआईआरएन) और आईआईएसडी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पैनल चर्चा में 'विकासशील देशों के दृष्टिकोण से सतत विकास लक्ष्यों को किस प्रकार विश्व व्यापार संगठन के नियमों में शामिल किया जा सकता है' पर एक प्रस्तुति दी।
- 30 नवंबर, 2021 को यूएन ईएससीएपी *के एपीसीटीटी* और डीएसआईआर द्वारा आयोजित संधारणीय विकास के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति (4आईआर) प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में '4IR प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने वाले वित्तीय साधनों' पर प्रस्तुति दी।
- 29 नवंबर, 2021 को प्रिया द्वारा 'विकास सहयोग के बदलते स्वरूपरू नागरिक समाज के लिए क्या भूमिकाएं?' पर आयोजित वर्चुअल संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया गया।
- 29 नवंबर 2021 को यूएनडीपी, ओईसीडी और जी20 इटालिया द्वारा आयोजित सतत विकास और समावेशी वैश्वीकरण पर छठी यूएनडीपी–ओईसीडी–जी20 कार्यशाला में उत्तर–दक्षिण, दक्षिण–दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग सहित सार्वजनिक वस्तुओं के प्रदान करने के लिए बहुपक्षवाद का नवीनीकरण पर पैनल चर्चा में पैनलिस्ट।
- 28 नवंबर, 2021 को आईसीसीआर द्वारा आयोजित अगली पीढ़ी लोकतंत्र नेटवर्क कार्यक्रम में 'कोविड के बाद भारत की आर्थिक स्थिति' पर एक सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 27 नवंबर, 2021 को एसोसिएशन ऑफ एशिया स्कॉलर्स द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर समापन भाषण दिया।
- 24 नवंबर, 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस में 'एक लचीली जैव चिकित्सा आपदा प्रतिक्रिया का निर्माणः कोविड–19 महामारी से सीख' पर आईसीएमआर तकनीकी सत्र के दौरान जैव सुरक्षा पर वैश्विक साझेदारी पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- 24 नवंबर, 2021 को ईएक्सआईएम बैंक और सीआईआई द्वारा आयोजित अफ्रीका के साथ अभिनव वित्तपोषण साझेदारी पर दूसरे सीआईआई शिखर सम्मेलन में अफ्रीका के वित्तपोषण परिदृश्य को नेविगेट करने के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
- 24 नवंबर, 2021 को Centro कम Investigaciones कम Politica Internacional द्वारा सामरिक अध्ययन पर आयोजित छठे सम्मेलन में सामरिक विवादों के क्षेत्रों के रूप में स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी पर एक प्रस्तुति दी।
- 23 नवंबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान और टीआईआरएन द्वारा आयोजित विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय पहल पर एक संवादात्मक चर्चा में अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया।
- 22 नवंबर, 2021 को ओईसीडी द्वारा आयोजित डीएसी बाहरी संबंध समूह की बैठक में भारत के विकास सहयोग पर ब्रीफिंग पर एक प्रस्तुति दी।
- 22 नवंबर, 2021 को जेट्रो बैंकॉक और ईआरआईए इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रिसर्च इंस्टीट्यूट नेटवर्क (आरआईएन) की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित किया।
- 20 नवंबर 2021, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा संवाद, दिल्ली जिमखाना क्लब द्वारा आयोजित 'क्वाडः वैश्विक

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य' पर एक प्रस्तुति दी।

- 17 नवंबर, 2021 को नीति आयोग द्वारा आयोजित प्रमुख थिंक टैंकों की बैठक में 'भारत–चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार विवरण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 16 नवंबर 2021 को कोलंबो में यूएन ईएससीएपी द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर आयोजित पांचवें दक्षिण एशिया फोरम में 'क्षेत्रीय सहयोग के लिए बेहतर और त्वरित एसडीजी उपलब्धि प्राथमिकता कार्रवाई' पर एक प्रस्तुति दी।
- 15 नवंबर, 2021 को यूनिसेफ द्वारा आयोजित 'तेजी से बदलती दुनिया में यूनिसेफ – स्थिति और प्रोग्रामिंग के लिए निहितार्थ' पर सत्र में 'दक्षिण एशियाः कोविड–19 दीर्घ संकट' पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 नवंबर, 2021 को रोम में द यूरोपियन हाउस – एम्ब्रोसेटी द्वारा अफ्रीका और मध्य पूर्व पर आयोजित दूसरे यूरोपीय कॉर्पोरेट परिषद के वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का भविष्य' पर एक प्रस्तुति दी।
- आयुष मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को आयोजित आयुर–उद्यमः कार्यक्रम में 'भारत में आयुष क्षेत्र – संभावनाएं और चुनौतियां' पर एक प्रस्तुति दी।
- 27 अक्टूबर 2021 को जनसंख्या और विकास में भागीदार, ढाका द्वारा आयोजित राष्ट्रीय दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला में 'राष्ट्रीय टास्क फोर्स और एसएससी को आगे बढ़ाने वाले साझेदार संस्थानों की भूमिका' पर सत्र का संचालन किया।
- 26 अक्टूबर, 2021 को एसए बीआरआईसीएस थिंक टैंक, बीआरआईसीएस, जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट और जोहान्सबर्ग इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स और इब्साः हाल के शैक्षणिक मंचों पर विचार के दौरान 'ब्रिक्स और इब्साः एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य' पर प्रस्तुति दी।
- 22 अक्टूबर 2021 को ईजीआरओडब्लू फाउंडेशन द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला में 'भारत चीन व्यापार घाटा और व्यापक व्यापार विवरण' पर एक प्रस्तुति दी।
- 13 अक्टूबर 2021 को जीआईएफटी और पटियाला के खालसा कॉलेज द्वारा आयोजित 'कोविड–19 और कोविड–19 के बाद के विश्व के लिए नवप्रवर्तन प्रणाली की पुनर्कल्पना' पर ग्लोबलिक्स–इंडियालिक्स वेबिनार में तकनीकी सत्र ए का संचालन किया।
- 12 अक्टूबर, 2021 को कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एग्रीकल्चर, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च नेटवर्क, एकेडमी ऑफ ग्लोबल फूड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज चाइना सेंटर, यूके, नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक द्वारा आयोजित 'वैश्विक गरीबी और ग्रामीण पुनरोद्धारः चुनौतियां और अनुभव' पर वेबिनार में पैनलिस्ट।
- 12 अक्टूबर 2021 को सीआईआई द्वारा आयोजित सीआईआई सीपीएसई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फोरम की पहली बैठक में भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष पर एक प्रस्तुति दी।
- 8 अक्टूबर, 2021 को एक्ज़िम बैंक द्वारा आयोजित भारत – जापान आर्थिक भागीदारीः व्यापार और परे वेबिनार में 'एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर परिप्रेक्ष्य' प्रस्तुति दी।
- पुस्तक 'वैश्विक विकास–सहयोग की उत्पति, विकास एवं भविष्य' पर परिचर्चा में भाग लिया जिसका आयोजन जर्मन विकास संस्था ने 29 सितंबर 2021 को किया।
- भारत और आसियान का द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार संबंधों पर परिचर्चा में भाग लिया जिसका ऑनलाइन आयोजन आसियान के आर्थिक अनुसंधान सन्साधन ने 21 सितंबर 2021 को किया।
- दक्षिण सहयोग में कार्यप्रणाली में विविधता के प्रभाव का निर्धारणः दक्षता के परिपेक्ष्य में संश्लेषण विषय पर प्रस्तुती 13 सितम्बर को यूएनओएसएससी और यूएनडीपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दी।
- इस्लामिक विकास बैंक द्वारा आयोजित परिचर्चा 'अनिश्चित समय में विकास सहयोग को सशक्त करना' में 9 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए स्टार्टअपस पर ऑनलाइन आयोजित परिचर्चा में 9 सितंबर 2021 को भाग लिया जिसका आयोजन आईसीएसएसआर ने किया।
- कोविड–19 और उसके बाद की स्थिति से निपटना विषय पर प्रस्तुति स्वामी विवेकानन्द संस्कृतिक केन्द्र, सीओल, दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में 2 सितंबर 2021 को दी।
- सीआईआई द्वारा आयोजित अफ्रीका समिति की ऑनलाइन बैठक में 1 सितंबर 2021 के भाग लिया।
- सतत विकास लक्ष्य और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवम नवप्रवर्तन पर प्रस्तुति 23 अगस्त 2021 को पंचायती राज मंत्रालय, भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबनार मे की।
- ब्रिक्स सहयोग के भविष्य पर विकास

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

नीति केन्द्र द्वारा ऑनलाइन आयोजित बातचीत में 11 अगस्त 2021 को भाग लिया।

- भारत और दक्षिण कोरिया के संदर्भ में आर्थिक कूटनीति पर सत्र की अध्यक्षता की जिसका आयोजन 11 अगस्त 2021 को भारत प्रतिष्ठान और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय दूतावास, सियोल ने संयुक्त रूप से की।
- आईएलओ द्वारा वेबीनार में अनौपचारिकता तथा नेटवर्कस की शक्ति विषय पर प्रस्तुति 10 अगस्त 2021 को की।
- दक्षिणीय सहयोग और समावेशी विकास रोजगार और उद्यमिता पर प्रस्तुति आईएलओ द्वारा आयोजित वबीनार में 10 अगस्त 2021 को की।
- भारत इडोनेशिया और इटली (3 आईस) के जी—20 प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा में भाग लिया जिसका ऑनलाइन आयोजन ओईसीडी ने 9 अगस्त 2021 को किया।
- सीआईआई, विदेश मंत्रालय तथा वाणिाज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वीं सीआईआई—एक्सिम बैंक सभा में भारत—अफ्रीका द्विपक्षीय व्यापार का एएफसीटीए के साथ जोड़ने के विषय पर प्रस्तुति 13 जुलाई 2021 को की।
- कल्याणकारी राज्य नीतियों और शासन विषय पर मुख्य भाषण जागरण लेकसिटि विश्वविद्यालय और कोनराड अडीनार स्टिपटंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ऑनलाईन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 12 जुलाई 2021 को दिया।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन में भागीदार सतत विकास के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए विषय पर उच्चस्तरीय संवाद में भाग लिया जिसका ऑनलाईन आयोजन घाना के संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थाई मिशन, जापान, यूएनडीसा, ईसी/जेआरसी, युनेस्को तथा यूएनईसीए न 9 जुलाई 2021 को किया।
- वैश्वीकरण की नई व्यवस्था का सामना करने विषय पर प्रस्तुत लेस रीकोनट्रस एकोलामिकी असडी एक्स—एन—प्रोवनस द्वारा आयोजित इकसवें कार्यक्रम में 4 जुलाई 2021 को की।
- 21 जून 2021 को यूरोपियन थिंक टैंक्स ग्रुप (ईटीटीजी) द्वारा 'बड़ी ताकतों से परेः यूरोपीय संघ, साझेदारियां और समावेशी बहुपक्षवाद' विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रस्तुति दी।
- 19 जून 2021 को आईआईसी द्वारा अरुणा शर्मा की पुस्तक 'डांसिंग टुवड्र्स द +5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑन ए होलिस्टिक बीट' पर आयोजित परिचर्चा की अध्यक्षता की।
- 18 जून 2021 को भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला द्वारा 'आत्मनिर्भर भारतः विचारों में स्वराज्य की ओर' पर आयोजित तीसरे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में 'भारतीय विकास मॉडल और समकालीन संबंधों का पुनरीक्षण' विषय पर उद्घाटन भाषण दिया।
- 14 जून, 2021 को इस्टिट्यूटो अफारी इंटरनेशनली (आईएआई) और अंकटाड द्वारा 'जी20 नीतिगत एजेंडे में अल्प विकसित देशों की भूमिका को बढ़ावा देना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित उच्च स्तरीय गैर—सार्वजनिक कार्यशाला में भाग लिया।
- 10 जून 2021 को ब्रिक्स थिंक टैंक सहयोग के लिए चीन परिषद और जियामेन म्युनिसिपल पीपुल्स गवर्नमेंट द्वारा 'ब्रिक्स सहयोग हेतु एक प्रतिमान बनाने के लिए साथ मिलकर नवाचार केंद्र का निर्माण करना' विषय पर संयुक्त रूप से आयोजित 2021 ब्रिक्स थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'वित्तीय नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 3 जून 2021 को दक्षिणीय सहयोग पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) और संयुक्त राष्ट्र में पुर्तगाल के स्थायी मिशन द्वारा 'बीएपीए+40 के बाद त्रिकोणीय सहयोगः 2030 एजेंडे की प्राप्ति के लिए एक बहु—हितधारक साझेदारी' विषय पर अलग से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में पैनलिस्ट थे।
- 25 मई 2021 को 'यूएनडीपी की अगली रणनीतिक योजना' विषय पर यूएनडीपी द्वारा आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 23 मई 2021 को यूटा विश्वविद्यालय द्वारा 'स्थिरता, सरलता और आध्यात्मिकताः 3S' विषय पर आयोजित सम्मेलन में 'भारतीय दर्शन और वैश्विक प्रतिबद्धताएंः सतत विकास लक्ष्यों का संदर्भ' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 7 मई 2021 को ओईसीडी विकास केंद्र द्वारा 'बहुपक्षवाद के नए अनुभव/नए आईसी—3आई बैठक' पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 27 अप्रैल 2021 को ओईसीडी द्वारा 'त्रिकोणीय सहयोग से परे भावी सहयोग' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में भाग लिया।
- 20 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र एस्कैप द्वारा 'महामारी से परेः एशिया और प्रशांत में संकट से ज्यादा मजबूती के साथ उबरना' विषय पर 2021 थीम स्टडी का शुभारंभ करने के दौरान 'भारत में एसडीजी के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्तंभों पर महामारी का प्रभाव' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 15 अप्रैल 2021 को सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सेवा बैठक में 'विकास परिवेश में भावी चुनौतियां और तैयारी' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 14 अप्रैल 2021 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द फाउंडेशन पोर ला रीचेर्चे स्ट्रेटेजिक, और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित द्वितीय भारत—फ्रांस—ऑस्ट्रेलिया 1.5 त्रिपक्षीय संवाद के दौरान 'प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा' विषय पर आयोजित परिचर्चा बैठक में आरंभिक भाषण दिया।
- 7 अप्रैल 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा 'क्रेडिटलाइन के जरिए सहित आसियान के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी की स्थापना' विषय पर आयोजित विचार—मंथन सत्र के दौरान 'डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत—आसियान सहयोग के लिए अनुशंसित परियोजनाएं' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 7 अप्रैल 2021 को ओईसीडी विकास केंद्र द्वारा आयोजित 3आई संभावित बैठक पर परिचर्चा में भाग लिया।
- 6 अप्रैल 2021 को 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य' विषय पर आयोजित विशेषज्ञ कार्य समूह की परिचर्चा बैठक में भाग लिया।

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

प्रोफेसर एस.के. मोहंती

- इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा स्थापित इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल (आईईआरए) अवार्ड: 2020 में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 21 मार्च 2022 को आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- मॉरीशस विश्वविद्यालय, विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, मॉरीशस तथा हिन्द महासागर तटीय सहयोग संघ(आईओआरए) सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से 23 फरवरी 2022 को आयोजित किए गए 'कोविड–19 के पश्चात अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए निरंतर नवाचार' विषय पर वर्चुअल विचारोत्तेजक कार्यशाला में 'आईओआरए में उभरती नीली अर्थव्यवस्था: विनिर्माण ढांचे की बदलती गतिशीलता' विषय पर प्रस्तुति दी।
- टी20 सचिवालय, जकार्ता इंडोनेशिया की ओर से 10 फरवरी 2022 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्थापना सम्मेलन में 'वैश्विक व्यापार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के बारे में पॉलिसी ब्रीफ : विकासशील देशों के लिए नीतिगत विकल्प' पर चर्चा में भाग लिया।
- 'वैश्विक व्यापार को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के बारे में टी20 पॉलिसी ब्रीफ : विकासशील देशों के लिए नीतिगत विकल्प' के बारे में 17 जनवरी, 2022 को नीतिगत सिफारिशें सौंपी और टी20 सचिवालय, जकार्ता इंडोनेशिया द्वारा 5 फरवरी, 2022 को उन्हें स्वीकार कर लिया गया।
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 2 फरवरी 2022 को आयोजित भारत–जीसीसी एफटीए पर संयुक्त कार्य समूह से संबंधित बैठक में भाग लिया।
- मध्य प्रदेश की निर्यात नीति 2022–2027 के प्रारूप पर चर्चा के लिए 10 जनवरी 2022 को लंच ऑन मीटिंग में भाग लिया।
- मध्यप्रदेश के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य–मध्य प्रदेश जीडीपी टास्क फोर्स पर योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 जनवरी 2022 को आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2020 को आयोजित इंडिया एक्जिम बैंक इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड 2020: आईईआरए अवार्ड कमेटी की दूसरी बैठक पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- नई दक्षिणी नीति पर अध्यक्षीय समिति; अर्थशास्त्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (एनआरसी) और कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, कोरिया द्वारा नई दक्षिणी नीति प्लस: दृष्टि, प्रगति और भविष्य पर संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया और भारत–कोरिया आर्थिक भागीदारी में गतिशीलता: 21वीं सदी के लिए एक मॉडल पर एक प्रस्तुति दी।
- 1 दिसंबर, 2021 को बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पर सीपीडी बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित बैठक 'बांग्लादेश–भारत साझेदारी के 50 वर्ष: अगले 50 वर्षों की यात्रा की ओर' में भाग लिया, और 'आधी सदी पुराने भारत–बांग्लादेश व्यापार की एक कहानी', पर आभासी रूप से एक प्रस्तुति दी।
- दिनांक 17 नवंबर 2021 को नीति आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित थिंक टैंक चर्चा बैठक में अध्यक्ष के रूप में भाग लिया।
- उभरते क्षेत्रीय क्रम में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पना: 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर 27 अक्टूबर, 2021 को आरआईएस, आईसीडब्ल्यूए, कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी (केएनडीए) और कोरिया गणराज्य के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति का कोरिया संस्थान (केआईईपी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहले भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता में एक वक्ता के रूप में भाग लिया और 'कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को फिर से प्रासंगिक बनाना' पर सत्र में एक प्रस्तुति दी।
- 27 अक्टूबर, 2021 को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव पर चर्चा बैठक में भाग लिया।
- 7 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित व्यापार चर्चा बैठक में भाग लिया।
- समुद्री आकीशय योजना तथा समुद्र अर्थव्यवस्था: सागर साधनों का सतत उपयोग पर एक टिप्पणी समुद्री आकीशय योजना तथा क्षेत्रीय सहयोग पर वेबीनार

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

में की जिसका आयोजन सोसाइटी फॉर इंडियन औशियन स्टडीस ने 3 सितम्बर 2021 को की।

- विदेश मंत्रालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई परिचर्चा में भाग लिया जिसका आयोजन 26 अगस्त 2021 को नई दिल्ली में किया गया।
- आयुष मंत्रालय में आयोजित भारत में आयुष क्षेत्र का भविष्य और चुनौतियों पर हुई चर्चा में टीम प्रमुख होने के नाते 9 जुलाई 2021 को भाग लिया।
- आईओआरए क्षेत्रीय समुद्री व्यापार में सम्भावनाओं का अनुमुक्त करना तथा क्षेत्रीय समुद्र व्यापार में अझेदित संभावना पर दृश्यदूर संलाप में 8 जुलाई 2021 को भाग लिया।
- 25 जून 2021 को नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया और 'भारत में आयुष क्षेत्रः संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर प्रस्तुति दी।
- 27 मई 2021 को आईएमयू चेन्नई कैंपस द्वारा 'हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के सदस्य देशों और बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के साथ साझेदारियां बनाना और समुद्री सहयोग बढ़ाना' विषय पर आयोजित कार्य क्षेत्र 2 की दूसरी बैठक में भाग लिया।
- 6 मई 2021 को नई दिल्ली में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 2020 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं और भूटानी राजनयिकों को 'नीली अर्थव्यवस्था' पर व्याख्यान दिया।
- 29 अप्रैल 2021 को आसियान–भारत अध्ययन केंद्र, विदेश मामलों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान, और कोरियाई राष्ट्रीय राजनयिक अकादमी, सियोल, कोरिया द्वारा 'कोविड बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को फिर से प्रासंगिक बनाना' विषय पर आयोजित 'प्रथम भारत–कोरिया 2+2 संवाद' में एक वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 14 अप्रैल 2021 को ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द फाउंडेशन पोर ला रीचेर्चे स्ट्रेटेजिक, और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज द्वारा आयोजित भारत–फ्रांस–ऑस्ट्रेलिया 1.5 त्रिपक्षीय संवाद 2021 में भाग लिया, और 'समुद्री वैश्विक संसाधन क्षेत्र, कनेक्टिविटी, और मत्स्य पालन की भू–राजनीति' विषय पर प्रस्तुति दी।

डॉ सब्यसाची साहा

एसोसिएट प्रोफेसर

- एसडीपीआई द्वारा 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 24वें सतत विकास सम्मेलन (एसडीसी) के दौरान 'दक्षिण एशिया में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर प्रगति पर कोविड–19 का प्रभावः क्षेत्रीय सहयोग के लिए चुनौतियां और आगे की राह' शीर्षक वाले पैनल में पैनलिस्ट (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 7 दिसंबर 2021 को ट्यूरिन में आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स और औपचारिकताः आईएलओ भागीदार परिप्रेक्ष्य' पर वेबिनार में रिसोर्स पर्सन (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 1 दिसंबर, 2021 को जी20 – टीआईआरएन (व्यापार और निवेश अनुसंधान नेटवर्क) द्वारा आयोजित 'सतत विकास उद्देश्यों के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों को बनाए रखने और सुधारने में जी20 की भूमिका' शीर्षक वाले पैनल में पैनलिस्ट (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 29 नवंबर से 3 दिसंबर, 2021 तक वी ब्रिक्स इंटरनेशनल स्कूल, मॉस्को, रूस में रिसोर्स पर्सन (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 24 से 25 नवंबर, 2021 तक काहिरा, मिस्र में आयोजित 'दक्षिणीय सहयोग पर उच्च स्तरीय एपीआरएम सहकर्मी समीक्षा मंचः अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण में चुस्ती और लचीलापन' में पैनलिस्ट। (आभासी रूप से भाग लिया)।
- 29 अप्रैल 2021 को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय में आईएफएस प्रोबेशनर्स के लिए 'ब्रिक्स की गतिशीलताः भारत के लिए अवसर और चुनौतियां' विषय पर व्याख्यान दिया।
- 24 जून 2021 को केन्या सार्वजनिक नीतिगत अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान (केआईपीपीआरए) द्वारा 'चार प्रमुख एजेंडे को पूरा करने में तेजी लाने में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीएंडआई)' विषय पर आयोजित चौथे वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया, और 'प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्रों की भूमिका – दक्षिणी नवाचार केंद्रों की ओर' विषय पर प्रस्तुति दी।

डॉ. प्रियदर्शी दाश

एसोसिएट प्रोफेसर

- भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स द्वारा 14 जनवरी 2022 को आयोजित 'फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एआई, साइबर जोखिमों और डेटा विज्ञान' विषय पर यूकेआईईआरआई–डीएसटी सम्मेलन में चर्चा में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।
- जी–20 इंडोनेशिया द्वारा बी20 इंडोनेशिया, आरआईएस और ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को ' जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी ढांचा और वैश्विक सार्वजनिक सामान' विषय पर आयोजित वर्चुअल सेमिनार के दौरान चर्चा में प्रतिभागी के रूप में भाग लिया।
- जी–20 इंडोनेशिया, टी20 इंडोनेशिया और यूएनआईडीओ

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

द्वारा 24 मार्च, 2022 को 'जी–20 देशों में और उनके अलावा डिजिटीकरण

- और पर्यावरणीय निरंतरता को आगे बढ़ाने में उद्योग के महत्व' पर आयोजित रणनीतिक गोलमेज चर्चा में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 25–27 दिसंबर, 2021 को भोपाल में आयोजित भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन में 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशः उभरती गतिशीलता' पर तकनीकी सत्र में प्रस्तुति दी।
- 9 दिसंबर, 2021 को आरआईएस और ओस्लो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'महामारी के बाद की दुनिया में भारत–अफ्रीका संबंधों पर गोलमेज सम्मेलन' में फिनटेक पर प्रस्तुति दी।
- एशिया अफ्रीका फोरम ऑन करप्शन, इंडोनेशिया द्वारा 7–8 दिसंबर, 2021 को एशिया अफ्रीका फोरम समिट ऑन करप्शन 2021 में 'लाभ स्थानांतरण, आर्थिक भगोड़ों और अवैध वित्तीय प्रवाह के संसाधन निहितार्थ' पर एक प्रस्तुति दी।
- 26–27 नवंबर, 2021 को सोका विश्वविद्यालय, जापान द्वारा दक्षिण एशिया में स्मृति और अतीत पर आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 'हिंद–प्रशांत आर्थिक विजनः भविष्य की एशियाई विकास गाथा में भारत की बड़ी भूमिका' पर प्रस्तुति दी।
- 26–27 नवंबर, 2021 को आरआईएस, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 'ब्रिक्स आभासी आर्थिक कॉन्क्लेवः वैश्विक आर्थिक सहयोग और ब्रिक्स की भूमिका को फिर से आकार देना – सहक्रियाओं और पूरकताओं की खोज करना' पर वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 24 नवंबर, 2021 को आरआईएस और जी20 रिसर्च फोरम द्वारा आयोजित 'आगामी जी20 की विकासशील देशों द्वारा अध्यक्षता के लिए टी20 सुधार' पर वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र का संचालन किया।
- 28 अक्टूबर, 2021 को आरआईएस और आईएफपीआरआई द्वारा आयोजित 'बिम्सटेक क्षेत्र में संधारणीय कृषि और मूल्य संवर्धन में सहयोग की खोज' पर वेबिनार की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- 27 अक्टूबर 2021 को आरआईएस, आईसीडब्लूए, केएनडीए और केआईईपी द्वारा आयोजित 'उभरती क्षेत्रीय व्यवस्था में भारत–कोरिया संबंधों की पुनर्कल्पनाः 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'न्यू सदर्न पॉलिसी' का तालमेल पर भारत–कोरिया 2+2 द्विपक्षीय वार्ता में "कोविड के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत–कोरिया आर्थिक साझेदारी को फिर से प्रासंगिक बनाना" पर तकनीकी सत्र में बतौर परिचर्चा प्रस्तुत किया।
- 8 अक्टूबर 2021 को एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित 'भारत–जापान आर्थिक साझेदारीः व्यापार और उससे परे' में एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर पर प्रस्तुति दी।
- डिजीटल भुगतानों पर संवादः विकासशील देशों के अनुभव विषय पर परिचर्चा का संचालन किया जिसका आयोजन वैश्विक विकास केन्द्र ने 22 जुलाई 2021 को किया।
- डिजीटल युग में सेवा व्यापार विषय पर एक प्रस्तुती ऑनलाइन संवाद में की जिसका आयोजन नीति संवाद केन्द्र, ढाका और फ्रेडरिच एबर्ट स्टिफटंग ने 19 जुलाई 2021 को की।
- 24 जून 2021 को 'डिजिटल ब्रिक्स' पर वर्चुअल रूप से आयोजित आरआईएस–ओआरएफ पैनल परिचर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में प्रस्तुति दी।
- 21 मई, 2021 को 'एसडीजी और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना' विषय पर आयोजित ब्रिक्स अकादमिक फोरम 2021 संवाद के दौरान 'बेसल नियम और विकासशील देशों में विकास वित्त का प्रवाह' विषय पर प्रस्तुति दी (वर्चुअल)।
- 28 अप्रैल 2021 को प्लेखानोव रूसी अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय, रूस द्वारा 'सीमा पार की नई वास्तविकताओं में एशियाई देश' पर आयोजित रूसी वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलन के दौरान 'विकास में डिजिटलीकरण को मुख्यधारा में लानाः एशिया की ओर से पहल और सबक' विषय पर प्रस्तुति दी (वर्चुअल)।

श्री राजीव खेर

विशिष्ठ फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'एशिया और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था : दृष्टिकोण और भावी जोखिम' विषय पर एक संगोष्ठी में भाग लिया।
- आईसीए और फिक्की द्वारा 19 मार्च 2022 को 'वैश्वीकरण के दौर में मध्यस्थता' विषय पर आयोजित सम्मेलन के चौथे संस्करण में भाग लिया।
- पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स द्वारा 16 मार्च 2022 को आयोजित 'क्या हम एक ऐसा कार्बन टैक्स डिजाइन कर सकते हैं, जिससे

आरआईएस संकाय द्वारा बाहर के प्रकाशनों में योगदान

कारोबारी टकराव उत्पन्न न हों?' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।

- एशियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा 18 फरवरी 2022 को आयोजित डायरेक्टर पावर ई–मीटिंग में भाग लिया।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 11 फरवरी 2022 को आयोजित चौथे वार्षिक सीनियर केयर कॉन्क्लेवः बिल्डिंग सिल्वर इकोनॉमी में भाग लिया।
- एयरटेल बैंक की 10–11 फरवरी 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस द्वारा 9 फरवरी 2022 को आयोजित प्रमुख सेमिनार और बुक लॉन्च– द स्ट्रगल एंड द प्रॉमिसः रिस्टोरिंग इंडियाज पोटेंशियल में भाग लिया।
- गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 1 फरवरी 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 19 और 31 जनवरी 2022 को आयोजित अनुशासनात्मक समिति – बेंच– द्वितीय की बैठक में भाग लिया।
- 31 जनवरी 2022 को व्हिसल ब्लोअर पर प्री–बोर्ड मीटिंग में भाग लिया।
- संसद टीवी द्वारा 22 जनवरी 2022 को आयोजित व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने से संबंधित बजट स्पेशल इंग्लिश प्राइम टाइम शो में आमंत्रित किया गया।
- एयरटेल पेमेंट्स बैंक ड्राफ्ट रणनीति नोट पर 18 जनवरी 2022 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- 17 जनवरी 2022 को एनएबीसीबी सलाहकार समिति के मानद सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 18 अक्टूबर, 12 नवंबर और 27 दिसंबर 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक समिति – बेंच– II बैठक में भाग लिया।
- 17 दिसंबर 2021 को आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित वेबिनार 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' में हिस्सा लिया।
- 16 दिसंबर 2021 को सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा आयोजित "अनशैकलिंग इंडियाः हार्ड ट्रुथ्स एंड क्लियर चॉइस फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल" पुस्तक के विमोचन में भाग लिया।
- 13–15 दिसंबर 2021 को सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2022 में भाग लिया।
- 10 दिसंबर 2021 को एसआईएएम द्वारा आयोजित 'विजन सस्टेनेबल मोबिलिटीः सीओपी26 के निहितार्थ' पर व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिया।
- 9 दिसंबर 2021 को सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) द्वारा आयोजित 'बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की भूमिका का पुनरीक्षण' पर प्रमुख संगोष्ठी में भाग लिया।
- 3 दिसंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'बदलते वैश्विक भू–राजनीतिक आयाम और भारत पर इसका प्रभाव' पर यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और संस्थापक इयान ब्रेमर के साथ बातचीत में भाग लिया।
- 2 दिसंबर 2021 को ट्रू नॉर्थ की 17वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।
- गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 11 और 24 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 23 नवंबर 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित 'भारत – ताइवान व्यापार सहयोग – सहक्रियाओं के निर्माण और नई भागीदारी' पर डिजिटल सम्मेलन और प्रदर्शनी में भाग लिया।
- सीयूटीएस–सीआईआरसी द्वारा 6 – 17 नवंबर 2021 को आयोजित 'प्रतियोगिता, विनियमन और विकास' सम्मेलन में भाग लिया।
- 29 अक्टूबर 2021 और 10 नवंबर 2021 को किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 22 अक्टूबर 2021 और 8–9 नवंबर 2021 को एयरटेल बैंक की बोर्ड बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 8 नवंबर 2021 को कोनराड एडीनौर–स्टिफटंग के भारत कार्यालय के सहयोग से आईसीआरआईईआर द्वारा आयोजित 'डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलनः अपेक्षित परिणाम और आगे की राह' पर वेबिनार में भाग लिया।
- 2 नवंबर 2021 को चीन पर सीआईआई कोर ग्रुप की बैठक में भाग लिया।
- सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित

'वन से जुड़ी वस्तुओं के लिए उत्पादन और व्यापार नीतियों में स्थिरता का एकीकरण' पर एक सत्र में भाग लिया।

- 27 अक्टूबर 2021 को मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अटलांटिक परिषद के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 'सीओपी26 से क्या अपेक्षाएं हैं – भारतीय व्यवसायों के लिए एक रूपरेखा' पर एक विशेष चर्चा में भाग लिया।
- 27 अक्टूबर 2021 को सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात पर फोकस' पर चर्चा में एक पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल ट्रेड (सीआरआईटी) द्वारा 26 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'संस्थागत मुद्दों और विश्व व्यापार संगठन सुधार' पर विचार–मंथन में भाग लिया।
- 21 अक्टूबर 2021 को अनंत केंद्र के सहयोग से अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली और चेन्नई और हैदराबाद में वाणिज्य दूतावासों के साथ मुंबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित 'नवीकरणीय ऊर्जा के साथ हरित अर्थव्यवस्था का विकास' पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।
- सिगुर सेंटर फॉर एशियन स्टडीज और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'महामारी के बाद की दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था' पर वेबिनार में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर द्वारा 6–8 अक्टूबर 2021 को आयोजित 'महामारी के युग में वैश्विक आर्थिक समन्वयः जी–20 सदस्यों के विचार' पर 13वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय जी–20 सम्मेलन में भाग लिया।
- भारत की परिकल्पनाः भारत को हरित सीमा में ले जाना पर जार्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वबीनार में 29 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- आईसीएआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के शासी मंडल की बैठक में 20 और 28 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- एयरटेल बैंक की 4 अगस्त 2021 और 27 सितंबर 2021 को हुई बैठकों में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से भाग लिया।
- 23 और 24 सितंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता विधि सम्मेलन का आयोजन एसोसिएट चेंबर द्वारा वाणिज्य और उद्योग के सम्मेलन में भाग लिया।
- भारत–यूके की 2030 योजनाः प्रतिस्पर्धा व्यकता, संवृद्धि, सत्तता और प्रैद्योगिकी पर सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में 17 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- शुद्ध शून्य पर पहुँचनाः भारत के लिए सीओपी 26 उपमार्ग विषय पर सीएससीपी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 16 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- प्रोद्योगिकियों द्वारा साझेदारी को प्रभावित करना विषय पर सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में 14 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- भारतीय लोक वित्त प्रणालीः राजकोषीय शासन विषय पर सीएसईपी और विश्व बैंक द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 13 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- जनसाधारण, ग्रह, समृद्धीः विशिष्टतक से पुर्ननिर्माण विषय पर आईसीआरआईईआर–केएस कोविड–19 वबेनार श्रंखला में 13 सितंबर 2021 को भाग लिया।
- किरलोस्कर ब्रदर्स लिमिटिड द्वारा आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से 9 सितम्बर 2021 को भाग लिया।
- ग्रीन हाउस रसाव को निर्माण क्षेत्र में जलवायु बदलाव में बदलाव से निपटने के लिए कम करना विषय पर सीआईआई द्वारा आयोजित तीसरी भारत–अमेरिका टाउन–हाल में 8 सितंबर का भाग लिया।
- इंडो–पेसिफिक महासागर पहल विषय आईसीडब्लूए द्वारा आयोजित परामर्श में 3 सितम्बर 2021 को भाग लिया।
- भारतीय लेखाकारों के संस्थान अनुशासन सीमित–पीट–II को बैठक में 27 जुलाई, 17, 31 अगस्त और 2, 15, 30 सितम्बर 2021 को भाग लिया।
- आईबीसी के पाँच वर्ष और आगे का मार्ग विषय पर सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में 27 अगस्त को भाग लिया।
- भारत की जलवायु कूटनीति विषय में फिक्की संसद मंच तथा कोनार्ड–अडानार–स्टिफटंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 24 अगस्त 2021 को भाग लिया।
- भारत@75: सरकार और व्यापार साथ मिलकर आत्मनिर्भर के लिए कार्य करना विषय पर सीआईआई की वार्षिक बैठक 2021 में 11–12 अगस्त को भाग लिया।
- भारत की डीकारबनाईजेशन की कार्यनीति विषय पर सीएसईपी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में 6 अगस्त 2021 को भाग लिया।
- डब्लूटीओ सुधार और भारत के उद्योग पर इसका प्रभाव विषय पर आयोजित बैठक में विशिष्ट वक्ता की हैसियत से भाग लिया।
- सत्तत कृषि मानचित्रण प्रसंस्करपित खादयानों के लिए अवसर और चुनौतिया विषय पर आयोजित वबीनार में 28 जुलाई 2021 को भाग लिया।
- गहरे व्यापार समझौता का अर्थशास्त्र पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में भाग

लिया। जिसका आयोजन विश्व बैंक ने 19 जुलाई 2021 को किया।

- भारत–अफ्रीका परियोजना साझेदारी विषय पर सीआईआई–एगजिम बैंक की 16वीं सभा में 13–15 जुलाई 2021 को भाग लिया।
- गुडईअर इंडिया लिमिटेड द्वारा बैठक में 13 जुलाई को स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से 13 जुलाई 2021 को भाग लिया।
- विदेश मंत्रालय तथा सीआईआई द्वारा इन्डो–पेसिफिक व्यापार शिखर–सम्मेलन पर आयोजित वबीनार में 6–8 जुलाई को भाग लिया।

- 30 जून 2021 को विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा 'विस्मृत कश्मीर– नियंत्रण रेखा की दूसरी ओर' पर आयोजित पुस्तक परिचर्चा में भाग लिया।
- 29 जून 2021 को आईएसआईडी–अंकटाड द्वारा 'सतत बेहतरी के लिए एफडीआई प्रवाह का लाभ उठानाः विश्व निवेश रिपोर्ट 2021' पर आयोजित नीतिगत गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।
- 29 जून 2021 को सामाजिक और आर्थिक प्रगति केंद्र द्वारा 'भारत बनाम चीनः वे मित्र क्यों नहीं हैं' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 28 जून 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा आयोजित हिंद–प्रशांत विशेषज्ञ समूह की बैठक में भाग लिया।
- 6 अप्रैल, 26 अप्रैल, 13 मई, 14 जून और 25 जून 2021 को इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अनुशासनात्मक समिति – बेंच– II की बैठक में भाग लिया।
- 21 जून 2021 को यूरोपियन थिंक टैंक्स–ग्रुप द्वारा 'बड़ी ताकतों से परेः यूरोपीय संघ, साझेदारियां और समावेशी बहुपक्षवाद' विषय पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।
- 16 जून 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'पड़ोसी पहले श्रृंखला – अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 4 जून 2021 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित आईपीआरएस 2.0 के लिए गठित संचालन समिति की 5वीं बैठक में भाग लिया।
- 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा 'व्यापार उपचार' पर आयोजित बैठक में भाग लिया।
- 2 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान और एशियाई अध्ययन के लिए सिगुर केंद्र, जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा 'भारत की परिकल्पना करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में एक चर्चाकर्ता के रूप में भाग लिया।
- 27 मई 2021 को गुडइयर इंडिया लिमिटेड द्वारा आयोजित एक बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 27 मई 2021 को पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 'भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव लानाः वैश्विक अनुभवों से सबक' विषय पर आयोजित वार्तालाप में भाग लिया।
- 24–25 मई 2021 को किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 21 मई 2021 को एशियन सेंटर फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी द्वारा आयोजित डायरेक्टर पावर ई–मीटिंग में भाग लिया।
- 20 मई 2021 को नई दिल्ली में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित एक बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 18 मई 2021 को नई दिल्ली में एयरटेल बैंक द्वारा आयोजित बैठक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लिया।
- 14 मई 2021 को विश्व डिजाइन संगठन के सहयोग से सीआईआई द्वारा आयोजित 'डिजाइन टॉक सीरीज' में भाग लिया।
- 11 मई 2021 को नई दिल्ली में 'चीन पर सीआईआई कोर ग्रुप' के एक सदस्य के रूप में भाग लिया।
- 10 मई 2021 को फिक्की द्वारा आयोजित भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2021 के मुख्य निष्कर्ष 'भारत–यूरोपीय संघ संबंधों के भविष्य' पर परिचर्चा में भाग लिया।
- 29 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'सामरिक धैर्य और लचीली नीतियांः चीन की चुनौती का सामना भारत कैसे कर सकता है' विषय पर आयोजित डिजिटल सत्र में भाग लिया।
- 27–28 अप्रैल 2021 को ओपी जिंदल विश्वविद्यालय और कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'न्यायिक निर्णयों में अर्थशास्त्र के आयाम' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया।
- 23 अप्रैल 2021 को सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान में भाग लिया।
- 20 अप्रैल 2021 को एस्केप साउथ और दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय (एस्कैप – एसएसडब्ल्यूए) द्वारा 'दक्षिण एशिया उपक्षेत्र से परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित पैनल परिचर्चा में भाग लिया।
- 15 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- 15 अप्रैल 2021 को कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'ट्रिप्स और ज्ञान के आदान–प्रदान का पता लगाना' विषय पर आयोजित वर्चुअल संगोष्ठी में भाग लिया।
- 7 अप्रैल 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा 'भारत–अमेरिका व्यापार परिचर्चाः अमेरिका–भारत दवा सहयोग और वैक्सीन कूटनीति को मजबूत करना' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

डॉ. बी. बालाकृष्णन

विज्ञान कूटनीति फेलो

- 29 जून 2021 को जलवायु कूटनीति पर एफआईएसडी व्याख्यान में उद्घाटन वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 21 जून 2021 को विभिन्न देशों के 34 प्रतिभागियों के लिए वारसा साइंस डिप्लोमेसी स्कूल 2021 कोर्स द्वारा आयोजित पैनल परिचर्चा में वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 19 जून 2021 को 'ट्रिप्स छूटः लैटिन अमेरिका के लिए मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आयोजित आरआईएस–साउथ सेंटर वेबिनार में उद्घाटन वक्ता के रूप में भाग लिया।
- 15 जून, 2021 को भारत के पैनलिस्ट के रूप में आरआईएस–ओआरएफ के 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर संवाद' में भाग लिया।
- 23 अप्रैल 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी द्वारा ''पूर्वोत्तर में सतत रसद और ढुलाई' विषय पर आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

डॉ. कृष्णा रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फेलो

- 25 मई 2021 को 'नया क्षितिज अंतिम सम्मेलन – यूरोप में आरआरआई को लागू करने का अनुभव' में 'आरआरआई सभी विषयों, संदर्भों एवं देशों में अनुसंधान और नवाचार के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में' विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की।
- 15 अप्रैल 2021 को सुपर एमओआरआरआई द्वारा आयोजित सुपर एमओआरआरआई परियोजना के क्षेत्रीय वेबिनारों में एशिया/प्रशांत पर सत्र के दौरान परिचर्चा का संचालन किया।

प्रोफेसर टी. सी. जेम्स

विजिटिंग फेलो

- केरल राज्य जैव विविधता मंडल द्वारा आयोजित सम्मेलन में व्यापार और विकास लक्ष्य और आयुष उद्योग के लिए नीतियों पर विशेष भाषण दिया तथा सत्र की अध्यक्षता 27 सितम्बर 2021 को की।
- आधुनिक विश्व में बौद्धिक अधिकार और कापीराईट विषय पर वार्ता 24 सितम्बर 2021 को दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय में प्रस्तुत की।
- प्रकाशन आचार नीतिः साहित्यिक चोरी और कापीराईट विषय पर वार्ता देवा माथा महा विद्यालय कुराविला गडू में 21 सितम्बर 2021 को प्रस्तुत की।

डॉ पी के आनंद

विजिटिंग फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।
- आरआईएस द्वारा द एशिया फाउंडेशन के सहयोग से 31 मार्च 2022 को भारत –ऑस्ट्रेलिया–प्रशांत द्वीपसमूह विकास सहयोग को आगे बढ़ाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- किंग अब्दुलअजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर (इथरा), दहरान, सऊदी अरब द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'डिजिटल वेलबीइंग' शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस द्वारा 28–29 मार्च 2022 को आयोजित 'विश्व की सुनेंः सार्वभौमिक सीमाओं के भीतर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना' पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- आरआईडीएस द्वारा विज्ञान प्रसार के सहयोग से 28 मार्च 2022 को न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मानद सचिव डॉ के श्रीधर द्वारा 'रिवायरिंग द ब्रेनः इज इट पॉसिबल?' विषय पर दिए गए एसटीआईपी व्याख्यान में भाग लिया।
- 23 मार्च 2022 को आयोजित टीएफ5 बैठक में 'उत्तरजीविता के लिए शिक्षा– प्रारंभिक बचपन के लिए बहु–क्षेत्रीय और एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण को मजबूत करना' शीर्षक वाले पॉलिसी ब्रीफ के लिए सह–लेखक के रूप में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–पीआरआई द्वारा 22 मार्च 2022 को 'भारत और जापान में कोविड–19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं और भविष्य में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- एशियन कॉन्फ्लुएंस, इंडिया ईस्ट एशिया सेंटर द्वारा 3 मार्च 2022 को 'पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र और पड़ोस का विकासः उद्यमिता और लोगों जोड़ने हेतु भारत–जापान सहयोग' विषय पर आयोजित वेब संवाद में भाग लिया।
- डॉ अजय माथुर, डीजी, आईएसए द्वारा 28 फरवरी 2022 को सौर ऊर्जा पर एसटीआईपी नीतिगत व्याख्यान में भाग लिया।
- आरआईएस, आईसीडब्ल्यूए, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (जीआईजीए) और जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स (एसडब्ल्यूपी) द्वारा 24 फरवरी, 2022 को आयोजित इंडो–जर्मन 1.5 ट्रैक डायलॉग 2022 में भाग लिया।
- टी20 सचिवालय, इंडोनेशिया द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित 'इंडोनेशिया जी–20 अध्यक्षता : आर्थिक परिवर्तन से एक साथ रिकवर करना और मजबूती से रिकवर करना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- ' आसियान–भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाना – भारत और आसियान के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत में रणनीतिक संरचना विकसित करना' पर 18 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक में भाग लिया।
- जी–20 इंडोनेशिया के साथ आरआईएस और ग्लोबल सॉल्यूशंस इनिशिएटिव के सहयोग से 18 फरवरी 2022 को जी–20 में महामारी पश्चात बुनियादी सुविधाएं और वैश्विक सार्वजनिक सामान विषय पर संगोष्ठी में भाग लिया।
- 9 और 10 फरवरी 2022 को आयोजित 'कोविड–19 महामारी से समावेशी रिकवरी को साकार करना' शीर्षक वाले टी20 स्थापना सम्मेलन में भाग लिया।
- आईएफएडी द्वारा 3 फरवरी 2022 को आयोजित 'ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2021: खाद्य प्रणाली की मुख्यधाराएं' पर चर्चा में भाग लिया।

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 19 जनवरी, 2022 को आयोजित 'कृषि खाद्य प्रणालियों को आघातों और दबावों के प्रति अधिक लचीला बनाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' पर 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद के कार्यक्रम (आभासी) में हिस्सा लिया।
- 15–16 दिसंबर 2021 को आयोजित '16वें राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्य 2030 एसेस, एक्ट, एक्सलरेट' पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया (यूएन जीसीएनआई) के कार्यक्रम (आभासी) में भाग लिया।
- 14 दिसंबर, 2021 को 'भारत–वियतनाम सत्रः व्यापार सहयोग के अवसर' पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (आभासी)।
- 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 'सामाजिक उद्यम और विकलांगताः आसियान क्षेत्र में नवाचार, जागरूकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा' पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान और पूर्वी एशिया के कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आधिकारिक पक्ष कार्यक्रम 'विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन 2021: स्वस्थ भविष्य के लिए हर बच्चे को सशक्त बनाना – स्कूल में भोजन और पोषण शिक्षा की संभाव्यता' में भाग लिया, जो 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। (आभासी)
- 30 नवंबर 2021 को आयोजित टी20 हैंडओवर कार्यक्रम 'इटली से इंडोनेशिया तकः जी20 रिकवरी पहल में टी20 का योगदान' में भाग लिया। (आभासी)
- 'अफ्रीका और भारतः खाद्य और कृषि में परिवर्तन के साथ अनुभव और सीखने और सहयोग के अवसर' पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, अफ्रीका में कृषि अनुसंधान मंच और बॉन विश्वविद्यालय के विकास अनुसंधान केंद्र द्वारा 26 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। (आभासी)
- 24 नवंबर, 2021 को विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत की औद्योगीकरण चुनौतियां, अवसर और आगे की राह पर आयोजित औद्योगिक विकास और भारत भूमि और विकास अध्ययन संस्थान के सम्मेलन में हिस्सा लिया। (आभासी)
- 26–28 अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित 'इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी' विषय पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, एफआईआई रियाद, सऊदी अरब द्वारा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 5वीं वर्षगांठ पर वेबिनार में भाग लिया।
- इस्टिटूटो अफ़ारी इंटरनेशनल, रोमा ऑफ़ टी20: इटालियन प्रेसीडेंसी द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी ढांचे की दिशा में जी20 की भूमिका' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- टी–20 की संगोष्टियों/कार्यशालाओं में भाग लिया, जिसका आयोजन टी–20 इटली चैयर ने जुलाई–सितम्बर 2021 में किया।
- कोविड–19 के बाद एमएसएमईएस की सतत संवृद्धी पुनः प्रदीप्त करना विषय संगोष्टी में भाग लिया जिसका आयोजन आईएसआईडी–आईसीएस एसआर ने 30 जुलाई 2021 को किया।
- आसियान–इंडिया की विकास में भागेदारी पर प्रस्तुती 20 अगस्त 2021 को की।
- सत्तत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण तथा पंचायतों की भूमिका विषय पर वेबीनार में भाग लिया जिसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय ने 23 अगस्त 2021 को किया।
- अप्रैल–जून 2021 के दौरान टी20 इटली चेयर्स द्वारा आयोजित टी20 गोलमेज सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लिया।
- 20 अप्रैल 2021 को 'आसियान ऑन प्वाइंट' पब्लिक फोरम #3 – कोविड–19 के बाद आसियान कार्यबल तैयार करना' पर आयोजित ईआरआईए वेबिनार श्रृंखला में भाग लिया।
- 27 मई 2021 को ईआरआईए वेबिनार श्रृंखला – एपिसोड #4 'महामारी के बाद रिकवरी के लिए आसियान और पूर्वी एशिया में उद्यमिता, स्टार्ट–अप्स , नवाचार (ई–एस–आई)' में भाग लिया।
- 24 जून 2021 को ईआरआईए द्वारा 'सफलता के लिए महत्वपूर्ण साझेदारियां – सार्वजनिक, निजी और लोग' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 16 जून 2021 को आईआईसी, नई दिल्ली द्वारा 'मजबूत वित्तीय प्रणाली और गवर्नेंस' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फैलो

- आईसीआरआईईआर द्वारा 31 मार्च 2022 को आयोजित (वर्चुअल) 'लचीली आपूर्ति श्रृंखला के प्रति भारत–जापान साझेदारी' विषय पर एक वेबिनार में भाग लिया।

- किंग अब्दुलअजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर (इथरा), दहरान, सऊदी अरब द्वारा 30 मार्च 2022 को आयोजित 'डिजिटल वेलबीइंग' शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- ग्लोबल सॉल्यूशंस द्वारा 28–29 मार्च 2022 को आयोजित 'विश्व की सुनें: सार्वभौमिक सीमाओं के भीतर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना' पर हाइब्रिड शिखर सम्मेलन (वर्चुअल) में भाग लिया।
- आईसीआरआईईआर–पीआरआई द्वारा 22 मार्च 2022 को 'भारत और जापान में कोविड–19 के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएं और भविष्य में आर्थिक सहयोग की संभावनाएं' विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- टी20 सचिवालय, इंडोनेशिया द्वारा 24 फरवरी 2022 को आयोजित 'इंडोनेशिया जी–20 अध्यक्षता : आर्थिक परिवर्तन से एक साथ रिकवर करना और मजबूती से रिकवर करना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा 19 जनवरी, 2022 को आयोजित 'कृषि खाद्य प्रणालियों को आघातों और दबावों के प्रति अधिक लचीला बनाना' विषय पर वेबिनार में भाग लिया।
- 'क्या वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है? हाल के जी20 शिखर सम्मेलन, सीओपी 26 और व्यापार चर्चा से कुछ विचार' पर 17 दिसंबर, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद के कार्यक्रम (आभासी) में हिस्सा लिया।
- 15–16 दिसंबर 2021 को आयोजित '16वें राष्ट्रीय सम्मेलन लक्ष्य 2030 एसेस, एक्ट, एक्सलरेट' पर संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के कार्यक्रम (आभासी) में भाग लिया।
- 14 दिसंबर, 2021 को 'भारत–वियतनाम सत्र: व्यापार सहयोग के अवसर' पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया (आभासी)।
- 8 दिसंबर 2021 को आयोजित 'सामाजिक उद्यम और विकलांगता: आसियान क्षेत्र में नवाचार, जागरूकता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा' पर आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान और पूर्वी एशिया के कार्यक्रम में भाग लिया। (आभासी)
- जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के आधिकारिक पक्ष कार्यक्रम 'विकास के लिए पोषण शिखर सम्मेलन 2021: स्वस्थ भविष्य के लिए हर बच्चे को सशक्त बनाना – स्कूल में भोजन और पोषण शिक्षा की संभाव्यता' में भाग लिया, जो 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया था। (आभासी)
- 30 नवंबर 2021 को आयोजित टी20 हैंडओवर कार्यक्रम 'इटली से इंडोनेशिया तक: जी20 रिकवरी पहल में टी20 का योगदान' में भाग लिया। (आभासी)
- 'अफ्रीका और भारत: खाद्य और कृषि में परिवर्तन के साथ अनुभव और सीखने और सहयोग के अवसर' पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, अफ्रीका में कृषि अनुसंधान मंच और बॉन विश्वविद्यालय के विकास अनुसंधान केंद्र द्वारा 26 नवंबर 2021 को संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में भाग लिया। (आभासी)
- 24 नवंबर, 2021 को विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत की औद्योगीकरण चुनौतियां, अवसर और आगे की राह पर आयोजित औद्योगिक विकास और भारत भूमि और विकास अध्ययन संस्थान के सम्मेलन में हिस्सा लिया। (आभासी)
- 26–28 अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित 'इन्वेस्ट इन ह्यूमैनिटी' विषय पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट, एफआईआई रियाद, सऊदी अरब द्वारा आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 5वीं वर्षगांठ पर वेबिनार में भाग लिया।
- इस्टिटूटो अफ़ारी इंटरनेशनल, रोमा ऑफ़ टी20: इटालियन प्रेसीडेंसी द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 को 'अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी ढांचे की दिशा में जी20 की भूमिका' पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- अप्रैल–जून 2021 के दौरान टी20 इटली चेयर्स द्वारा आयोजित टी20 गोलमेज सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लिया।
- 20 अप्रैल 2021 को 'आसियान ऑन प्वाइंट' पब्लिक फोरम #3 – कोविड–19 के बाद आसियान कार्यबल तैयार करना' पर आयोजित ईआरआईए वेबिनार श्रृंखला में भाग लिया।
- 27 मई 2021 को ईआरआईए वेबिनार श्रृंखला – एपिसोड #4 'महामारी के बाद रिकवरी के लिए आसियान और पूर्वी एशिया में उद्यमिता, स्टार्ट–अप्स , नवाचार (ई–एस–आई)' में भाग लिया।
- 24 जून 2021 को ईआरआईए द्वारा 'सफलता के लिए महत्वपूर्ण साझेदारियां – सार्वजनिक, निजी और लोग' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
- 16 जून 2021 को आईआईसी, नई दिल्ली द्वारा 'मजबूत वित्तीय प्रणाली और गवर्नेंस' विषय पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।

डॉ. पंखुड़ी गौड़

सहायक प्रोफेसर

- वाणिज्य विभाग में 9 मार्च, 2022 को आयोजित चर्चा में भाग लिया।
- आईएसडीबी टीम के साथ 19 जनवरी, 2022 को एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया।

vè;k; 7

आंकड़े एवं सूचना केन्द्र

आरआईएस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ने हाल के महीनों में नवीनतम विशिष्ट प्रकाशनों, रिपोर्टों, डेटाबेस, ई–जर्नल्स एवं लेखों इत्यादि को हासिल किया है, ताकि आरआईएस की संकाय और आगंतुक विद्वानों को अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकें। यह कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विभिन्न प्रकाशनों या आलेखों के कार्यक्रम का आदान–प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों पर विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी अधिक प्रकाशनों या आलेखों तथा अध्ययन कार्यक्रमों को जोड़कर संसाधन आधार को निरंतर समृद्ध करता रहता है।

इस केंद्र के प्रमुख वैश्विक संस्थानों जैसे कि एफएओ, आईएलओ, ओईसीडी, यूएन, अंकटाड, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इत्यादि के साथ घनिष्ठ जुड़ाव हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य–पत्र (वर्किंग पेपर), परिचर्चा पत्र (डिस्कशन पेपर), री–प्रिंट्स, समसामयिक पत्र दरअसल प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में या तो परस्पर आदान–प्रदान किए गए कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त होते हैं या संस्थागत वेबसाइटों के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। वर्तमान केंद्र में 24,590 से भी अधिक पुस्तकें हैं जिनमें सरकारी प्रकाशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अन्य शोध संस्थानों के दस्तावेज शामिल हैं। इनके अलावा सजिल्द पुस्तक के रूप में 1850 पत्र–पत्रिकाएं हैं। इस केंद्र ने 434 से भी अधिक प्रिंट और ऑनलाइन पत्र–पत्रिकाओं की सदस्यता भी ले रखी है जिनमें जस्टर, आईएमएफ ई–लाइब्रेरी, एल्सवियर– साइंसडायरेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विली इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस केंद्र को प्रतिष्ठित स्रोतों से सम्मानार्थ भेंट के आधार पर लगभग 50 पत्र–पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। 350 से भी अधिक सीडी रॉम और डेटाबेस हैं। एक और खास बात यह है कि 'डेलनेट' का सदस्य होने के नाते यह संसाधन–साझाकरण को बढ़ावा देता है।

इस केंद्र में आसान पहुंच के लिए इंट्रानेट के माध्यम से ऑनलाइन समृद्ध संग्रह उपलब्ध है।

अभिलेखन केंद्र/पुस्तकालय के संग्रह में ये शामिल हैं

- पुस्तकें
- सांख्यिकीय वार्षिकी
- दस्तावेज–डब्ल्यूपी–ओपी–डीपी
- जर्नल / पत्र–पत्रिकाएं (प्रिंट+ऑनलाइन+सीडी–रॉम)
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के समाचार पत्र
- पिछला संस्करण (बैक वॉल्यूम)
- सीडी–रॉम
- सीडी–रॉम में डेटाबेस
- आरआईएस डेटाबैंक

व्यापार, टैरिफ एवं गैर–टैरिफ उपायों, भुगतान संतुलन, वित्तीय सांख्यिकी, विकास सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, बौद्धिक संपदा सेवाओं और कॉरपोरेट डेटा एवं सूचना पर आरआईएस का वैश्विक डेटाबेस। भारतीय आंकड़े 8– अंकीय स्तर पर व्यापार संबंधी टाइम सीरीज डेटाबेस, भारतीय कंपनियों एवं उनके वित्तीय प्रदर्शन के डेटाबेस, सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस और सीमा शुल्क टैरिफ आंकड़ों को कवर करता है।

आरआईएस का डेटा सर्वर

आरआईएस एक आधुनिक डेटा सर्वर का रख–रखाव बिल्कुल सही ढंग से कर रहा है जिसमें उसके आंकड़ो कोष की बढ़ी हुई सुरक्षा के तहत आंकड़ों को नष्ट करने वाले वाइरल या हैकिंग सहित किसी भी संभावित बाहरी हमले से बचाव की पुख्ता व्यवस्था की गई है। आरआईएस ने त्वरित संदर्भ के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टाइम सीरीज आंकड़ा हासिल किया है। इसने टैरिफ आंकड़ा कोष, भारतीय कंपनियों के डेटाबेस, व्यापार आंकड़ों की दिशा (डॉट्स), विश्व विकास संकेतकों (डब्ल्यूडीआई), इत्यादि के साथ इस पर महत्वपूर्ण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़ा (एचएस एंड एसआईटीसी) अपलोड किए हैं। सर्वर पर आंकड़ा कोष को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। यह संकाय के सदस्यों को तत्काल अद्यतन डेटा उपलब्ध कराता है जो उनके साक्ष्य–आधारित शोध अध्ययनों में गहराई से मदद करता है। यही नहीं, ऐसे में व्यक्तिगत आरआईएस संकाय सदस्यों के लिए महंगी बहु–वैश्विक डेटा प्रणालियों को खरीदने की जरूरत नहीं रह जाती है।

आरआईएस की वेबसाइट और ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर

(www.ris.org.in)

आरआईएस की वेबसाइट को प्रतिदिन अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली एवं यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल सामग्री के साथ नवीनीकरण किया जाता है और यह नवीनतम सुविधाओं एवं कार्यों से सुसज्जित या लैस है। इसे आरआईएस की आंतरिक टीम द्वारा वास्तविक समय

पर अपडेट किया जाता है, ताकि उसके आउटरीच कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में वैश्विक सार्वजनिक डोमेन में गहन अनुसंधान अध्ययनों और संबंधित घटनाक्रमों को उपलब्ध कराया जा सके। यह स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त, निवेश, विकास सहयोग, वैश्विक आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिणीय सहयोग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आरआईएस के कार्यक्रम के मुख्य क्षेत्रों के बारे में व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। यह अनुसंधान रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, सूचना–पत्र (न्यूजलेटर) और मीडिया लेखों के रूप में आरआईएस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकाशनों की विस्तृत श्रृंखला की मुफ्त डाउनलोड सुविधा प्रदान करती है। इसमें आरआईएस द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं का विवरण भी है। चालू वित्त वर्ष (2020–21) के दौरान तीन नए उप–कार्य क्षेत्रों (सब–डोमेन) को आंतरिक तौर पर विकसित किया गया है और फिर उन्हें आरआईएस की वेबसाइट से लिंक कर दिया गया है, ताकि उनकी स्पष्ट और व्यापक पहुंच संभव हो सके। अब आरआईएस की मुख्य वेबसाइट के अंतर्गत ग्यारह उप–कार्य क्षेत्र (सब–डोमेन) हैं। इनमें ये शामिल हैं:

ब्रिक्स
http://bricscivil.ris.org.in

बिमस्टेक
http://bimstec.ris.org.in

एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
http://aagc.ris.org.in

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) पहल
http://iora.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों पर आरआईएस का कार्यक्रम
http://sdg.ris.org.in

सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल
http://sti4sdg.ris.org.in

भारतीय विकास सहयोग के लिए फोरम
http://fidc.ris.org.in

एफआईएसडी
http://fisd.in

भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पर फोरम (एफआईटीएम)
http://fitm.ris.org.in

ब्लू इकोनॉमी फोरम
http://blueeconomyforum.ris.org.in

वैश्विक विकास केंद्र
http://gdc.ris.org.in

आसियान भारत केंद्र
http://aic.ris.org.in

न्यू एशिया फोरम
http://newasiaforum.ris.org.in

इसके अलावा, वेबसाइट पर निम्नलिखित वेबसाइट पेज भी हैं :

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
http://ris.org.in/asian-infrastructure-investment-bank

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) फोरम
http://ris.org.in/science-technology-and-innovation-policy-stip-forum-and-monthly-lecture-series-0

दिल्ली प्रोसेस
http://ris.org.in/delhi-process

गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दस्तावेज
http://ris.org.in/documents-non-aligned-movement

समर स्कूल
http://ris.org.in/summer-school-0

पेरिस शांति फोरम
http://ris.org.in/deadline-extended-extra-time-submit-your-project-paris-peace-forum

आरआईएस की देख–रेख वाली अन्य वेबसाइटें

नेटवर्क ऑफ सदर्न थिंक–टैंक्स (नेस्ट)
http://southernthinktanks.org

इब्सा
http://ibsa-trilateral.org

दक्षिण एशिया नीतिगत अध्ययन केंद्र (एसएसीईपीएस)
http://saceps.org.in

चालू वित्त. वर्ष (2019–20) के दौरान आरआईएस की वेबसाइट ने 'हिट' की कुल संख्या में शानदार वृद्धि दर्ज की है। इसने गूगल द्वारा संचालित शीर्ष अनुसंधान परिणामों में से एक का दर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है जो इसकी निरंतर बढ़ती दृश्यता को रेखांकित करता है। आरआईएस नियमित रूप से अपने त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर और मासिक ई–पत्रिका को भी प्रकाशित करता है जिन्हें प्रमुख नीति–निर्माताओं एवं आकृतिकारों, थिंक टैंकों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, प्रमुख शिक्षाविदों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रख्यात हस्तियों के बीच दुनिया भर में प्रसारित किया जाता है, ताकि उन्हें

विकासशील देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले मुद्दों पर आरआईएस द्वारा किए जा रहे विश्वसनीय शोध कार्यों की विस्तृत विविधता से अवगत कराया जा सके।

सोशल मीडिया

आरआईएस ने ट्विटर, फेसबुक एवं यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंचो पर अपनी उपस्थिति काफी बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में इसके अनुगामी भी हैं। आरआईएस के यूट्यूब चैनल को निरंतर अपडेट रखा जाता है। लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आयोजनों को इसकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराया जाता है। आरआईएस के यूट्यूब चैनल की दर्शक संख्या में अच्छी–खासी वृद्धि दर्ज की गई है तथा उसका ग्राहक आधार भी अब और ज्यादा बढ़ गया है।

आरआईएस फेसबुक और ट्विटर

4 हजार से भी अधिक अनुगामी हैं और इसके पेजों को लोगों की रायशुमारी के आधार पर 5 में से 4.3 रेटिंग दी गई है। ट्विटर हैंडल के 4 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वास्तविक समय पर लोगों की त्वरित पहुंच के लिए आरआईएस के प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप को इन दोनों ही प्लेटफॉर्मों पर तुरंत उपलब्ध कराया जाता है। यही नहीं, दर्शकों की ओर से मिली प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहजनक है।

आरआईएस की इंट्रानेट सुविधा

संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट सुविधा है जो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं से जुड़ी बातों के संबंध में पासवर्ड संरक्षित जानकारियां प्रदान करती है, जिनमें अवकाश का रिकॉर्ड, वेतन पर्ची (सैलरी स्लिप), चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य विवरण शामिल होते हैं। यह अपने संकाय के लिए अनुसंधान डेटाबेस भी प्रदान करती है जो सीडी प्रारूप में उपलब्ध होता है और जो अन्य बातों के अलावा व्यापार आंकड़ों की दिशा, कस्टाडा, विश्व विकास संकेतकों, सरकारी वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़ों (आईएमएफ) को कवर करता है।

वित्त वर्ष 2021–22 में देशों द्वारा हिट्स

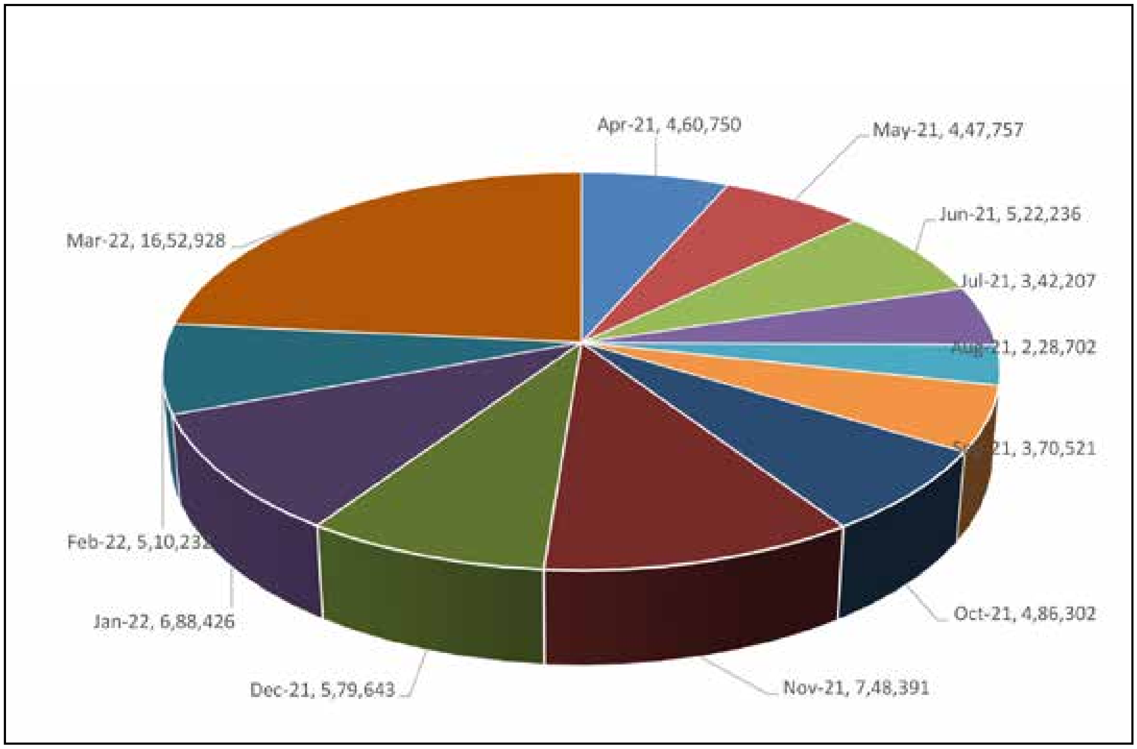

वित्त वर्ष 2021–22 में आरआईएस सब–डोमेन में हिट्स

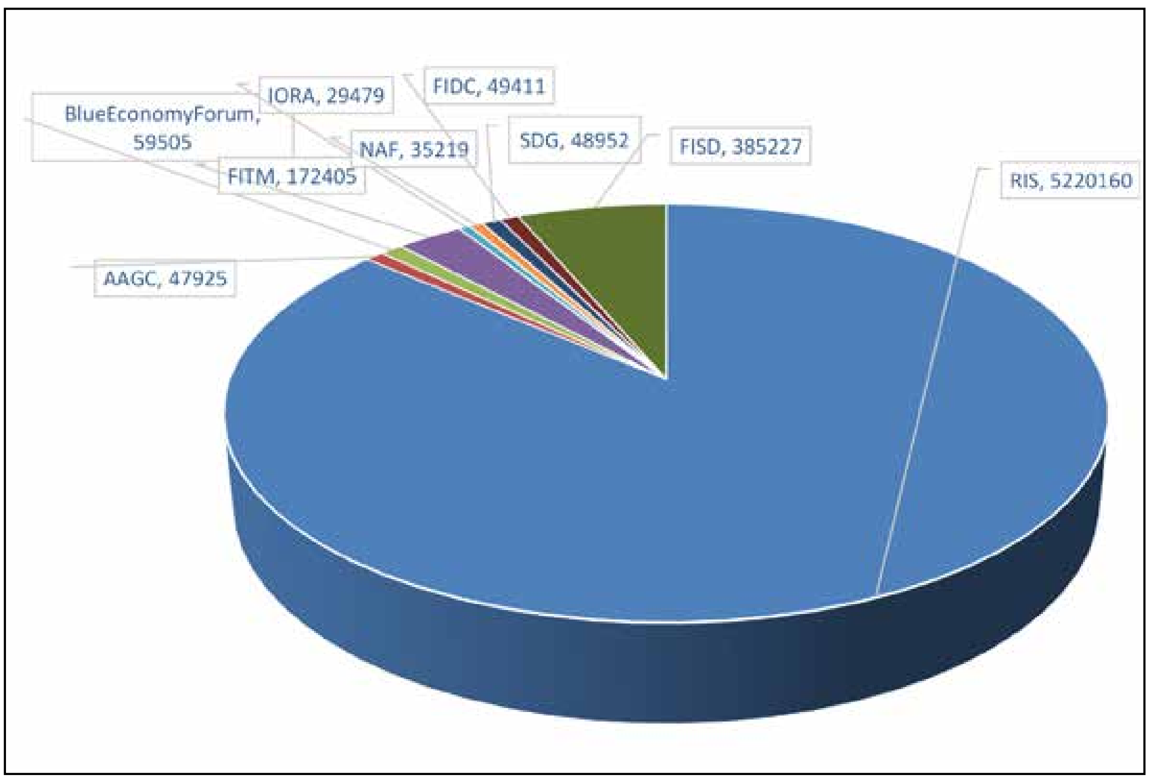

मानव संसाधन

प्रो. सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक

विशेषज्ञता : अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामले, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तत तथा विकास सहयोग

संकाय

डॉ एस के मोहंती

प्रोफेसर

विशेषज्ञता : वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण तथा विकास संबंधी आर्थिक मामले

डॉ सब्यासाची साहा

सह प्रोफेसर

विशेषज्ञता : प्रोद्योगिकी एवं विकास, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार, आर्थिक विकास एवं विश्व व्यापार संगठन

डॉ प्रियदर्शी दाश

सह प्रोफेसर

विशेषज्ञता : अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त

डॉ पंकज वशिष्ठ

सह प्रोफेसर

विशेषज्ञताः व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ बीना पाण्डेय

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञता : सामाजिक क्षेत्र, जेंडर सशक्तिकरण एवं विकास संबंधी मामले

डॉ. सुशील कुमार

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञताः अतंर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त

डॉ. अमित कुमार

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञताः नवप्रवर्तन, दूरदर्शिता एवं नियंत्रण

सुश्री पंखुड़ी गौर

सहायक प्रोफेसर

विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, एफटीए और मेगा क्षेत्रीय

विशिष्ट फैलो

श्री राजीव खेर

विशिष्ठ फैलो

विशेषज्ञताः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य

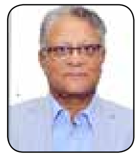

श्री अमर सिन्हा

विशिष्ठ फैलो

विशेषज्ञताः आर्थिक कूटनीति और दक्षिणीय सहयोग

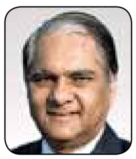

श्री आर वी साही

विशिष्ठ फैलो

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

श्री भास्कर बालाकृष्णन

साइंस डिपलोमेसी फैलो

विशेषज्ञताः एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

प्रो. टी सी जेम्स

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी (आईपीआर)

प्रो. मिलिंदो चक्रवर्ती

विजिटिंग फैलो

(31 जुलाई 2022 तक)

विशेषज्ञताः सूक्ष्म–अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सहयोग और मूल्यांकन

डॉ. पी के आनन्द

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः आर्थिक विकास और विकास

श्री कृष्ण कुमार

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः आधिकारिक सांख्यिकी एवं सतत विकास लक्ष्य

डॉ. के रवि श्रीनिवास

विजिटिंग फैलो

विशेषज्ञताः बौद्धिक संपदा अधिकार एवं वैश्विक व्यापार

श्री सुभोमॉय भट्टाचार्य

सलाहकार

विशेषज्ञताः सार्वजनिक नीति एवं ऊर्जा विशेषज्ञ

श्री अरुण सोमाचुदन नायर

सलाहकार

(31 जुलाई 2022 तक)

विशेषज्ञताः विदेशी व्यापार एवं निवेश

डॉ. ऑगस्टीन पीटर

विजिटिंग फैलो

(30 अप्रैल 2022 तक)

विशेषज्ञताः व्यापार निवेश एवं प्रतिस्पर्धा नीती

विजिटिंग फैलो/सलाहकार/अनुसंधान एसोसिएट

डॉ नम्रता पाठक
अनुसंधान सहयोगी
विशेषज्ञता: पारंपरिक ज्ञान

डॉ दिनोज कुमार उपाध्याय
सलाहकार
(30 सितंबर 2022 तक)
विशेषज्ञता: व्यापार, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार

डॉ कपिल पाटिल
अनुसंधान सहयोगी
(10 फरवरी 2022 तक)
विशेषज्ञता: एसटीआई सहयोग एवं विज्ञान नीति

डॉ स्नेहा सिन्हा
शोध सहयोगी
विशेषज्ञता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन

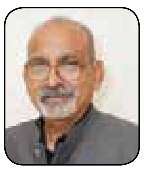

डॉ अंशुमन गुप्ता
सलाहकार
(14 फरवरी 2022 से)
विशेषज्ञता: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

डॉ राहुल रंजन
सलाहकार
(15 फरवरी 2022 से)
विशेषज्ञता: ऊर्जा अर्थशास्त्र और ऊर्जा में व्यापार

डॉ सविता के एल
फैलो
(7 मार्च 2022 से)
विशेषज्ञता: एसडीजी के लिए पर्यावरण अर्थशास्त्र, एसडीजी और एसटीआई

श्री सायंतन घोषाल
सलाहकार
(11 जनवरी 2022 से)
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक सुरक्षा कल्याण प्रणाली

चैतन्य गिरी
सलाहकार
(1 दिसंबर 2021 से)
विशेषज्ञता: अंतरिक्ष डोमेन रणनीतियाँ, ग्रह विज्ञान

कनिका रखरा
सलाहकार
(25 जनवरी 2022 से)
विशेषज्ञता: बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन

आसियन–भारत केंद्र

डॉ. प्रबीर डे
प्रोफेसर / समन्वयक, एआईसी
विशेषज्ञता: अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं परिवहन संबंधी सुविधाएं, सेवा क्षेत्र में व्यापार

सुश्री श्रेया पान
अनुसंधान सहायक
(23 मार्च 2022 तक)
विशेषज्ञता: वैश्विक व्यापार

डॉ शम्पा कुन्डू
सहायक
(1 अक्टूबर 2021 से)

डॉ निदा रहमान
यंग प्रोफेशनल
(17 मई 2021 से)

वैश्विक विकास पर पहल

सुश्री साधना रैलिया
जीडीसी फैलो
(30 सितंबर 2021 तक)

सुश्री रितुप्रना बैनर्जी
जीडीसी मैनेजर

श्री अमित अरोड़ा
जीडीसी मैनेजर

अनुसंधान सहायक

सुश्री कृतिका खन्ना

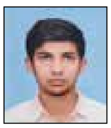

श्री सैयद अर्सलान अली
(3 जनवरी 2022 से)

सुश्री नीलाक्षी महर्षि
(3 जनवरी 2022 से)

सुश्री संजना अग्रवाल
(4 फरवरी 2022 से)

सुश्री प्रतिवा शॉव
(3 अगस्त 2021 तक)

श्री अपूर्व भटनागर
(4 दिसंबर 2021 तक)

सुश्री चांदनी डवानी
(15 मार्च 2022 तक)

सुश्री सुनन्दा महाजन
(22 अक्टूबर 2021 तक)

सुश्री देबाजंना डे
(13 सितंबर 2021 तक)

सुश्री सोनल गर्ग
(18 अप्रैल 2021 तक)

श्री सिद्धार्थ नायडू
(28 फरवरी 2022 तक)

सुश्री श्वेता शाजू
(24 जून 2021 से)

सुश्री सुखमनी कौर
(18 जुलाई 2021 से)

सुश्री सिद्धि शर्मा
(22 जुलाई 2021 से)

श्री चैतन्य खुराना
(24 जून 2021 से)

श्री रवि कुमार गुप्ता
(28 जून 2021 से)

श्री प्रणेश एम
(3 जनवरी 2022 से)

श्री प्रीत अमोल सिंह
(3 जनवरी 2022 से)

सुश्री इशिता वर्मा
(3 जनवरी 2022 से)

श्री हरिओम अरोड़ा
(5 जून 2021 तक)

सहायक वरिष्ठ अध्येता

प्रोफेसर अनिल सुकलाल
उप महानिदेशक, एशिया और मध्य पूर्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग विभाग, दक्षिण अफ्रीका

प्रोफेसर हरिबाबू ईजनवरजला
पूर्व कुलपति प्रभारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय

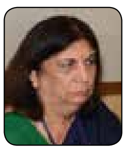

डॉ. बेनू श्नाइडर
पूर्व में संयुक्त राष्ट्र एवं अंकटाड के साथ और भारतीय रिजर्व बैंक में सलाहकार

प्रोफेसर अमृता नार्लीकर
अध्यक्ष, जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल एंड एरिया स्टडीज (गीगा)

प्रोफेसर मुकुल जी. अशर
प्रोफेसरियल फेलो, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. बालाकृष्ण पिसुपति
चेयरपर्सन, फ्लेज और पूर्व अध्यक्ष, एनबीए, चेन्नई

डॉ. बिश्वजीत बनर्जी
मुख्य अर्थशास्त्री, वित्त मंत्रालय, स्लोवाक गणराज्य और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा

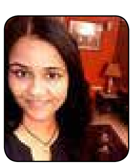

डॉ. मितु सेनगुप्ता
प्रोफेसर, राजनीति और प्रशासन विभाग, रायर्सन यूनिवर्सिटी, कनाडा, विजिटिंग प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट (सीएसडी)

प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल
आरबीआई के पूर्व चेयर प्रोफेसर, विकास अध्ययन केंद्र, तिरुवनंतपुरम

प्रोफेसर शाहिद अहमद
प्रोफेसर और प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया

प्रोफेसर श्रीविद्या राघवान
कानून के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ लॉ, नॉर्मन, अमेरिका

डॉ. रामकिशन एस. राजन
वाइस–डीन (अनुसंधान) और प्रोफेसर, ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर

डॉ. सुमा अत्रे
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस और रणनीति, ब्रुनेल बिजनेस स्कूल, यूके

डॉ. टी. पी. राजेंद्रन
पूर्व सहायक महानिदेशक, आईसीएआर और विजिटिंग फेलो, आरआईएस

प्रोफेसर केविन पी. गालाघेर
प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, बोस्टन यूनिवर्सिटी; सीनियर एसोसिएट, जीडीएई, टफ्ट्स यूनिवर्सिटी

डॉ गणेशन विग्नराज
एडजंक्ट सीनियर फेलो
सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ओवरसीज इंस्टीट्यूट (ODI), लंदन; अनिवासी सीनियर फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज (ISAS)

स्टाफ के अन्य सदस्य

श्री महेश सी अरोड़ा
निदेशक, वित्त एवं प्रशासन

श्री एच. के. मलिक
(10 मार्च 2022 से)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं वित्त)

महानिदेशक कार्यालय

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रभारी, महानिदेशक कार्यालय
श्रे एन एन कृष्णन, निजी सचिव *(31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत)*
श्रीमती रितु परनामी, निजी सचिव
सुश्री गोहर नाज, सचिवीय सहायक
श्री अनिल कुमार, सहायक
श्री पियूष वर्मा, अवर श्रेणी लिपिक
श्रीमती शालिनी शर्मा, स्वागती
श्री भास्कर तिवारी, सहायक लेखाकार
(3 जनवरी 2022 से)

प्रकाशन विभाग

श्री तीश कुमार मल्होत्रा, प्रकाशन अधिकारी
श्री संजय शर्मा, (संपादकीय) सहायक
श्री सचिन सिंघल, प्रकाशन सहायक (वेब और डिजाइन)

अनुसंधान सहयोग

सुश्री किरन वाघ, निजी सचिव
श्री संजीव शर्मा, निजी सचिव
(*डेपूटेशन पर)*
श्री सुरेन्द्र कुमार, निजी सहायक
श्रीमती बिन्दु गंभीर, आशुलिपिक
श्री जे. श्रीनिवास राव, सहायक
श्री बैदनाथ पाण्डेय, कार्यालय सहायक

आंकड़ा एवं सूचना केन्द्र

श्रीमती ज्योति, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
श्रीमती सुशीला, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी/डॉटाबेस एकक

श्रीमती सुषमा भट्ट, उपनिदेशक, आंकड़ा प्रबंधन
श्री चन्द्र शेखर पुरी, उपनिदेशक, प्रणाली
श्रीमती पूनम मल्होत्रा, डाटा एंट्री आपॅरेटर
श्री सत्यपाल सिंह रावत, जूनियर सहायक
श्री सौम्य रंजन, आईटी सहायक

वित्त एवं प्रशासन

श्री वी कृष्णामणि, प्रशासनिक सलाहकार
(31 अक्तूबर 2021 तक)

श्रीमती शीला मल्होत्रा, अनुभाग अधिकारी (लेखा)
(30 सितंबर 2021 तक)

श्रीमती अनु बिष्ट, सहायक
श्री सुरजीत, लेखाकार

सहायक स्टाफ

श्री सत्यवीर सिंह, स्टाफ कार चालक
श्री जे बी ठाकुरी, स्टाफ कार चालक
श्री बलवान
श्री प्रदीप
श्री राजू
श्री राज कुमार
श्री मनीष कुमार
श्री राज कुमार
श्री सुधीर राणा
श्री बिरजू
श्री प्रदीप नेगी
श्री अविनाश कपूर
(*21 मार्च 2022 से)*

vè;k; 9

वित्तीय विवरण

जीएसए एसोसिएट्स एलएलपी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

16, डीडीए फलैट्स, ग्राउंड फलोर, पंचशील शिवालिक मोड़,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली–110017 टेलीफोन : 41811888, 7862099205, ई–मेलः admin@gsa.net.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली की आमसभा के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों के ऑडिट की रिपोर्ट

राय

हमने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, (इकाई) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी 'विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली' के वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक का तुलन पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरण की अनुसूची शामिल है।

हमारी राय में, संलग्न वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक इस इकाई की वित्तीय स्थिति, उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इसके वित्तीय प्रदर्शन और प्राप्तियों एवं भुगतान का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण या तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुरूप वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के खण्ड 'वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में वर्णित हैं। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार इस इकाई से बिल्कुल पृथक हैं और हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा यह मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और बिल्कुल उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन और प्रशासन के प्रभारी लोगों के दायित्व

प्रबंधन पर ही इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व होता है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इकाई की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन का सही व निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त या प्रासंगिक माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण का स्वरूप निर्धारित करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो सटीक एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन ही 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' के रूप में अपनी इकाई की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रबंधन इसके लिए 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' से संबंधित उन तथ्यों का खुलासा करता है, जो मान्य या लागू होते हैं। प्रबंधन इसके साथ ही लेखांकन के 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' से संबंधित आधार का उपयोग करता है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो अपनी इकाई का परिसमापन करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या परिचालन बंद न करने के लिए उसके पास कोई यथार्थवादी विकल्प हो।

प्रशासन के प्रभारी लोग इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

वित्तीय विवरण के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी तरह की तथ्य संबंधी गलतबयानी से मुक्त है। हमारा उद्देश्य लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना भी है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत या यथोचित आश्वासन दरअसल आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन यह कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि 'एसए' के अनुसार किए गए ऑडिट तथ्य संबंधी गलतबयानी होने पर सदैव उसका पता लगा ही लेंगे। गलतबयानी दरअसल धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उसे तथ्य संबंधी गलतबयानी माना जाता है यदि व्यक्तिगत या समग्र रूप से वे इन वित्तीय विवरण के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों।

'एसए' के अनुसार किए जाने वाले ऑडिट के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- हम धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण की तथ्य संबंधी गलतबयानी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करते हैं, इन जोखिमों को कम करने में सक्षम ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन एवं निष्पादित करते हैं, और ऐसा ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारी राय को ठोस आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं बिल्कुल उपयुक्त होता है। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी का पता नहीं लगा पाने का जोखिम दरअसल त्रुटि से उत्पन्न होने वाली तथ्य संबंधी गलतबयानी से जुड़े जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- हम ऑडिट के लिए उपयुक्त माने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं की डिजाइनिंग की जा सके जो विभिन्न परिस्थितियों में बिल्कुल उपयुक्त होती हैं।
- हम इस्तेमाल में लाई जा चुकी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का आकलन करते हैं।
- हम प्रबंधन द्वारा 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' से संबंधित लेखांकन आधार का उपयोग किए जाने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और यह इस प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित होता है कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ऐसी कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता है, जो एक 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' के रूप में अपना संचालन निरंतर जारी रखने संबंधी इस इकाई की क्षमता पर संशय प्रकट करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई तथ्य संबंधी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण 'लाभकारी कारोबार वाली परिचालनरत इकाई' के रूप में इसका परिचालन बंद हो सकता है।
- हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का आकलन करते हैं। हम इसका आकलन भी करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करना संभव हो।

हम अन्य बातों के अलावा ऑडिट के दौरान चिन्हित की गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण खामियों सहित की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं ऑडिट के समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ बातचीत करते हैं।

हम गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को एक ऐसा विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने स्वायत्तता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ संकलित किया है। हम उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिनका असर संभवतः हमारी स्वायत्तता पर, और जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों पर पड़ सकता है।

अन्य आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं धारणा के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे,
- हमारी राय में, कानून के तहत आवश्यक माने जाने वाले बही–खाते को इकाई ने अब तक बिल्कुल सही ढंग से सुव्यवस्थित रखा है, जैसा कि हमारे द्वारा बही–खाते की छान–बीन से प्रतीत होता है, और
- इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया तुलन–पत्र, आय एवं व्यय का विवरण और प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा–जोखा वस्तुतः बही–खाते के अनुरूप ही है।

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/N500339

ह./–
सीए सुनील अग्रवाल
साझेदार
एम संख्या : 083899
यूडीआईएनः 22083899AQXWCV7802

स्थान : नई दिल्ली :
दिनांक : 05/09/2022

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी)

31 मार्च 2022 तक तुलन पत्र

राशि

	अनुसूची #	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
देनदारियां			
अनुसंधान एवं विकास कोष	1	14,50,26,683.01	13,56,55,874.86
अचल परिसंपत्ति कोष (गैर एफसीआरए)	} 2	11,83,26,021.00	1,96,97,803.00
अचल परिसंपत्ति कोष (एफसीआरए)		1,14,634.00	2,52,597.00
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (गैर एफसीआरए)	} 3	1,62,92,667.14	68,00,325.14
प्रायोजित परियोजनाओं की अव्ययित राशि (एफसीआरए)		9,09,88,960.24	87,27,688.28
अव्ययित सहायता अनुदान विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त	4a	65,10,730.00	8,76,883.00
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (गैर एफसीआरए)	} 4	6,18,16,104.63	4,20,48,243.67
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (एफसीआरए)		72,52,196.00	12,23,949.00
कुल		**44,63,27,996.02**	**21,52,83,363.95**
परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (गैर एफसीआरए)	} 5	11,83,26,021.00	1,96,97,803.00
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (एफसीआरए)		5,15,930.00	6,53,893.00
निवेश (गैर एफसीआरए)	} 6	5,26,19,103.00	5,06,46,467.00
निवेश (एफसीआरए)		8,61,53,579.95	9,23,84,916.33
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (गैर एफसीआरए)	} 3	80,52,406.00	51,06,303.00
प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य राशि (एफसीआरए)		1,60,672.90	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (गैर एफसीआरए)	} 7	6,39,85,822.03	3,29,23,505.48
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि (एफसीआरए)		11,65,14,461.14	1,38,70,476.14
कुल		**44,63,27,996.02**	**21,52,83,363.95**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16

अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल
साझेदार
एम सं. 083899
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05/09/2022

ह./–
एच.के. मलिक
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं लेखा)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था)
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता राशि में

राशि रु. में

	अनुसूची #	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
vk;			
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान	4(ए)	11,90,65,528.00	10,98,70,364.00
कार्यक्रम से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए हस्तांतरित प्रायोजित परियोजना अनुदान (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	3	3,83,48,023.74	2,69,50,673.78
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर हस्तांतरित अधिशेष राशि (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		21,42,204.00	45,77,697.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय (गैर–एफसीआरए)		2,82,818.00	96,742.72
अर्जित ब्याजः			
• सावधि जमा पर (एफसीआरए)		47,87,984.00	57,63,307.00
• सावधि जमा पर (गैर–एफसीआरए)		23,94,767.00	26,64,439.00
• बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते (एफसीआरए) पर		5,25,445.00	3,45,966.00
• बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते (गैर एफसीआरए) पर		3,00,911.00	3,05,933.00
• कर्मचारियों को दिए ऋण पर (गैर–एफसीआरए)		92,396.00	1,166.00
• आयकर रिफंड पर (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		33,934.00	1,02,177.00
• अन्य विविध आय (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		-	100.00
प्रायोजित परियोजनाओं से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपरिव्ययों के लिए वसूली(गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		18,55,709.00	16,45,820.00
देय बट्टे खाते में डाला		1,432.00	1,146.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – बेची गई/बट्टे खाते में डाल दी गई संपत्तियों का डब्ल्यू.डी.वी. (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2	-	45,563.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कोष से हस्तांतरित राशि – भारत सरकार/प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिगृहीत परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)		50,30,180.00	47,65,546.00
d|y		**17,48,61,331.74**	**15,71,36,640.50**
O;;			
कार्यक्रम व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	8	3,83,48,023.74	2,69,50,673.78
स्थापना व्यय (गैर–एफसीआरए)	9	8,46,89,270.00	7,93,17,435.00
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (गैर–एफसीआरए)	10	3,73,52,160.73	3,00,17,521.64
प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय (एफसीआरए)	11	70,889.12	20,620.36
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	5	50,30,180.00	47,65,546.00
प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतरित की गई घाटा राशि (गैर–एफसीआरए और पूर्व अवधि व्यय	3	-	9,99,611.04
अनुसंधान और विकास कोष में हस्तांतरित अधिशेष		-	6,15,758.00
		93,70,808.15	1,44,49,474.68
d|y		**17,48,61,331.74**	**15,71,36,640.50**

खातों पर उल्लेखनीय लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों के एक अंतरंग हिस्से का निर्माण करते हैं

आज की तारीख तक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–	ह./–	ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल	एच.के. मलिक	प्रो. सचिन चतुर्वेदी
साझेदार	प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं लेखा)	महानिदेशक
एम सं. 083899		
स्थानः नई दिल्ली		
दिनांकः 05/09/2022		

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली
(1860 के सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी)

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रसीद और भुगतान

	çkfIr;k	31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ		31 ekpZ 2021 dks lekIr o"kZ	
,	çkjfHkd tek				
i)	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	36,056.00		50,816.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :				
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक	39,140.00		39,140.00	
	बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)	2,44,41,874.76		2,16,25,605.52	
	बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	73,54,784.14		2,12,74,113.28	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	9,23,84,916.33		8,80,50,977.33	
	सावधि जमा में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर एफसीआरए)	5,06,46,467.00		3,03,46,419.00	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	2,72,523.00		2,29,244.00	
	dqy ,		17,51,75,761.23		16,16,16,315.13
ch	çkIr vunku				
i)	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से	22,84,00,000.00		11,47,96,000.00	
ii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से (गैर–एफसीआरए)	2,29,33,746.80		2,59,45,338.00	
iii)	विभिन्न प्रायोजित परियोजनाओं से(एफसीआरए)	10,64,08,161.00		1,06,06,035.00	
	dqy ch		35,77,41,907.80		15,13,47,373.00
lh	vftZr C;kt				
i)	ऋण, अग्रिम आदि पर ब्याज, (गैर–एफसीआरए)	66,438.00		1,166.00	
ii)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(एफसीआरए)	5,25,445.00		3,45,966.00	
iii)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	24,40,337.00		21,46,146.00	
iv)	सावधि जमा खातों पर ब्याज(एफसीआरए)	70,20,375.00		47,44,566.00	
v)	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप पर ब्याज(गैर–एफसीआरए)	9,97,952.00		3,05,933.00	
vi)	आय कर रिफंड पर ब्याज	33,934.00		1,02,177.00	
			1,10,84,481.00		76,45,954.00
	dqy vxzuhr		54,40,02,150.03		32,06,09,642.13

	Hkxrku	31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ		31 ekpZ 2021 dks lekIr o"kZ	
,	O;;				
i)	स्थापना व्यय – अनुसूची – 12 (गैर – एफसीआरए)	8,63,32,839.00		7,72,88,720.00	
ii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 13 (गैर–एफसीआरए)	3,14,81,631.77		3,10,25,072.64	
iii)	प्रशासनिक और अन्य कार्यक्रम व्यय – अनुसूची – 14 (एफसीआरए)	44,053.12		18,534.36	
iv)	व्यय – प्रायोजित परियोजनाएं – अनुसूची – 15 (गैर–एफसीआरए और एफसीआरए)	2,96,71,075.74		3,41,56,969.78	
	dqy ,		14,75,29,599.63		14,24,89,296.78
ch	lifÙk] l;a= vkj midj.k dk fy, Hkxrku				
i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (गैर–एफसीआरए)	8,77,75,634.00		46,06,263.00	
ii)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (एफसीआरए)	35,046.00		1,86,240.00	
	dqy ch		8,78,10,680.00		47,92,503.00
lh	vfxze vkj tek				
i)	अग्रिम (गैर–एफसीआरए)	3,88,392.00		7,25,694.00	
ii)	अग्रिम (एफसीआरए)	1,74,510.00		6,000.00	
iii)	प्राप्य टीडीएस (गैर–एफसीआरए)	2,78,529.00		2,50,475.00	
iv)	प्राप्य टीडीएस (एफसीआरए)	5,45,980.00		4,71,562.00	
v)	गतावधि या पुराने चेक	3,31,128.00		-	
	dqy lh		17,18,539.00		14,53,731.00
Mh	vU;				
i)	लौटाए गए अनुदान	3,83,720.00		-	
ii)	एलआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को किया गया भुगतान	19,04,044.00		12,99,518.00	
iii)	आरआईएस भविष्य निधि में भुगतान की गई राशि	-		12,29,000.00	
iv)	मूर्त आस्तियों और विविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को वापस किया गया)	36,603.00			
	dqy Mh		23,24,367.00		25,28,518.00
	dqy vxzuhr		23,93,83,185.63		15,12,64,048.78

	çkfIr;k	31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ		31 ekpZ 2021 dks lekIr o"kZ	
	dqy vxzkuhr		54,40,02,150.03		32,06,09,642.13
Mh	vU; vk;				
i)	रॉयल्टी	1,17,649.72		93,329.88	
ii)	विविध आय	-	1,17,649.72	100.00	93,429.88
	dqy Mh	12,18,081.00		10,29,951.00	
bZ	vfxze vkj tek				
i)	ऋण/अग्रिम की वसूली (गैर –एफसीआरए)	21,677.00		99,712.00	
ii)	कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली (गैर–एफसीआरए)	44,011.00		2,90,778.00	
iii)	गतावधि या पुराने चेक (गैर–एफसीआरए)	-		32,03,562.00	
iv)	,लआईसी से प्राप्त राशि और कर्मचारियों को देय	-		-	
v)	अग्रिम में प्राप्त राशि (गैर–एफसीआरए)	1,59,798.00		-	
vi)				1,33,079.00	
vii)	ऋण/अग्रिम की वसूली (एफसीआरए) की ओर से प्राप्त राशि		14,43,567.00		47,57,082.00
	dqy bZ				
,Q	vU;				
i)	मूर्त आस्तियों का निपटान	-		1,100.00	
ii)	मूर्त आस्तियों और वविध मदों का निपटान (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को लौटाने योग्य)	26,243.00		36,603.00	
iii)	आय कर रिफंड	4,84,816.00	5,11,059.00	9,41,953.00	9,79,656.00
	dqy ,Q				
	dqy		54,60,74,425.75		32,64,39,810.01

	Hkqxrku	31 ekpZ 2022 dks lekIr o"kZ		31 ekpZ 2021 dks lekIr o"kZ	
	dqy vxzkuhr		23,93,83,185.63		15,12,64,048.78
bZ	vfre 'ks"k ¼Dyksftax cSysal½				
i)	हाथ में नकदी (गैर–एफसीआरए)	42,473.00		36,056.00	
ii)	बैंक में जमा राशि :	39,140.00		39,140.00	
	बचत खाते में– आंध्रा बैंक(गैर –एफसीआरए)	5,56,00,240.03		2,44,41,874.76	
	बचत खाते/ऑटो स्वीप में – बैंक ऑफ इंडिया (गैर – एफसीआरए)				
	बचत बैंक खाता/ऑटो स्वीप – बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	54,77,360.14		73,54,784.14	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (एफसीआरए)	8,61,53,579.95		9,23,84,916.33	
	सावधि जमा– बैंक ऑफ इंडिया (गैर –एफसीआरए)	5,26,19,103.00		5,06,46,467.00	
	बचत खाते में –भारतीय स्टेट बैंक (एफसीआरए)	10,65,20,308.00		-	
iii)	डाक टिकट– फ्रैंकिंग मशीन में बैलेंस (गैर – एफसीआरए)	2,39,036.00		2,72,523.00	
			30,66,91,240.12		17,51,75,761.23
	dqy bZ				
	dqy		54,60,74,425.75		32,64,39,810.01

खातों पर महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियां एवं नोट 16
अनुसूची 1 से 16 खातों का अत्यावश्यक भाग है
हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कृते जीएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टेड अकाउंटेंट्स
कंपनी की पंजीकरण संख्या 000257N/ N500339

ह./–
सीए सुनील अग्रलवाल
साझेदार
एम सं. 083899
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05/09/2022

ह./–
एच.के. मलिक
प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन एवं लेखा)

ह./–
प्रो. सचिन चतुर्वेदी
महानिदेशक

आरआईएस

विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त नीतिगत अनुसंधान संस्थान हैं जोकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर कार्य करता है। आरआईएस प्रभावशाली नीतिगत वार्ता को बढ़ावा देने एवं वैश्विक एवं क्षेत्रिय आर्थिक मामलों के संबंध में विकासशील देशों में क्षमता निर्माण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आरआईएस की कार्य योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दक्षिणीय सहयोग को बढ़ावा देना और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय बातचीत में विकासशील देशों के साथ समन्वय करना है। आरआईएस क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कई प्रयासों की अंतः सरकारी प्रक्रियाओं में कार्यरत है। आरआईएस अपने विचारकों के गहन कार्य के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों एवं विकास भागीदारी के पटल पर नीतिगत सुसंगतता को सुदृढ़ करता है।

आरआईएस एवं इसकी कार्ययोजना के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने क लिए कृपया इसकी वेबसाइटः wwww.ris.org.in देखें।

आरआईएस
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4—बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली—110 003, भारत । दूरभाषः 91—11—24682177—80
फैक्सः 91—11—24682173—74, ई—मेल: dgoffice@ris.org.
वेबसाइट: http://www.ris.org.in